



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-आई-10012020-215261
CG-MH-E-10012020-215261

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 499]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 499]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSH 9, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 20 दिसम्बर, 2019

सं. टीएएमपी/38/2019.—एसडब्ल्यूपीएल महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतत-द्वारा, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण मुरमुगांव पत्तन न्यास में वर्थ 5क और 6क के दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड के प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/38/2019-एसडब्ल्यूपीएल

साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड

आवेदक

कोरमः

- (i). टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवंबर 2019 के 29 वें दिन पारित)

यह मामला, मुरमुगांव पत्तन ट्रस्ट (एमओपीटी) में वर्थ 5क और 6क के लिए दरमानों के संशोधन के लिए साउथ वेस्ट पत्तन लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के 24 जुलाई 2019 के प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने अपने आदेश टीएएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवंबर, 2016 के द्वारा एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर प्रस्ताव और एसडब्ल्यूपीएल पर लागू तत्कालीन प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के आधार पर एसडब्ल्यूपीएल के एसओआर को संशोधित किया गया था। 17 नवंबर 2016 को स्वीकृत एसओआर को 30 नवंबर 2016 को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 433 पर अधिसूचित किया गया था। संशोधित दरमान, भारत के राजपत्र में एसओआर को अधिसूचित करने वाले आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू हुआ। उक्त आदेश में, इन गतिविधियों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपेक्षित 34% और 17% की प्रशुल्क वृद्धि की तुलना में इस प्राधिकरण ने कार्गो प्रहस्तन प्रभारों में 27.80% और वर्थ किराया प्रभार में 10% की वृद्धि की अनुमति दी थी। दरमान(नों) की वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई थी। इस प्राधिकरण द्वारा पारित एक स्पीकिंग आदेश भारत के राजपत्र में 06 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया गया था।

2.2. प्रशुल्क आदेश दिनांक 17 नवंबर 2016 के संदर्भ में, एमओपीटी ने उक्त प्रशुल्क आदेश दिनांक 17 नवंबर 2016 की समीक्षा करने के लिए एक आवेदन दायर किया। हालांकि, एमओपीटी ने अपना समीक्षा आवेदन वापस ले लिया था।

3.1. एसडब्ल्यूपीएल ने 08 अप्रैल, 2019 को अपने पत्र के तहत, प्रशुल्क की मौजूदा वैधता को 30 सितंबर 2019 तक या नए प्रशुल्क को अधिसूचित किए जाने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अनुरोध किया।

3.2. इस संबंध में, यह एसडब्ल्यूपीएल के संज्ञान में लाया गया कि हमने अपने 8 नवंबर, 2017 के पत्र के तहत, एसडब्ल्यूपीएल से 2016-17 के वास्तविकताओं और संशोधित प्रशुल्क अनुमानों को संशोधित करने और इससे संबंधित 2017-18 और 2018-19 वर्षों के आय और व्यय अनुमानों के आधार पर इस प्राधिकरण के निर्णय के अनुसरण में, आदेश सं. टीएएमपी/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवंबर 2016 के पैरा 13(vii) (क) के अनुसरण में अधिकतम 30 नवंबर 2017 तक एक प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया था। इसके बाद 5 मार्च 2018 को अनुस्मारक भेजा गया। अनुस्मारक के बावजूद एसडब्ल्यूपीएल ने कोई जवाब नहीं दिया। इस प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन करने और हमारे पत्र द्वारा एसडब्ल्यूपीएल को किए गए अनुरोध पर चुप रहने के बजाय, एसडब्ल्यूपीएल ने मौजूदा एसओआर की वैधता के विस्तार की मांग की। एसडब्ल्यूपीएल के पत्र दिनांक 08 अप्रैल 2019 पर कार्रवाई करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल को वर्ष 2018-19 के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने कोई उत्तर नहीं दिया।

4. इस वीच, पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं.पीआर-14149/20/2009- पीजी (भाग-IV) दिनांक 5 मार्च 2019 को सभी प्रमुख पत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी ऑपरेटरों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 जारी किए हैं और पूर्व में निर्धारित प्रशुल्क दिशानिर्देश, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 द्वारा इस पर दी गई शक्तियों का प्रयोग और इस प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से कार्य करने का निर्देश दिया। महापत्तन न्यास ट्रस्ट में संचालित बीओटी ऑपरेटरों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 और तक पूर्ववर्ती शासित प्रशुल्क दिशानिर्देश 7 मार्च 2019 को राजपत्र नं. 92 पर असाधारण (भाग IIII खंड 4) के राजपत्र में अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसके बाद, प्रशुल्क नीति, 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, महापत्तन न्यासों और पूर्ववर्ती प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के तहत संबंधित बीओटी संचालकों के साथ परामर्श के बाद प्रशुल्क नीति को संचालित करने के लिए कार्य दिशानिर्देशों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

5.1. इस पृष्ठभूमि में, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए प्रशुल्क नीति, 2019 के बाद 24 जुलाई 2019 को अपना प्रस्ताव दायर किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने निम्नलिखित उल्लेख किया है:

(i). एसडब्ल्यूपीएल ने प्रशुल्क और मेजर पोट्स के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दस्तावेजों और सहायक दस्तावेजों के अनुसार प्रशुल्क दिशानिर्देशों और कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशुल्क निर्धारण का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित प्रशुल्क की 01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक तीन साल तक वैध रहेंगे।

(ii). आगम/निर्गम:

एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान 11.75 एमएमटी, 10.61 एमएमटी और 5.25 एमएमटी का आगम/निर्गम प्रहस्तन कार्य किया है। औसत राजस्व मांग (एआरआर) पर विचार करने के लिए अगले प्रशुल्क चक्र के लिए आगम/निर्गम को पिछले तीन वर्षों के औसत के रूप में लिया गया है, अर्थात् 9.2 एमएमटी।

(iii) व्यय अनुमान:

(क) प्रचालन व्यय (मूल्यहास को छोड़कर):

प्रचालन व्यय को पिछले 3 वर्षों के वास्तविक खर्च के औसत के रूप में लिया गया है।

(ख) मूल्यहास:

प्रशुल्क प्रस्ताव के लिए, मूल्यहास की गणना आईजीएपी के अनुसार की गई थी और आईएनडीएस के अनुसार उचित समायोजन मूल्यहास-संगणन में किया गया है। विवरण फॉर्म -7 में दी गई है।

(ग) रॉयल्टी:

2019 के संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.2 के अनुसार, निजी ऑपरेटर द्वारा स्वामी पत्तन को, अनुज्ञेय लागत के रूप में देय रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी प्रशुल्क गणना के लिए सरकार द्वारा पोत परिवहन मंत्रालय के आदेश सं. पीआर-14149/6/2002-पीजी दिनांक 29 जुलाई 2003 के निर्णयानुसार अनुमति नहीं होगी। बीओटी के उन मामलों में जहां बोली प्रक्रिया को 29 जुलाई 2003 से पहले अंतिम रूप दिया गया था, रॉयल्टी/राजस्व को प्रशुल्क अभिकलन में लिया जाएगा वर्तम प्रशुल्क निर्धारण के लिए अगले उच्चतम बोलीदाता द्वारा उद्धृत राशि अधिकतम हो।

तदनुसार, 13.1% रॉयल्टी (निविदा के लिए दूसरी सबसे बड़ी बोली होने के नाते) को गणना के लिए स्वीकार्य खर्च माना जाता है।

(घ) लीज किराया:

यह एलए के प्रावधानों के आधार पर पेश किया गया है।

[एआरआर गणना में माना गया लीज किराया अंकेक्षित वार्षिक खातों में उल्लेखित वास्तविक पर आधारित है]

(iv) एआरआर :

एआरआर पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित अनुमान लगाए गए थे:

(क) विनिमय दर:

बर्थ भाड़ा से आय की गणना के लिए रु.70 / अमरीकी डालर की दर पर विचार गया है।

(ख) अचल सम्पत्ति:

सकल निश्चित आस्तियों पर विचार के लिए, आईजीएएपी के आधार पर निश्चित परिसंपत्तियों पर पहुंचने के लिए आईएनडीएएस पर आधारित अंकेक्षित वार्षिक खातों में सूचित किए गए निश्चित आस्तियों पर देय समायोजन किए गए थे।

(ग) कार्यशील पूँजी:

कार्यशील पूँजी की गणना के लिए निम्न पर विचार किया गया :

(i). **इन्वेंटरी:** वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इन्वेंटरी की खपत ₹.325.70 लाख थी। एआरआर गणना के लिए, 6 महीने की औसत खपत यानी ₹.162.85 लाख मानी जाती है।

(ii) **विविध देनदार:** एसडब्ल्यूपीएल ने लाइसेंस शुल्क और लीज किराया के रूप में पत्तन ट्रस्ट को अग्रिम के रूप में ₹.867.76 लाख का भुगतान किया। वार्षिक औसत यानी ₹.433.88 लाख एआरआर गणना के लिए विविध देनदार(संड्री डेटर्स) के रूप में शामिल है।

(iii) **नकदी:** एसडब्ल्यूपीएल टर्मिनलों का वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आधार पर वार्षिक व्यय ₹.13,244.44 लाख है। एआरआर पर विचार करने के लिए, एक महीने का खर्च यानी ₹.1103.70 लाख कार्यशील पूँजी के लिए नकद मांग के रूप में लिया जाता है।

(v) नियोजित पूँजी पर रिटर्न:

जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, नियोजित पूँजी पर 16% प्रत्यागम पर विचार किया गया है।

(vi) एआरआर में सूचकांकन :

इंडेक्स के साथ एआरआर निकालने के लिए, 3.45% लागू डब्ल्यूपीआई लिया गया है।

(vii) प्रस्तावित दरमान :

एआरआर की गणना के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क को 23% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एसओआर प्रस्तुत किए गए हैं।

5.2. एसडब्ल्यूपीएल ने, कार्यशील दिशानिर्देशों में निर्धारित फार्म-1 में प्रस्तावित दर पर एआरआर की विस्तृत गणना और फार्म-3 और अन्य में प्रस्तावित दर पर राजस्व आकलन प्रस्तुत किया है। फार्म-1 (एआरआर), फार्म-3 (रेवेन्यू एस्टिमेशन), फार्म-6 क (री-कंसीलिएशन स्टेटमेंट), फार्म-7 (एआरआर कम्प्यूटेशन में समायोजन के विवरण देते हुए आईजीएएपी के अनुसार फिक्स्ड एसेट स्टेटमेंट), कार्यशील चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई है।

(i). एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुमजित एआरआर अभिकलन की सारांश स्थिति नीचे दी गई है:

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 1 (2016-17)	वर्ष 2 (2017-18)	वर्ष 3 (2018-19)
(1).	कुल व्यय (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार)			
(i).	परिचालन व्यय (मूल्यहास सहित)	24,021.16	23,605.00	16,819.02
(ii).	वित्त और विविध व्यय (एमई)	239.73	279.60	21.84
	कुल व्यय 1 = (i) + (ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86

(2).	उन वस्तुओं के संबंध में समायोजन जहां आईएनडीएएस(लेखा परीक्षित खातों के अनुसार) और आईजीएएपी के अनुसार आंकड़ों में भिन्नता है			
(i).	मूल्यहास	(670.77)	(964.17)	(793.46)
(ii).	अन्य व्यय आइटम, यदि कोई हो, सूचीबद्ध होनी चाहिए	(217.50)	(0.02)	(0.75)
	समायोजन का कुल योग 2 = (i) + (ii)	(888.27)	(964.19)	(794.21)
(3).	समायोजन घटाऊँ:			
(i).	पत्तन के लिए वास्तविक रॉयलटी / राजस्व हिस्सा	(3,415.98)	3,554.06	(2,154.16)
(ii).	ऋण पर ब्याज	(239.73)	(279.60)	(21.84)
(iii).	बुरे और संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	-	-	-
(iv).	धीमी गति से चलती इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	-	-	-
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो	-	-	-
	कुल 3 = [3 (i) + 3 (ii) + 3 (iii) + 3 (iv) + 3 (v) + 3 (vi)]	(3,655.71)	(3,833.65)	(2,176.00)
(4).	जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2 के अनुसार स्वीकार्य रॉयलटी / राजस्व शेरार।	2,486.07	2,586.56	1,567.75
(5).	कुल समायोजन के बाद कुल व्यय ($5 = 1 + 2 + 3 + 4$)	22,202.98	21,673.32	15,438.40
(6).	क्रम सं. 5 का का औसत व्यय = [वर्ष 1 + वर्ष 2 + वर्ष 3] / 3			19,771.57
(7).	नियोजित पूँजी			
	(i). सकल अचल संपत्ति (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) वर्ष 3 के 31 मार्च या वर्ष 3 के 31 दिसंबर को वीओटी ऑपरेटर के द्वारा अपनायी गई (आईजीएएपी के अनुसार)		48,602.09	
	(ii) जोड़ें: वीओटी ऑपरेटर द्वारा वर्ष 3 के 31 मार्च को या 31 दिसंबर को प्रगति के रूप में वीओटी की प्रगतिरत् कार्यशील पूँजी (लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार)		172.75	
	(iii) जोड़ें: प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यशील पूँजी			
	(क) इन्वेंटरी		162.85	
	(ख) विविध देनदार		2,704.74	
	(सी) नकद		1,103.70	
	(घ) सम (क) + (ख) + (ग)		3,971.30	
	(iv) कुल कार्यशील पूँजी [(i) + (ii) + (iii)]		52,746.14	
(8).	क्रम.7 (iv) पर नियोजित पूँजी पर 16% प्रत्यागम।		8,439.38	
(9).	वर्ष 3 के 31 मार्च को या वर्ष 3 के 31 दिसंबर को यथालागू वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर) [(6) + (8)]		28,210.95	
(10).	वर्ष 4 के लिए एआरआर में लागू डब्ल्यूपीआई का @ 100% इंडेक्सेशन @ 3.45% लागू होता है और वर्ष 4 के लिए सूचकांकित एआरआर होगा (9) x 1.0345)		29,218.22	
(11).	सूचकांकित वार्षिक राजस्व मांग की अधिकतम सीमा स्तरीयता		29,218.22	
(12).	ऊपर क्रम नं. 11 में अनुमानित अधिकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमान(नों) में राजस्व अनुमान।		29,082.00	

(ii) एसडब्ल्यूपीएल ने, अनुमानित एआरआर को पूरा करने के लिए वर्ष भाड़े के प्रभार में और कार्गो प्रहस्तन प्रभार में 23% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है।

(iii) एसडब्ल्यूपीएल के पास फॉर्म 4 में मौजूदा प्रशुल्क के लिए राजस्व आकलन का विस्तृत परिकलन प्रस्तुत किया है और साथ ही वर्ष 1, वर्ष 2 और वर्ष 3 के दौरान बीओटी ऑपरेटर द्वारा प्रहस्तित वास्तविक आगम/निर्गम के औसत के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क है। उक्त प्रपत्र के अनुसार, प्रस्तावित प्रशुल्क पर अनुमानित कुल राजस्व रु. 29,082.00 लाख है।

6.1. परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, 24 जुलाई 2019 के एसडब्ल्यूपीएल प्रस्ताव की एक प्रति एमओपीटी और संबंधित उपयोगकर्ताओं/उपयोगकर्ता संगठनों को दिए गए हमारे पत्र दिनांक 1 अगस्त 2019 को भेज दी गई थीं।

6.2. जवाब में, गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) और हीरालाल एंड कंपनी ने 16 अगस्त 2019 के अपने पत्रों के माध्यम से अपनी टिप्पणियों को प्रस्तुत किया है, जो कि हमारे पत्र दिनांक 27 अगस्त 2019 को प्रतिक्रियात्मक सूचना के रूप में एसडब्ल्यूपीएल को भेज दी गयी थी। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने ई-मेल दिनांक 21 अगस्त 2019 में अपना उत्तर दिया है।

6.3. 23 सितंबर 2019 को जारी किए गए अपने ईमेल के एमओपीटी ने एसडब्ल्यूपीएल को संबोधित 23 सितंबर 2019 को लिखे गए पत्र की एक प्रति भेज दी है जिसमें एमओपीटी ने विषयगत प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है जिसे हमारे 24 सितंबर कम्ते पत्र द्वारा एसडब्ल्यूपीएल को भेज दिया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 02 सितंबर 2016 को एमओपीटी के दिनांक 23 सितंबर 2019 की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है।

7.1. इस मामले में 27 सितंबर 2019 को एमओपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने प्रस्ताव की एक संक्षिप्त पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी दी गई है। संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी, एसडब्ल्यूपीएल और संबंधित उपयोगकर्ता / उपयोगकर्ता संगठनों ने अपना-अपना पक्ष रखा है।

7.2. इसके बाद, एमओपीटी ने 10 अक्टूबर 2019 के अपने ईमेल के माध्यम से अतिरिक्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया है जो कि हमारे पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2019 के तहत को प्रतिक्रिया सूचना के रूप में एसडब्ल्यूपीएल को भेज दिए गए थे। हालांकि, एसडब्ल्यूपीएल ने जवाब नहीं दिया है।

7.3. संयुक्त सुनवाई में सहमति के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल को हमारे दिनांक 04 अक्टूबर 2019 के पत्र के तहत अनुरोध किया गया कि वह 09 अक्टूबर 2019 तक संयुक्त सुनवाई की कार्यवाही से उत्पन्न निम्नलिखित विंदुओं पर कार्रवाई करें:

- (i). संयुक्त सुनवाई में, एमओपीटी ने बताया कि एसडब्ल्यूपीएल के साथ पत्तन द्वारा दर्ज किए गए लाइसेंस एग्रीमेंट (एलए) के अनुसार, पत्तन कार्गो प्रहस्तन चार्ज से एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अर्जित सकल राजस्व पर 18% राजस्व हिस्सेदारी अर्जित करता है। एमओपीटी को एलए के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल के वर्थ किराया के राजस्व से राजस्व हिस्सा नहीं मिलता है। बंदरगाह ने एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया कि वह वर्थ किराया शुल्क में मामूली वृद्धि कार्गो संबंधी शुल्कों में और कार्यों में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित 23% वृद्धि के बजाय अधिक वृद्धि पर विचार करे। जैसा कि संयुक्त सुनवाई में सहमति व्यक्त की गई थी, एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया गया था कि वह इस मामले को देखे और टीएमपी और एमओपीटी को जवाब दे।
- (ii). एमओपीटी का यह भी कहना है कि एसडब्ल्यूपीएल ने थर्मल कोल और लौह अयस्क छर्रों के लिए कार्गो प्रहस्तन प्रभारों में रियायत का प्रस्ताव किया है जो विदेशी कार्गो के लिए प्रस्तावित दर का 60% है। ये दो कार्गो मदें सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार तटीय रियायत की हकदार नहीं हैं। एसडब्ल्यूपीएल के मौजूदा एसओआर में इन दो कार्गो वस्तुओं के लिए तटीय रियायत नहीं देते हैं जो तटीय रियायत के लिए पात्र नहीं हैं। एसडब्ल्यूपीएल, सरकार के तटीय रियायत नीति के अनुरूप होने के प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करे जिसका सभी प्रमुख पत्तन न्यासों और वहां पर कार्यशील बीओटी ऑपरेटरों द्वारा समान रूप से अनुपालन किया जाता है।

8. संयुक्त सुनवाई से उठने वाले एकशन पॉइंट्स के जवाब में, एसडब्ल्यूपीएल ने अपना संशोधित प्रस्ताव दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को अपने ई-मेल दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के तहत दर्ज किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने अपने संशोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

- (i). पोतों से संबंधित शुल्कों में 15% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है और कार्गो से संबंधित शुल्कों में 26% की वृद्धि का प्रस्ताव है, जबकि इसकी तुलना में वर्थ के किराए में और कार्गो से संबंधित शुल्क में 23% की व्यापक वृद्धि पहले प्रस्तावित थी।
- (ii) तटीय कोयला और कोक के लिए शुल्क विदेशी कार्गो के समान रखा गया है।
- (iii) प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार अब दंडात्मक ब्याज 15% प्रस्तावित है।
- (iv) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा फॉर्म-1 से फॉर्म-8 तक में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

9. संशोधित प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल को हमारे पत्र दिनांक 04 नवंबर 2019 के माध्यम से दिनांक 18 नवंबर, 2019 तक कुछ बिंदुओं पर जानकारी / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को रद्द करने का अनुरोध किया था। एसडब्ल्यूपीएल ने अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण पर अपने पत्र दिनांक 14 नवंबर 2019 और दिनांक 22 नवंबर 2019 एवं 22 नवंबर 2019 के तत्पाश्चात्यक ईमेलों के तहत अपना जवाब प्रस्तुत किया है। हमारे द्वारा मांगी गई अनौपचारिक जानकारी/स्पष्टीकरण और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत उत्तर का सारांश नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	प्राधिकरण द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण	एसडब्ल्यूपीएल के उत्तर
1.	<u>वार्षिक राजस्व मांग (फार्म सं.1):</u>	
(i).	<p>2019 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.3.2. के अनुसार, आईएनडीएएस और आईजीएएपी के तहत सूचित किए गए व्यय में भिन्नता है, तो एआरआर गणना में आईएनडीएएस को छोड़कर और आईजीएएपी के आंकड़ों पर विचार करके आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए। इस संबंध में, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा क्रम सं.2 पर प्रस्तुत फॉर्म नं. 6 क, में विचारित खातों में सूचित आईएनडीएएस के अनुसार व्यय लागत विवरण ग्रेच्युटी और सामान्य व्यय के लिए समायोजन को दर्शाया गया है। एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया जाता है कि वह आईएनडीएएस के अनुसार वार्षिक खातों में बताए गए आंकड़ों के साथ क्रांस संदर्भ देते हुए किए गए समायोजन की व्याख्या करे। इसके अलावा6-क के रूप में समेकित आईजीएएपी के आंकड़ों का आधार, स्पष्टीकरण के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए विस्तारपूर्वक बताएं।</p> <p>जब भी एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष-2016-17 के लिए ग्रेच्युटी के लिए समायोजन को, ऑडिट वार्षिक खातों में आईएनडीएएस वनाम आईजीएएपी के अनुसार के आंकड़ों के हवाले से दिखाया है, आईजीएएपी के अनुसार, वर्ष 2017-18 के और 2018-19 के आईएनडीएएस के अनुसार ऑडिट किए गए वार्षिक खातों में ग्रेच्युटी मद के लिए ऐसे किसी भी समायोजन पर विचार नहीं करने का कारण स्पष्ट किया जाए।</p>	<p>कंपनी, आईएनडीएएस के उल्लेखों के प्रावधान के तहत, अपनी तुलन पत्र में परिभाषित लाभ योजना के शुद्ध व्यायित्व को परिसंपत्ति और देयता के रूप में मानती है। शुद्ध परिभाषित लाभ/देयता/परिसंपत्तियों के पुनः माप के माध्यम से लाभ और नुकसान जो कि आईजीएएपी में लागू थे अन्य व्यापक आय से मेल खाते हैं।</p> <p>एसडब्ल्यूपीएल ने बाद में 22 नवंबर 2019 के ईमेल के माध्यम से स्पष्ट किया है कि आईएनडीएएस के तहत, कंपनी की सेवा लागत और शुद्ध लाभ देयता पर शुद्ध व्याज या रियायती दर का उपयोग करते हुए परिकलित परिसंपत्ति की अवधि के खर्च के छूट की वर्तमान और पिछली अवधियों से सहमत है और एक कर्मचारी लाभ लागत लागत के रूप में प्रभारित किया गया है। हालांकि, परिभाषित वास्तविक लाभ / हानियों, योजनावद्ध परिसंपत्तियों पर प्रत्यागम अधिकतम सीमा स्तर के प्रभाव में बदलाव को आईएनडीएएस के लेखा नियम के प्रावधान के तहत अन्य आय के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना आवश्यक है।</p> <p>हालांकि, पूर्ववर्ती परिदृश्य में, आईजीएएपी के तहत इसे एक कर्मचारी लाभ के रूप में माना गया था।</p>
(ii).	(क) कार्यशील पूंजी (मानदंडों के अनुसार) की गणना से संबंधित फॉर्म 3 में, एसडब्ल्यूपीएल ने क्रम सं. नंवर (क) पर रु.2,270.86 लाख की प्राप्ति	कार्यशील पूंजी की गणना के लिए, देनदारियां हटा दी गई हैं।

	<p>पर विचार किया है। यह 2019 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.6 में निर्धारित कार्यशील पूँजी मानदंडों और कार्य दिशानिर्देशों के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म 3 के अनुरूप नहीं पाया गया है। एसडब्ल्यूपीएल, प्रशुल्क दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक संशोधन करने के लिए।</p>	
	<p>(ब) प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2019 को संचालित करने के लिए कार्य दिशानिर्देशों के खंड 2.2 के साथ पठित 2019 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.6 के अनुसार, संविदात्मक दायित्वों से उठने वाले संविदात्मतक आपत्तियों को स्वामी पतन बंदरगाह को लीज किराया/लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान कार्यशील पूँजी की गणना, के लिए विविध देनदारियां माना जाएगा। एसडब्ल्यूपीएल को एलए के अनुच्छेद 7.3.5.2 में निर्धारित की गई भूमि का पट्टा किराए का भुगतान अग्रिम रूप से हर साल करना आवश्यक है। ऑडिट एनुअल अकाउंट्स में वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस फीस रु.656.89 लाख है। इसका 50% तत्संबंधी रु.328.45 लाख होती है जो पहले के प्रशुल्क संशोधन के बाद अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। जबकि, एसडब्ल्यूपीएल ने फॉर्म -3 में लाइसेंस शुल्क के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि के लिए रु.433.88 लाख की राशि पर विचार किया है। एसडब्ल्यूपीएल, इस मद में कार्यशील पूँजी की गणना में आवश्यक सुधार करे।</p>	<p>कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अग्रिम लाइसेंस शुल्क के लिए मई 2019 के महीने में पतन ट्रस्ट को रु.8,6776,187 के लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है। पिछले वर्ष कंपनी ने केवल रु.656.89 लाख का भुगतान किया था और इसलिए वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क पर 4.26% की स्वीकार्य वृद्धि को देखते हुए भी यह पतन के ट्रस्ट को भुगतान की गई वास्तविक राशि कम हो जाएगी। इसलिए, भुगतान की गई वास्तविक राशि का आधा रु.4,33,88,094 कार्यशील पूँजी के लिए स्वीकार किया जाता है।</p>
	<p>(ग) वर्किंग कैपिटल कम्प्यूटेशन में स्वीकार्य नकद व्यय को रु.1,103.70 लाख पर विचार किया गया है यानी एक महीने के परिचालन खर्चों के 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक खातों में मूल्यहास और वित लागत को छोड़कर। यह मानते हुए कि एआरआर की गणना में क्रमांक 2 के तहत कुछ समायोजन किए गए हैं, फार्म सं. 1 में क्रम सं. 5 के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए कुल व्यय के आधार पर आईजीएएपी के अनुसार और उसमें उल्लेखित मूल्यहास को छोड़ने के बाद, एक महीने के नकद खर्चों पर विचार करना होगा।</p>	<p>वार्षिक राजस्व मांग के आधार पर कुल परिचालन व्यय रु.19771.57 लाख है। रु.809.47 लाख की एआरआर गणना के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत मूल्यहास के समायोजन के बाद, वार्षिक प्रचालन व्यय रु.18,962.10 लाख है। कार्यशील पूँजी पर विचार करने के लिए, औसत एक महीने का खर्च यानी 1580.17 नकद शेष राशि के रूप में माना जाता है।</p>
(iii).	<p>प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के क्लॉज 2.5 के अनुसार नियोजित पूँजी में सकल स्थिर संपत्ति (संपत्ति, संयोजन और उपकरण) [आम तौर पर स्वीकृत भारतीय लेखा सिद्धांत (आईजीएएपी)] के अनुसार] के साथ साथ 31 मार्च/31 दिसंबर तक उल्लेखित प्रगतिरत कार्यपूँजी खातों और निर्धारित मानकों के अनुसार सूचित आंकड़े शामिल किए जाएंगे बीओटी संचालकों को समायोजन का विवरण देकर विधिवत प्रमाणित एक मेलापक विवरण प्रस्तुत करना होगा जो समायोजनों के विवरण देते हुए आईजीएएपी के तहत लागत/उपकरण लेखाकार के तहत लेखा परीक्षित लेखाओं और सकल अचल संपत्ति (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) के आंकड़ों सहित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट / कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा कार्यशील चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा पूँजी नियोजित विधिवत प्रमाणित होगा।</p> <p>एसडब्ल्यूपीएल, एक मेलापक विवरण प्रस्तुत करे जिसमें आईजीएएपी के तहत विधिवत प्रमाणित लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित स्थाई अचल संपत्तियों का वर्ष 2018-19 का लेखा-जोखा रु.48,602.09 लाख अर्थात वर्ष 2018-19 के लिए आईएनडीएएस के तहत कुल वार्षिक खातों में सूचित की गई सकल संपत्ति रु.46,790.08 लाख रूपये [यानी रु.194.73 लाख (मूर्त) + रु. 46,595.35 लाख (अमूर्त संपत्ति)]।</p>	<p>संयंत्र और उपकरणों के प्रमुख के तहत, अधिग्रहीत की गई पूँजीगत वस्तुओं के लिए भारत सरकार की ईपीसीजी योजना के तहत पोतीय अनलोडर्स का अधिग्रहण किया गया था। ड्यूटी सेव की गई राशि का मूल्य, रु.3008 लाख तक कुल संपत्ति के उचित मूल्य पर विचार करने के लिए आईएनडीएएस के प्रावधान के तहत अचल संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है, हालांकि उक्त ड्यूटी लाभ को आईजीएएपी के एएस 12 के तहत निर्धारित परिसंपत्ति की लागत के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। मेलापक विवरण अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।</p>

	यह कार्य विस्तृत परिकलन और स्पष्टीकरण के साथ पेश किया जा सकता है। यदि काम एक्सेल में पेश किया जा रहा है, तो उसी को समायोजन से समझने के लिए लिंकेज से लैस किया जा सकता है।	
(iv).	एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 3.45% की दर से अनुमानित 282,10.95 लाख के एआरआर को सूचकांकित किया है। वर्ष 2019-20 के लिए लागू 4.26% सूचकांक पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, एसडब्ल्यूपीएल सूचकांक को संशोधित करें हैं और संशोधित एआरआर पर परिकलित करें।	वित्तीय वर्ष 2019-20 के सूचकांक को 3.45 प्रतिशत के स्थानपर 4.26 प्रतिशत कर दिया के संशोधित कर दिया गया है और तदनुसार, प्रस्ताव में संशोधन किया गया है।
2.	<u>राजस्व अनुमान (फार्म-4):</u>	
(i).	एसडब्ल्यूपीएल ने दिनांक 17 अक्टूबर 2019 के ई-मेल के अंतर्गत 16 अक्टूबर 2019 के अपने पत्र के तहत संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। संशोधित प्रस्ताव में एसडब्ल्यूपीएल ने कार्गों और पोत संबंधी दोनों गतिविधियों के लिए अपने मूल प्रस्ताव में मांगी गई 23% वृद्धि की तुलना में पोत संबंधी आय में 15% वृद्धि और कार्गो-वाहक संबंधी आय में 26% की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने संशोधित एसओआर का भी प्रस्ताव किया है तथापि, यह देखनेमें आया है कि फॉर्म 4 में प्रस्तुत राजस्व अनुमान में, एसडब्ल्यूपीएल ने संशोधित प्रस्तावित दर पर विचार नहीं किया है। इसलिए, एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध है कि वह संशोधित एसओआर में प्रस्तावित दरों के आधार पर संशोधित फॉर्म - 4 प्रस्तुत करें।	फॉर्म 4 को संशोधित राजस्व अनुमान और संशोधित प्रशुल्क प्रस्ताव के अनुसार संशोधित किया गया है। इसके बाद, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने ईमेल दिनांक 22 नवंबर 2019 को संशोधित फार्म-4 प्रस्तुत किया, जिसमें कि बीओटी ऑपरेटर द्वारा व1, व2 और व3 के दौरान प्रहस्तित वास्तविक आगम/निर्गम के औसत के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व अनुमान का विस्तृत परिकलन देते हुए संशोधित फार्म 4 में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रपत्र के अनुसार, प्रस्तावित प्रशुल्क पर अनुमानित कुल राजस्व ₹.287.50 करोड़ है, जबकि संशोधित अनुमानित एआरआर ₹.291.35 करोड़ है।
(ii).	एसडब्ल्यूपीएल द्वारा राजस्व आकलन में पोत संबंधित प्रभारों की वर्तमान विनिमय दर 1यूएस \$ = ₹.69.00 के मुकाबले 1यूएस \$ = ₹. 70.99 मानी गयी है। एसडब्ल्यूपीएल प्रचलित विनिमय दर के आधार पर पोत संबंधी प्रशुल्कों के राजस्व अनुमान को संशोधित कर सकता है।	विनिमय दर 1यूएस \$ = भारतीय मुद्रा-₹. 69 को 1यूएस \$ = INR 71 के रूप में संशोधित किया गया है।
(iii).	एसडब्ल्यूपीएल ने, वाहिकाओं के लिए पानी की आपूर्ति के लिए एक नए प्रशुल्क मद का प्रस्ताव किया है जिसके राजस्व प्रभाव का, एसडब्ल्यूपीएल ने फॉर्म -4 में उल्लेख नहीं किया है। एसडब्ल्यूपीएल, संभावित राजस्व आकलन का भी फॉर्म -4 उल्लेख करे।	जलापूर्ति आय की परिकल्पना नहीं की गई है। उस को एसओआर से हटा दिया गया है।
(iv).	मौजूदा एसओआर में निर्धारित प्रशुल्क मद और संशोधित प्रशुल्क के साथ प्रस्तावित एसओआर में शामिल हैं; लेकिन निम्नलिखित प्रशुल्क मदों के लिए फॉर्म -4 में पत्तन द्वारा किसी भी राजस्व का आकलन नहीं लगाया गया है: (क) घाट भाड़ा वर्थ नंबर 5 क और 6 क पर: (i). विदेशी कार्गो: (क) लौह अयस्क छर्रों (ख) कोई अन्य थोक कार्गो	लौह अयस्क छर्रों और किसी भी अन्य थोक कार्गो से राजस्व का अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि पिछले वर्षों के अनुभव के अनुसार इन कार्गो की उम्मीद नहीं है। प्रस्ताव ने यह कहते हुए प्रशुल्क बढ़ा दिया गया है कि अगर ग्राहक इस टर्मिनल के माध्यम से इन कार्गो के प्रहस्तन की बात करते हैं तो यह लागू होगा। यदि इन कार्गो का प्रहस्तन किया जाएगा, तो क्षमता की कमी के कारण अन्य सामान जैसे चूना पत्थर या कोयले की मात्रा कम हो सकती है। इसलिए, इन कार्गो के कारण कुल राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

	<p>(ii) सभी तटीय कार्गों।</p> <p>(ख) वर्थ संख्या 5क पर सभी कार्गों प्रहस्तन प्रभार।</p> <p>(ग) वर्थ नंबर 6 ए में कार्गों प्रहस्तन चार्ज़:</p> <p>(i). (क) लौह अयस्क छर्रों (विदेशी कार्गों)</p> <p>(ख) कोई अन्य थोक कार्गों (विदेशी कार्गों)</p> <p>(ii). सभी तटीय प्रभार</p> <p>एसडब्ल्यूपीएल ने पुष्टि की कि वर्ष 2018-19 में उपरोक्त मदों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा कोई आगम निर्गम/सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं और वर्ष 2018-19 के दौरान कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया है। यदि वर्ष 2018-19 में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आगम/निर्गम कार्य नहीं किया गया था, तो एसडब्ल्यूपीएल उपरोक्त मदों के लिए राजस्व आकलन के लिए 2016-17 और / या 2017-18 के आगम निर्गम को आधार मान सकता है।</p>	
3.	<p><u>दरमान:</u></p> <p>(i). <u>सामान्य नियम और शर्तें:</u></p> <p>प्राधिकरण ने समय-समय पर एसडब्ल्यूपीएल सहित सभी प्रमुख पत्तन न्यासों और बीओटी ऑपरेटरों के लिए सामान्य अनुकरणीय आदेश पारित किए हैं और एसडब्ल्यूपीएल सहित सभी मेजर पत्तन न्यासों और बीओटी ऑपरेटरों के लिए दरमान(नों) में उपयुक्त नोटों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। हालाँकि, एसडब्ल्यूपीएल ने निम्नलिखित सामान्य अनुकरणीय आदेश के अनुरूप प्रस्तावित दरमान(नों) में उपयुक्त नोटों को शामिल नहीं किया है:</p> <p>(क). (i). संशोधन आदेश संख्या/53/2015-बीओसीपीटी दिनांक 10 जून 2016 को अनुकरणीय संख्या क्रम संख्या ५३ / 53/2015-बीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 से संवंधित, पोत संबंधित शुल्क (बीआरसी) के लिए पोत के वर्गीकरण के लिए निर्धारित प्रणाली से संबंधित प्रावधान और पोतों से संबंधित शुल्क और रियायती तटीय दर के मानदंड।</p> <p>(ii) संशोधन आदेश संख्या प्राधिकरण/53/2015-बीओसीपीटी दिनांक 25 सितंबर 2018 को अनुकरणीय की संख्या क्रम संख्या प्राधिकरण/53/2015-ओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015, जहाजों और कार्गों के लिए रियायती तटीय शुल्क के लिए निर्धारित प्रावधान से संबंधित है। अधिसूचना संख्या 38/2018 के अनुसार श्रीलंका या वांगलादेश के क्षेत्रीय जल के माध्यम से एक अन्य भारतीय बंदरगाह- सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 11 मई 2018 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।</p> <p>(ख). प्राधिकरण ने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) द्वारा सभी प्रमुख पत्तन न्यासों और बीओटी ऑपरेटरों के दरमानों में दो वर्ष के लिए, प्रदेश लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक सेवा के लिए कंटेनरों पर अनिवार्य उपयोगकर्ता शुल्क (एमयूसी) के लिए प्रावधान को शामिल करते हुए सभी प्रमुख पत्तन न्यासों के लिए अनुकरणीय सामान्य आदेश के रूप में 24 जुलाई 2019 को आदेश संख्या</p>	<p>पोत संबंधी प्रभार (बीआरसी) लगाने के लिए पोतों का वर्गीकरण प्रणाली और रियायती तटीय दर पर पोत संबंधी प्रभार लगाने के लिए मानदंड और विदेशी दर से संबंधित 26 नवंबर, 2015 के संशोधन आदेश संख्या प्राधिकरण/53/2015-बीओसीपीटी के अनुसार, प्रावधानों को संशोधित एसओआर में शामिल कर लिया गया है।</p> <p>आदेश सं. प्राधिकरण/12/2019-एमयूसी के अनुसार उपयोगकर्ता अनिवार्य शुल्क (एमयूसी) का प्रावधान, विशेष रूप से कंटेनरों के लिए है। साउथ वेस्ट पत्तन किसी भी कंटेनर कार्गो का प्रहस्तन नहीं कर रहा है, इसलिए यह लागू नहीं है।</p>

	<p>प्राधिकरण/12/2019-एमयूसी पारित किया था और यह एसडब्ल्यूपीएल के मामले सहित सभी महापत्तन न्यासों और बीओटी टर्मिनलों पर भी लागू होंगा।</p> <p>एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध है कि सामान्य आदेशों में निर्धारित इन प्रावधानों को एसओआर में शामिल किया जाए।</p>	
(ii).	<p>सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार, तापीय कोयला, लौह अयस्क छर्रे और क्रूड ऑयल सहित पीओएल तटीय रियायत के हकदार नहीं हैं।</p> <p>(क) तदनुसार, मौजूदा एसओआर में घाट-भाड़ा शुल्क(प्रभार) और कार्गो प्रहस्तन शुल्क के तहत लौह अयस्क छर्रे के लिए कोई तटीय रियायत निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, प्रस्तावित एसओआर में एसडब्ल्यूपीएल ने तटीय लौह अयस्क छर्रे के लिए रियायती दर प्रस्तावित की है जो सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुरूप नहीं है। एसडब्ल्यूपीएल, इस श्रेणी के तहत प्रहस्तन का अनुमान, यदि कोई हो, तो प्रस्तावित एसओआर और राजस्व अनुमान में, आवश्यक सुधार करें।</p> <p>(ख). मौजूदा एसओआर में, घाट शुल्क और कार्गो प्रहस्तन शुल्क में खंड के और ख के तहत निर्धारित क्रमशः " थर्मल कोयला को छोड़कर कोयला" नाम दिए गए हैं। तदनुसार, सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार, इस नामकरण के तहत तटीय कार्गो के लिए प्रशुल्क में रियायत निर्धारित है। तथापि, प्रस्तावित एसओआर में एसडब्ल्यूपीएल ने 'सभी प्रकार का कोयला' के रूप में नामकरण को आशोधित किया है। ऐसा करते समय, एसडब्ल्यूपीएल ने तटीय कोयला कार्गो के लिए रियायती शुल्क का प्रस्ताव नहीं किया है। चूंकि तापीय कोयला सरकार की तटीय रियायत नीति और प्रशुल्क आदेश नंबर प्राधिकरण/4/2004-सामान्य दिनांक 15 मार्च 2005 के अनुसार तटीय रियायत का हकदार नहीं है, एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया जाता है कि प्रस्तावित एसओआर में आवश्यक सुधार करे ताकि सभी प्रकारों के कोयले के लिए तटीय रियायत दी जा सके, जिसमें तापीय कोयला के लिए सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुरूप रियायती शुल्क के बिना पृथक प्रविष्टि की जाए ताकि परिणामतः, राजस्व अनुमानों में भी आवश्यक सुधार किया जाए।</p>	<p>थर्मल और गैर-थर्मल दोनों कोयले के राजस्व अनुमान के लिए, कंपनी ने पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर केवल विदेशी जहाजों पर विचार किया। यद्यपि, संशोधित एसओआर में, थर्मल कोयले के अलावा कोयले को ले जाने वाले तटीय जहाजों के लिए रियायत का प्रस्ताव, प्रशुल्क नीति के अनुसार किया गया है, राजस्व अनुमानों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी कोयले, विदेशी जहाजों के लिए माने गए हैं।</p> <p>[संशोधित प्रस्तावित दरमान(नों) में, एसडब्ल्यूपीएल ने थर्मल कोल के लिए तटीय रियायत का प्रस्ताव नहीं किया है। हालांकि, लौह अयस्क छर्रे के लिए, एसडब्ल्यूपीएल ने तटीय रियायत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुरूप नहीं है।]</p>
(iii).	<p>कार्यकारी दिशानिर्देश, 2019 के खंड 8.2.3 में कहा गया है कि घाट-भाड़ा अनुसूची के तहत किसी भी कार्गो को "अनिर्दिष्ट" श्रेणी में वर्गीकृत करने से पहले, प्रासंगिक सीमा-शुल्क वर्गीकरण का यह पता लगाने के लिए संदर्भित लिया/किया जाना चाहिए कि कार्गो को घाट अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।। एसडब्ल्यूपीएल के मूल प्रस्ताव पर टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए एसओपीटी ने उक्त खंड को शामिल करने का अनुरोध किया है। इसलिए, एसडब्ल्यूपीएल को प्रस्तावित एसओआर में शामिल करने का अनुरोध किया जाता है।</p>	अनिर्दिष्ट कार्गो के लिए संशोधित प्रावधान एसओआर में शामिल किए गए।
(iv).	एसडब्ल्यूपीएल ने विविध सेवाओं को पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क एक	जल शुल्क के लिए प्रशुल्क हटा दिया गया है।

	<p>नया प्रशुल्क मद अर्थात् विदेशगामी जहाजों के लिए यूएस \$ 3.3069 प्रति 1000 लीटर की दर से जहाजों और और तटीय जहाजों के लिए प्रति 1000 लीटर पर रु.88.55 पर शामिल करने का प्रस्ताव किया है,। एसडब्ल्यूपीएल प्रस्तावित दर के लिए आधार प्रस्तुत करे और विदेशी जहाजों को पानी की आपूर्ति के लिए डॉलर के मूल्य को निर्धारित करे।</p>																																									
4.	<p><u>पिछली अवधि का अधिशेष :</u></p> <p>प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 3.1.2, यह निर्धारित करता है कि जिन ऑपरेटरों ने न्यायालयों से संपर्क नहीं किया है, उनके मामले में, इस दिशानिर्देश के तहत पहली प्रशुल्क निर्धारण की अवधि तक का अधिशेष/धारा, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के खंड अनुसार 2.13 के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे" जैसा कि नीचे पृष्ठ पर: प्रस्तुत किया गया है:</p> <p>"वास्तविक और वित्तीय निष्पादनों की, निर्धारित वैधता अवधि के दौरा मौजूदा प्रतिलिपि प्रशुल्क निर्धारण के समय पर आधारित निष्पादनों के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी यदि उल्लेखित निष्पादन में विचलन की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक या कम होती है तो प्रशुल्क को उसी प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। ऐसा करने समय लाभ हानि का 50 प्रतिशत प्रशुल्क में संशोधन के समय सेट-ऑफ कर दिया जाएगा।"</p> <p>इसलिए, एसडब्ल्यूपीएल से वास्तविक, वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने वाले विवरण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है, जो पिछले प्रशुल्क चक्र में दिए गए अनुमानों पर निर्भर है, जैसा कि पूर्ववर्ती प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के तहत पहले प्रशुल्क संशोधन में किया गया था और यदि द्वारा वास्तविक और वित्तीय दोनों मापदंडों में +/- 20% भिन्नता है तो मामले में अनुमानित एआरआर से आवश्यक संशोधन करे।</p>	<p>एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए पिछली अवधि के अधिशेष का संशोधित विवरण प्रस्तुत किया है।</p> <p>एक सारांश स्थिति नीचे दी गई है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विवरण</th> <th>अनुमान 15.01.2016 के प्रशुल्क आदेश के आधार पर</th> <th>वास्तविक</th> <th>विचलन %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आगम/निर्गम (एमएमटीपीए में)</td> <td>22.50</td> <td>27.64</td> <td>22.84%</td> </tr> <tr> <td>कुल परिचालन आय</td> <td>73,507.32</td> <td>74,378.95</td> <td>1.19%</td> </tr> <tr> <td>परिचालन लागत (मूल्यहास को छोड़कर)</td> <td>36,578.46</td> <td>44,683.01</td> <td>22.16%</td> </tr> <tr> <td>मूल्यहास</td> <td>7,358.75</td> <td>8,115.00</td> <td>10.28%</td> </tr> <tr> <td>ओवरहेइम</td> <td>5,633.08</td> <td>6,846.77</td> <td></td> </tr> <tr> <td>एफएमआई कम एफएमआई</td> <td>272.00</td> <td>278.64</td> <td>2.44%</td> </tr> <tr> <td>नियोजित पूंजी</td> <td>95,066.35</td> <td>87,139.26</td> <td>-8.34%</td> </tr> <tr> <td>धनता उपयोग के लिए समायोजित आरओसीई</td> <td>15,210.62</td> <td>13,942.28</td> <td>-8.34%</td> </tr> <tr> <td>शुद्ध अधिशेष / (धारा)</td> <td>8,998.41</td> <td>1,070.53</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	विवरण	अनुमान 15.01.2016 के प्रशुल्क आदेश के आधार पर	वास्तविक	विचलन %	आगम/निर्गम (एमएमटीपीए में)	22.50	27.64	22.84%	कुल परिचालन आय	73,507.32	74,378.95	1.19%	परिचालन लागत (मूल्यहास को छोड़कर)	36,578.46	44,683.01	22.16%	मूल्यहास	7,358.75	8,115.00	10.28%	ओवरहेइम	5,633.08	6,846.77		एफएमआई कम एफएमआई	272.00	278.64	2.44%	नियोजित पूंजी	95,066.35	87,139.26	-8.34%	धनता उपयोग के लिए समायोजित आरओसीई	15,210.62	13,942.28	-8.34%	शुद्ध अधिशेष / (धारा)	8,998.41	1,070.53	
विवरण	अनुमान 15.01.2016 के प्रशुल्क आदेश के आधार पर	वास्तविक	विचलन %																																							
आगम/निर्गम (एमएमटीपीए में)	22.50	27.64	22.84%																																							
कुल परिचालन आय	73,507.32	74,378.95	1.19%																																							
परिचालन लागत (मूल्यहास को छोड़कर)	36,578.46	44,683.01	22.16%																																							
मूल्यहास	7,358.75	8,115.00	10.28%																																							
ओवरहेइम	5,633.08	6,846.77																																								
एफएमआई कम एफएमआई	272.00	278.64	2.44%																																							
नियोजित पूंजी	95,066.35	87,139.26	-8.34%																																							
धनता उपयोग के लिए समायोजित आरओसीई	15,210.62	13,942.28	-8.34%																																							
शुद्ध अधिशेष / (धारा)	8,998.41	1,070.53																																								
	<p>इसके बाद, एसडब्ल्यूपीएल ने 22 नवंबर 2019 के अपने ईमेल के तहत, जिसमें अन्य आय, विदेशी मुद्रा लाभ/हानि, एसईआईएस (भारत योजना से सेवा निर्यात) आय, ईपीसीजी (कैपिटल गुड्स का निर्यात प्रोत्साहन) और विविध आय के संबंध में वर्गीकरण स्पष्ट किया है, वह इस प्रकार है:</p> <p>(i) विदेशी मुद्रा लाभ/हानि: यह राशि शिप-अनलोडर्स के लिए, लिए गए खरीदारों के क्रेडिट पर उल्लेखनीय लाभ को देखते हुए लाभ और हानि विवरण में परिलक्षित की गई है।</p> <p>(ii). एसईआईएस आय (सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया</p>																																									

		<p>स्कीम): यह आय सेवा के निर्यात से प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त होती है।</p> <p>(iii). ईपीसीजी(कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट प्रमोशन): इस योजना के तहत कस्टम ड्यूटी बचाने पर लाभ मिलता है। वर्तमान में आईएनडीएएस लेखांकन के तहत, इस कस्टम ड्यूटी लाभ को पूंजीगत लागत में जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए यह परिसंपत्तियों के परिशोधन में भी परिलक्षित की गई है।</p> <p>(iv). विविध आय : यह आय अस्थायी कार्य और अन्य कैपेक्स प्रयोजनों के लिए बाहरी ग्राहकों या उप-संचालकों के साथ साझा किए गए उपकरणों से उत्पन्न एक बारगी गैर-परिचालकीय प्रकृति की होती है।</p>
--	--	---

10.1. अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, एसडब्ल्यूपीएल ने अपने पत्र दिनांक 14 नवंबर 2019 और उसके बाद दिनांक 22 नवंबर 2019 के ईमेल में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें संशोधित प्रारूप -1 (एआरआर), फॉर्म -3 (कार्यशील पूंजी), फॉर्म -4 (राजस्व अनुमान), फॉर्म -6 ए (मेलापक विवरणी) और पिछली अवधि शामिल है।

(i) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एआरआर अभिकलन का सारांश नीचे दिया गया है:

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 1 (2016-17)	वर्ष 2 (2017-18)	वर्ष 3 (2018-19)
(1).	कुल व्यय			
(i).	प्रचालन व्यय(मूल्य हास सहित)	24,021.16	23,605.00	16,819.02
(ii).	वित्त और विविध व्यय(एमएमई)	239.73	279.60	21.84
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86
(2).	आईजीएपी और आईएनडीएएस के अनुसार सूचित आंकड़ों में मर्दों के बारे में जहां कहीं विचलन है, समायोजन घटाएं			
(i).	मूल्य हास	(670.77)	(964.17)	(793.46)
(ii).	अन्य व्यय मर्दों, यदि कोई हों, सूचीबद्ध करें	(217.50)	(8.69)	(18.20)
	2 - समायोजनों का योग=(i)+(ii)	(888.27)	(972.86)	(811.66)
(3).	घटाएं समायोजन :			
(i).	पत्तन को अदा की गयी वास्तविक रायल्टी / राजस्व भाग	(3,415.98)	(3,554.06)	(2,154.16)
(ii).	ऋणों पर ब्याज	(239.73)	(279.60)	(21.84)
(iii).	अशोध्य और संदेहजनक ऋणों के प्रावधान	-	-	-
(iv).	धीर्मी गति वाली इनवेंट्री के प्रावधान	-	-	-
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हों	-	-	-
	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	(3,655.71)	(3,833.65)	(2,176.00)
(4).	जोड़ें : प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार अनुदेय रॉयल्टी/राजस्व भाग	2,486.07	2,586.56	1,567.75
(5).	कुल समायोजनों के पश्चात व्यय (5=1+2+3+4)	22,202.98	21,664.65	15,420.95
(6).	क्रम. सं. 5 का ओसत व्यय = [वर्ष 1+वर्ष 2+वर्ष 3]/3			19,762.86
(7).	नियोजित पूंजी			

	(i).कुल स्थायी परिसंपत्तियां(संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) 31 मार्च के अनुसार बीओटी ऑपरेटर द्वारा अनुकरणीयआईजीएपी के अनुसार)	48,602.09
	(ii) जोड़ें: बीओटी ऑपरेटर द्वारा 31 मार्च को Y3 या 31 दिसंबर को प्रगति के रूप में प्रगति में पूंजीगत कार्य (लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार)	172.75
	(iii) जोड़ें: टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यशील पूंजी	
	(क) इनवेटरी	162.85
	(ख) विविध देनदार	433.88
	(ग) नकद	1,579.45
	(क) + (ख) + (ग) का जोड़	2,176.18
	(iv). नियोजित पूंजी का जोड़ (i)+(ii)+(iii)]	50,951.02
(8).	क्रम सं. .7 (iv) पर नियोजित पूंजी 16% पर प्रत्यागम	8,152.16
(9).	वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर) 31 मार्च को व3 के रूप में या लागू [[6) + (8)]	27,915.02
(10).	एआरआर: 100% की दर से लागू डब्ल्यूपीआई इंडेक्सेशन, 1.426% और पिछली अवधी के रू.30.51 लाख के अधिक्षेष के समायोजन के पश्चात	29,134.72
(11).	अधिकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित वार्षिक राजस्व मांग	29,134.72
(12).	ऊपर क्रम सं.11 में अनुमानित अधिकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित अधिसूचित दरमानों में राजस्व अनुमान।	28,750.00

(ii). अंतिम संशोधित प्रस्ताव में एसडब्ल्यूपीएल ने निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव दिया है:

- (क) अनुमानित एआरआर को पूरा करने के लिए वर्थ भाड़ा शुल्क में 15% और कार्गो से संबंधित शुल्क 26% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
[प्रस्तावित दर पर, कार्गो संबंधित शुल्कों में वृद्धि 20% से 26.67% तक काम करती है और एसडब्ल्यूपीएल द्वारा बताई गई 26% की समान वृद्धि नहीं होती है।]
- (ख). एसडब्ल्यूपीएल ने संशोधित फॉर्म 4 में सुसज्जित किया है, जो कि बी 1 ओ, वाई 2 और वाई 3 के दौरान बीओटी ऑपरेटर द्वारा संभाले गए वास्तविक आगम/निर्गम के औसत के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व आकलन का विस्तृत कार्य करता है। उक्त प्रपत्र के अनुसार, संशोधित अनुमानित एआरआर रु .291.35 करोड़ है।
- (ग). इसके अलावा, एसडब्ल्यूपीएल फॉर्म -1 (एआरआर), फॉर्म -3 (राजस्व आकलन), फॉर्म -6क (मेलापक विवरणी), फॉर्म -7 (समायोजनों का विवरण देते हुए एआरआर कम्प्यूटेशन में विचारित आईजीएपी के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति विवरण)की कार्यशील चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित प्रतियों को, जितना संभव/जल्दी हो सके भेजने के लिए सहमत हो गया है।

10.2. इसके बाद, एसडब्ल्यूपीएल ने 22 नवंबर 2019 के ईमेल द्वारा अंतिम संशोधित लागत विवरणों के संदर्भ में कार्यशील चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अपने ईमेल दिनांक 25 नवंबर 2019 को, फॉर्म -1 (एआरआर), फॉर्म -3 (राजस्व अनुमान), फॉर्म-6क (मेलापक विवरणी), एआरआर गणना में विचारित आईजीएपी के अनुसार फॉर्म -7 (स्थायी परिसंपत्ति विवरण) प्रस्तुत कर दिए हैं।

11. इस मामले में परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं। संबंधित पक्षों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों और तर्कों का एक अंश संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

12. इस मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, निम्न स्थिति उजागर होती है:

- (i). 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, साऊथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) के एसओआर पिछली बार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. प्राधिकरण/40/2016 दिनांक 17 नवंबर 2016 को संशोधित किये गये थे जिसमें लागत जमा प्राईसिंग कॉडल को अपनाया गया था। यह वैधता 31 मार्च 2019 तक निर्धारित की गई थी।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपने एसओआर के संशोधन के लिए दायर वर्तमान प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई से पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नवंबर 2016 के उक्त प्रशुल्क आदेश में निर्धारित किया गया था कि एसडब्ल्यूपीएल को आगम/निर्गम के मामले में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निर्भरता योग्य प्रस्तुत एवं विचारित प्रहस्तित अनुमानित आगम/निर्गम की तुलना में यदि वास्तविक आगम/निर्गम काफी भिन्न होता है तो वास्तविक प्रस्ताव फाइल करने के लिए शेड्यूल समीक्षा से पहले और एसओपीटी द्वारा दिए गए आदेश 13(vii) (आदेश सं. प्राधिकरण/40/2016-एसडब्ल्यूपीएल दिनांक 17 नवंबर 2016 में दिए गए कारणों के लिए पुष्टि करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल को बुलाया जा सकता है। वर्तमान प्रस्ताव में एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 11.75 एमएमटी, 10.61 एमएमटी और 5.25 एमएमटी का आगम/निर्गम का प्रहस्तन कार्य किया है।

इस संबंध में यह बताना प्रासंगिक है कि जब एमओपीटी का वर्ष 2016-17 में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रहस्तित वास्तविक आगम -निर्गम 11.75 एमटीपीए था, उस समय, एसडब्ल्यूपीएल ने 8 नवंबर 2017 के हमारे पत्र के माध्यम से का अनुरोध किया गया था कि वह 2016-17 के वास्तविक आधार पर एक प्रस्ताव दर्ज करें और वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रशुल्क अनुमानों और इसी आय और व्यय के अनुमानों को संशोधित करें और पैरा में इस प्राधिकरण के 17 नवंबर 2016 के आदेश की 13 (vii) (क) के निर्णय के अनुसरण में अधिकतम 30 नवंबर 2017 तक प्रस्ताव प्रस्तुत करें। इसके बाद 5 मार्च 2018 को अनुस्मारक भेजा गया। एसडब्ल्यूपीएल, ने उस समय चुप रहना बेहतर समझा था और स्मरण-पत्र के बावजूद और लाइसेंसर पत्तन द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी ओर, एसडब्ल्यूपीएल ने, 08 अप्रैल 2019 के अपने पत्र के अंतर्गत इस प्राधिकरण से मौजूदा प्रशुल्क की वैधता को 30 सितंबर 2019 तक या नए प्रशुल्क को अधिसूचित किए जाने तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। एसडब्ल्यूपीएल की ओर से गैर-कार्रवाई की उपरोक्त स्थिति एसडब्ल्यूपीएल के नोटिस में दिनांक 14 मई, 2019 के हमारे पत्र के माध्यम से लाई गई, जिसमें एसडब्ल्यूपीएल को वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक निष्पादन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। यह तब था, जब एसडब्ल्यूपीएल ने जुलाई 2019 में नए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के तहत अपने एसओआर के संशोधन के लिए वर्तमान प्रस्ताव दायर किया है।

- (iii). पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के तहत एक नीति निर्देश के रूप में, बीओटी ऑफरेटरों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 जारी किये हैं जो पहले 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित थे। एमओएस द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के जारी होने के परिणामस्वरूप, एसडब्ल्यूपीएल के संबंध में प्रशुल्क निर्धारण कार्रवाई, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 में निहित शर्तों और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के तहत करने के लिए जारी किए गए कार्य दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित की जानी है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपने एसओआर के सामान्य संशोधन के लिए 24 जुलाई 2019 का प्रस्तुत वर्तमान प्रस्ताव, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 और प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2019 के तहत संचालित कार्य दिशानिर्देशों के तहत अभिशासित करने के लिए है। एसडब्ल्यूपीएल ने हमारे द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी / स्पष्टीकरण को अपने पत्र दिनांक 14 नवंबर 2019 और बाद में दिनांक 22 नवंबर 2019 को ईमेल किया गये संशोधित वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर), मसौदा दरमान(नों) और संशोधित राजस्व अनुमान द्वारा पुष्ट किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा दायर अंतिम संशोधित प्रस्ताव 14 नवंबर 2019 के अपने पत्र और 22 नवंबर 2019 के बाद के ईमेल के साथ-साथ एसडब्ल्यूपीएल द्वारा किए गए सबमिशन और मामले के प्रसंस्करण के दौरान पत्तन के विश्लेषण पर इस विश्लेषण में विचार किया गया है।

- (iv). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2019 के खंड 2.1 में, एआरआर का आकलन करने के लिए प्रत्येक बीओटी ऑपरेटर से 31 मार्च को 3 वर्ष के, तुरत-पूर्ववर्ती तीन वर्षों (वर्ष 1), (वर्ष 2) और (वर्ष 3) के अंतिम लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार वास्तविक व्यय का औसत होता है, के आकलन की अपेक्षा की जाती है, जो कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 और इस प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कार्य दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ विशेष बहिष्करणों के अधीन और पूँजीगत लाभ पर 16% से अधिक प्रत्यागम के साथ कार्यात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत चार्टर्ड एकाउंटेंट/लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित हों।
- (ख). एसडब्ल्यूपीएल ने एआरआर का आकलन करते समय, तीन वर्षों अर्थात् यानी लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा-जोखा पर आधारित एवं विधिवत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2016-17 (वर्ष- 1), 2017-18 (वर्ष-2) और 2018-19 (वर्ष-3) के लिए एआरआर संगणना में अस्वीकार्य खर्चों का बहिष्करण किया है, जैसा कि प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में निर्धारित है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप किए गए निम्नलिखित समायोजन, 2019 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में, और कार्य दिशानिर्देशों का विशिष्ट उल्लेख किया गया है:
- (i). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019, के साथ-साथ के खंड 2.2 में कहा गया है कि बीओटी ऑपरेटर द्वारा स्वामी पत्तन को देय रॉयल्टी/रिवेन्यू शेयर के उन मामलों में जहां 29 जुलाई 2003 से पहले बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था, एआरआर अभिकलन के समय प्रशुल्क परिकलन में अगले उच्चतम बोलीदाता को ध्यान में रखा जाएगा।
- तदनुसार, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान क्रमशः रु.34.16 करोड़, रु.35.54 करोड़ और रु.21.54 करोड़ के ऑंडिट किए गए वार्षिक खातों में परिलक्षित राजस्व हिस्सेदारी को बाहर रखा गया है। चूंकि एसडब्ल्यूपीएल के संबंध में बोली प्रक्रिया को 29 जुलाई 2003 से पहले अंतिम रूप दे दिया गया था, इसलिए अगले उच्चतम बोलीदाता की सीमा तक राजस्व हिस्सेदारी यानी 13.1% को एआरआर की गणना में माना गया है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान क्रमशः रु.24.86 करोड़ रु.25.86 करोड़ और रु.15.67 करोड़ पर एआरआर परिकलन में विचार किया गया। ये प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.2 के अनुरूप हैं।
- (ii). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के क्लॉज 2.3.1 (ii) के अनुसार, ऋणों पर ब्याज, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, धीमी गति से चल रही इन्वेंट्री के लिए प्रावधान आदि को

बाहर रखा जाना है। तदनुसार, एसडब्ल्यूपीएल ने ऋण पर ब्याज के रूप 2016-17 से 2018-19 के दौरान क्रमशः रु.239.73 लाख, रु.279.60 लाख और रु.21.84 लाख को शामिल नहीं किया है। अपवर्जन के लिए अन्य वस्तुओं को शून्य माना जाता है।

- (iii). खण्ड 2.3.2 यह निर्धारित है कि अगर आईएनडीएएस और आईजीएएपी (मूल्यहास की तरह) के तहत सूचित किए गए व्यय में भिन्नता है, तो आईएनडीएएस के आंकड़ों को छोड़कर और आईजीएएपी के अनुसार आंकड़ों पर विचार करके एआरआर अधिकलन में आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए। एसडब्ल्यूपीएल के ऑफिट किए गए खाते आईएनडीएएस के अनुपालन में हैं। एसडब्ल्यूपीएल ने दिशानिर्देश मद की स्थिति का अनुपालन करने के लिए आईजीएएपी के अनुसार इन वस्तुओं का उल्लेख करने के लिए मूल्यहास, ग्रेचुटी और सामान्य खर्चों में आवश्यक समायोजन किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान एआरआर की गणना से क्रमशः रु.888.27 लाख, रु.972.86 लाख और रु.811.66 लाख का बहिकरण मूल्यहास के समायोजन और आईजीएएपी के तहत अन्य खर्चों के रूप में दिखाया है। एसडब्ल्यूपीएल ने फॉर्म 6क में अपेक्षित परिकलन को प्रस्तुत किया है जो कार्यशील चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा द्वारा विधिवत प्रमाणित है और विश्वस्नीय माना गया है।
- (v). प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के क्लॉज 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में दिए गए प्रावधानों और कार्यात्मक दिशानिर्देशों और ऊपर बताए गए समायोजन के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.4 में किए गए निर्धारणों के अनुसार 2016-17 से 2018-19 के लिए, रु.19,762.86 लाख (रु.197.63) करोड़ औसत खर्च का परिकलन किया गया है।

- (vi). (क). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के नियोजित पूंजी के क्लॉज 2.5 के अनुसार सकल स्थिर संपत्ति (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) [भारतीय सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांत (आईजीएएपी)] के अनुसार वर्ष के अंकेक्षित वार्षिक लेखा और कार्यशील पूंजी में आईएनडीएएस के तहत उल्लेखित आंकड़ों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के अनुरूप वर्ष-3 के 31 मार्च/31 दिसंबर तक पूंजीगत कार्य प्रगति के साथ-साथ वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखा परीक्षित खातों में आईएनडीएएस के तहत सूचित रु.467.90 करोड़ की सकल अचल संपत्ति शामिल होंगे। एसडब्ल्यूपीएल ने रु.48,602.09 लाख (रु.486.03 करोड़) की सकल अचल संपत्ति पर आईजीएएपी के अनुसार प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2019 के खंड 2.5 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार विचार किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने आईजीएएपी के अनुसार सकल स्थायी परिसंपत्तियों की गणना करते हुए कार्यशील चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित निर्धारित फॉर्म-7 को प्रस्तुत किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने इस संबंध में एक मेलापक विवरण भी प्रस्तुत किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 2018-19 के अनुसार प्रस्तुत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल स्थायी परिसंपत्तियों को आईजीएएपी के अनुसार माना गया है।

एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों में रुपये 172.75 लाख की प्रगतिरत कार्यगत-पूंजी पर विचार किया है।

- (ख). कार्यशील पूंजी में टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 के अनुसार इन्वेंट्री, विविध देनदार और नकद शेष शामिल हैं। इन्वेंट्री की गणना प्रशुल्क, दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार की गई है। जहां तक नकदी का संबंध है एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2018-19 के बजाय पिछले तीन वर्षों के औसत के नकद व्यय पर विचार किया है। कार्यशील पूंजी गणना के लिए नकद-व्यय को वर्ष 2018-19 के एक महीने के नकद व्यय के हिसाब से माना गया है।

(ग). टैरिफ दिशानिर्देशों के खंड 2.6 के अनुसार, 2019 टैरिफ दिशानिर्देशों, 2019 को संचालित करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देशों के खंड 2.2 के साथ पठित, संविदात्मक दायित्वों से उत्पन्न स्वामी पतंग को पट्टा किराया/लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान, करने के लिए कार्यशील पूँजी की गणना हेतु विविध देनदार माना जाएगा। एसडब्ल्यूपीएल को एलए के अनुच्छेद 7.3.5.2 में निर्धारित की गई भूमि के पट्टा किराए का भुगतान अग्रिम रूप से हर साल अग्रिम में करना आवश्यक है। ऑडिट एनुअल अकाउंट्स में वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस फीस ₹.656.89 लाख है। 50% तत्संबंधी ₹.328.45 लाख के दृष्टिकोण के अनुसार बनता है, जो पहले के टैरिफ संशोधन में अनुसरण किया गया था। जबकि, एसडब्ल्यूपीएल ने अग्रिम लाइसेंस शुल्क के लिए ₹.433.88 लाख की राशि पर विचार किया है। एसडब्ल्यूपीएल ने कहा है कि उसने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹.867.77 लाख के लिए मई 2019 के महीने में अग्रिम लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया है और उसी को एआरआर गणना में माना गया है। एसडब्ल्यूपीएल ने तर्क दिया है कि एसडब्ल्यूपीएल ने पिछले वर्ष 2018-19 में 656.89 लाख भुगतान किया है और इसके बाद भी 4.26% की स्वीकार्य वृद्धि पर विचार किया गया है, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में के लिए यह लाइसेंस शुल्क वास्तविक राशि से कम होगा। ₹.867.77 लाख का भुगतान एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एमओपीटी को किया गया। इसलिए, एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान की गई वास्तविक राशि के आधे के आंकड़े के औचित्य देने की कोशिश की है, अर्थात् कार्यशील पूँजी के लिए ₹.433.88 लाख।

इस संबंध में, यह बताना प्रासंगिक है कि टैरिफ गाइडलाइंस 2019 में एआरआर अभिकलन की गणना करने के लिए पिछले तीन साल के व1, व2 और व3 के अंतिम लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं के के औसत के आधार पर कुछ समायोजनों के अध्याधीन तथा नियोजित पूँजी पर 16% प्रत्यापगम(रिटर्न) का उल्लेख है, जिसके लिए व3 के ऑडिटेड खातों में बताए गए आंकड़े आधार बनते हैं, का उल्लेख किया गया है। एसडब्ल्यूआर पीएल के मामले में एआरआर अभिकलन, वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर समायोजन के अध्याधीन है जो टैरिफ दिशानिर्देशों पर निर्धारित है एसडब्ल्यूपीएल का केवल एक घटक पर विचार करने के लिए अनुरोध यानि व4 के आंकड़ों के आधार पर कार्यशील पूँजी के लिए लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान, 2019-20 में उद्धृत कारणों से दिशानिर्देश की स्थिति के अनुरूप नहीं पाया गया है और इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया है। कार्यशील पूँजी की गणना को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है। वर्ष 2018-19 के ऑडिट किए गए वार्षिक खातों में 50% लाइसेंस फीस की सूचना दी गई, अर्थात् ₹.656.89 लाख का 50% = ₹.328.45 लाख माना जाता है।

(घ). ऊपर बताए अनुसार संशोधनों के अधीन, संशोधित नियोजित पूँजी एसडब्ल्यूपीएल द्वारा परिकलित कुल ₹.50,951.02 लाख की नियोजित पूँजी की तुलना में ₹.50,319.48 लाख बनती है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 16% की दर से नियोजित पूँजी पर मान्य प्रत्यागम ₹.8,152.16 लाख (आरओसीई) है। संशोधित नियोजित पूँजी के आधार पर आरओसीई ₹.8,051.12 लाख गणित होता है।

(vii). एआरआर में तीन वित्तीय वर्षों 2016-17 से 2018-19 के लिए व्यय का औसत और 16% आरओसीई शामिल हैं। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा निकाला गया एआरआर ₹. 279.15 करोड़ (₹.197.63 करोड़ + ₹.81.52 करोड़) है। हमारे द्वारा संशोधित एआरआर ₹.278.14 करोड़ (₹.197.63 करोड़ + ₹.80.51 करोड़) बनता है। इसके अलावा, टैरिफ गाइडलाइंस, 2019 के क्लॉज 2.8 के अनुसार, उक्त एआरआर को वर्ष 2019-20 के लिए लागू डब्ल्यूपीआई के 100% पर सूचकांकित किया जाना चाहिए जो कि 4.26% है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा मूल्यांकन की गई अनुक्रमित छत वाले एआरआर 4.26% इंडेक्सेशन को लागू करते हुए ₹.291.04 करोड़ है। जिसे एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए विगत समयावधि के घाटे ₹.30.51 लाख (₹.0.31 करोड़) के समायोजन के लिए ऐसा किया है और इस घाटे को एआरआर में जोड़ा है और अधिकतम सीमा स्तकरीय सूचकांकित एआरआर 291.35 करोड़ (₹.291.04 + 0.31 करोड़) की सीमा में आ गया है।

हालांकि, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 2016-17 से 2018-19 के लिए बाद में संशोधित लागत विवरण स्वीकार्य लागत और 16% आरओसीई के बाद रु.1070.53 लाख (रु.10.70 करोड़) के अधिक्य को दर्शाता है।

हमारे द्वारा किए गए संशोधित एआरआर अभिकलन के अनुसार संशोधित सूचकांकित अधिकतम सीमा स्तरीय एआरआर वर्ष 2019-20 के लिए रु.289.99 करोड़ (रु.278.14 करोड़ * 1.0426) बनता है। इसमें पिछली अवधि का समायोजन शामिल नहीं है। पिछली अवधि से संबंधित विश्लेषण आगे के पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत एआरआर गणना का अंतिम विस्तृत परिकलन, जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है, विश्वस्तीय है। यह मासूली संशोधन के अध्याधीन है जैसा कि ऊपर बताया गया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा विस्तृत एआरआर गणना और हमारे द्वारा संशोधित एआरआर गणना क्रमशः अनुलग्नक-1 (क) और (ख) के रूप में संलग्न हैं।

- (viii). बीओटी ऑपरेटरों के मामले में, टैरिफ गाइडलाइंस 2019 के क्लॉज 3.1.2. अनुसार, जो इस प्राधिकरण के पिछले आदेश के खिलाफ कोर्ट में नहीं गए हैं, के लिए पहले टैरिफ निर्धारण के दौरान की अवधि तक प्रशुल्क का निर्धारण सरल्स/घाटा, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के तहत प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के खंड 2.13 के अनुसार किया जाना है।

एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वास्तविक का औसत देते हुए फॉर्म-8 प्रस्तुत किया है। उक्त रूप में, एसडब्ल्यूपीएल ने स्वीकार्य व्यय के बाद रु.76.28 लाख के औसत शुद्ध घाटे का आकलन किया है और नियोजित पूंजी पर 16% प्रत्यागम प्रभारित किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 20% तत्संबंधी है और शेष राशि 80% अर्थात रु.76.28 करोड़ * 80% = रु.61.02 लाख है, एसडब्ल्यूपीएल ने फाइनल घाटे की गणना में 50% निवल घाटा अर्थात रु.30.51 लाख का समायोजन माना है। अधिकतम सीमा स्तरीय एआरआर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-8 टैरिफ दिशानिर्देशों, 2019 के तहत पहले चक्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। कार्यकारी दिशानिर्देश-2019 के साथ संबद्ध कथित फार्म में निर्धारित नोट के अनुसार टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 में दिए गए उक्त प्रपत्र में दिए गए नोट के तहत, फॉर्म 8, पहले टैरिफ संशोधन के बाद प्रस्तुत किया जाना प्रासंगिक है।

एसडब्ल्यूपीएल ने, हालांकि, बाद में 2016-17 से 2018-19 की पिछली अवधि के लिए संशोधित लागत विवरणियां जिनमें पिछले प्रशुल्क आदेश में विचार किए गए अनुमानों की समीक्षा की गई है। ये वास्तविक दिशा-निर्देश खंड 3.1.2 के अनुसार हैं। टैरिफ दिशानिर्देश 2019 टैरिफ गाइडलाइंस 2005 के क्लॉज 2.13 के साथ पढ़ें। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए पिछली बार की वास्तविक अवधि के वास्तविक अनुमानों की समीक्षा बाद के पैराग्राफ में बताए गए कारणों से संशोधित / सही कर दिया गया है तथा कारणों को आगामी पैराग्राफों में उल्लेखित किया गया है।

- (ix). अंतिम टैरिफ संशोधन के दौरान, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अनुमानों को मानते हुए ही एसडब्ल्यूपीएल का टैरिफ तय किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2016, 2017 से 2018-19 के लिए वर्ष 2016-17 के लिए अनुमानों का आकलन करने के लिए विश्लेषण किया गया है ताकि टैरिफ दिशानिर्देश 2019 के खंड 3.1.2 का अनुपालन करते हुए टैरिफ अवधि के दौरान एसडब्ल्यूपीएल के वास्तविक निष्पादन का आकलन किया जा सके। पिछले टैरिफ ऑर्डर में अनुमानित स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सामान्य दृष्टिकोण का अनुपालन किया गया है, जो 2016-17 से 2018-19 के लिए वास्तविक शुद्ध अधिशेष/घाटे का आकलन करने के लिए अपनाया गया है। विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(क) वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान एसडब्ल्यूपीएल द्वारा संचलित वास्तविक आगम-निर्गम 11.77 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है, नवम्बर 2016 के प्रशुल्क आदेश में

अनुमानित प्रत्येक तीन वर्षों के कुल योग 22.50 एमएमटीपीए के लिए अनुमानित प्रशुल्क 7.50 की तुलना में समतुल्य अवधि के लिए कुल योग 27.64 एमएमटीपीए हेतु क्रमशः 10.62 एमएमटीपीए और 5.25 एमएमटीपीए है।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 में एमओपीटी द्वारा सूचित एसडब्ल्यूपीएल के वास्तविक यातायात का कुल जोड़ 27.68 एमएमटीपीए है जो समतुल्य अवधि के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचित वास्तविक योग यातायात 27.64 एमएमटीपीए से थोड़ा भिन्न है। एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट किया है कि यातायात संख्या से नगण्य भिन्नता है क्योंकि इसे लदान के बिल के अनुसार वास्तविक आगम- निर्गम से लिया गया है। इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचित वास्तविक यातायात पर विचार किया गया है।

वास्तविक निष्पादन में भिन्नता 22.84% सकारात्मक है जिसे 20% से अधिक पाया गया है।

- (ख) वर्ष 2017-18 के अंतिम प्रशुल्क आदेश में सुविचारित आम अनुमान तीन महीनों अर्थात् जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक आदेश के कार्यान्वयन की तारीख से वास्तविक आय की तुलना में नवम्बर 2016 के प्रशुल्क आदेश में प्रभावी कार्गो-प्रबंधन प्रभार में 27.8% की प्रशुल्क वृद्धि और भू-किराया प्रभार में 10% की प्रशुल्क वृद्धि के प्रभाव को उल्लेखित/लागू करने के लिए यथानुपाती आधार पर वर्ष 2017-18 और 2018-19 की अवधि के लिए समायोजित किया गया है।
- (ग) पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 12 जून 2015 के पत्र के माध्यम से सूचित भारत के महान्यायवादी का विचार है कि लेखा परीक्षित खातों पर आधारित प्रचालक द्वारा अर्जित उनकी वास्तविक आय पर विचार किया जाना चाहिए न कि किसी अनुमानित आय पर। अतः विगत अवधि के विश्लेषण के उद्देश्य के लिए वार्षिक खाते में सूचित की गई वास्तविक आय पर विचार किया गया है।
- (घ) द्वितीय सर्वोच्च बोली लगाने वाले द्वारा उल्लेखित राजस्व अंश की सीमा तक लागत मद के रूप में राजस्व अंश पर विचार किया गया है अर्थात् यह अंतिम प्रशुल्क आदेश में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान सूचित वास्तविक कार्गो प्रबंधन राजस्व पर 13.10% जो कि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा भी किए गए 2005 के प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खण्ड 2.8.1 के अनुसार है।
- (ङ) एसडब्ल्यूपीएल ने, विगत अवधि के लिए इसके द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में आईजीएएपी के अनुसार अवमूल्यन पर विचार किया है। इसी तरह प्राकल्पना पर विचार किया गया है कि पिछले संशोधन के दौरान तैयार किया गया लागत विवरण अनुमानों पर आधारित था जो उस समय आईजीएएपी पर आधारित था। वर्ष 2016-17 से एसडब्ल्यूपीएल ने आईएनडीएस की लेखा-जोखा की प्रणाली का अनुसरण किया है। किन्तु एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आईजीएएपी के तहत अवमूल्यत आंकड़े तथा पेशेवर सनदी लेखाकार द्वारा एतद्वारा प्रमाणित एसडब्ल्यूपीएल द्वारा की गयी सम-तुलना स्वीकार की जाती है।
- (च) यह देखा गया है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के ग्रेच्यूटी और सामान्य व्यय के संबंध में लागत विवरण में विगत अवधि में आईजीएएपी के अनुसार आवश्यक समायोजन नहीं किया है। चूंकि पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए अनुमानों पर किया गया विचार एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुसरण किये गए आईजीएएपी के अनुसार तत्कालीन लेखा-जोखा प्रणाली पर आधारित था जबकि आईएनडीएएस पर आधारित वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए लेखा-परीक्षित खातों में सूचित आंकड़ा, उसी अवधि के लिए अनुमानों के सन्दर्भ में, वास्तविक की तुलना में आईजीएएपी के अनुरूप लाने की आवश्यकता है। एसडब्ल्यूपीएल ने यह समायोजन नहीं किया है। इसलिए, विगत अवधि के लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में, यह समायोजन फार्म

6क में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा उपलब्ध कराए गये आईजीएपी के अनुसार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। यह समायोजन एसडब्ल्यूपीएल द्वारा स्वयं फार्म 6क में प्रस्तुत इन मदों के लिए आईजीएपी आंकड़ों पर आधारित 217.50 लाख, 8.69 लाख और 18.20 लाख की सीमा तक इसे घटाते हुए प्रवंधन और सामान्य ऊपरी खर्च से संबंधित व्ययों में लिया गया है।

- (छ) एसडब्ल्यूपीएल के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए सूचित वास्तविक एफएमआई क्रमशः 18.58 लाख, 3564.87 लाख और 2576.96 करोड़ रूपये हैं।

एसडब्ल्यूपीएल ने एफएमआई शीर्ष के तहत वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमशः 88.75 लाख, 309.51 लाख और 421.56 लाख रूपये पर विचार किया है। यह आय अन्य बन्दरगाह सेवाओं से वार्षिक खातों के अनुसार संचालन आय से संबंधित है और इसलिए हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में इसे एफएमआई से संचालन आय में स्थानांतरित कर दिया गया है। एसडब्ल्यूपीएल ने, विदेश विनियम लाभ/हानि, भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस) आय, लेखा परीक्षित वार्षिक खातों में एफएमआई शीर्ष के तहत सूचित विविध आमदनियों की प्रकृति को स्पष्ट किया है। विदेश विनियम लाभ को खरीददारों के खाते में जमा के कारण होने वाला काल्पनिक(नोशनल) लाभ बताया गया है। चूंकि यह मद वास्तविक लेन-देन के कारण उत्पन्न होने वाली नहीं बताई गयी है, इसलिए, इसे हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में आय के रूप में नहीं लिया गया है। विविध आय के संबंध में, एसडब्ल्यूपीएल ने कहा है कि यह उप-संविदाकारों के साथ साझा किए गए उपकरण से उत्पन्न गैर-संचालनात्मक एकवार्गी आय है। इसलिए इन मदों पर हमारे द्वारा तैयार विगत अवधि के लिए उपांतरित लागत विवरण में एफएमआई के रूप में विचार नहीं किया गया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में एसईआईएस सेवा आमदनी को एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन आय के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसे लागत विवरण में उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा, लेखा परीक्षित वार्षिक खाते में सूचित सम्पत्ति के विक्रय और कबाड़ के विक्रय से प्राप्त लाभ की आय को भी विगत अवधि के लिए हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण में पकड़ा गया है।

- (ज) एलए के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एमओपीटी को प्रदत्त 1.53 करोड़ रूपये की सुरक्षा जमा परियोजना अवधि के अन्त में वापसी योग्य है। पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान, सुरक्षा जमा वापसी का 11% छूट द्वारा परियोजना समय की शेष अवधि पर वार्षिकीकरण कर दिया गया था। एसडब्ल्यूपीएल ने इस मद के प्रभाव पर विचार नहीं किया है। पिछले प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया में परियोजना के अन्त में प्राप्त योग्य अवसानक मूल्य को 11% की छूट दर को लागू करते हुए परियोजना अवधि के अन्त में वार्षिक किया गया था। तुलना के लिए लागत विवरण में उसी आंकड़े पर विचार किया गया है।

- (झ) सभी अन्य लागत मदों को वार्षिक खाते में सूचित माना गया है।

- (ञ) 2005 के तब लागू प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के तहत पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान लगायी गई पूंजी, निर्धारित शर्तों के अनुसार निवल निर्धारित सम्पत्ति + कार्यकारी पूंजी है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक खाते में सूचित निवल निर्धारित सम्पत्ति, आईएनडीएएस पर आधारित है। एसडब्ल्यूपीएल ने आरओसीई संगणना के उद्देश्य के लिए वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमशः 310.96 करोड़, 290.35 करोड़ और 270.08 करोड़ रूपये लगाई गयी पूंजी पर विचार किया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित लगाई गयी पूंजी कार्यकरण से समर्थित नहीं है।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 316.27 करोड़, 299.97 करोड़ रूपये और 271.80 करोड़ रूपये, पेशेवर सनदी लेखाकार द्वारा एतद्वारा प्रमाणित, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा आईजीएएपी के तहत यथाप्रस्तुत निवल निर्धारित सम्पत्ति की, पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान जो एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अपनाई गई आईजीएएपी लेखा पद्धति पर आधारित था, के तहत विचारित निवल स्थायी सम्पत्ति के अनुमान के साथ तुलना से लिए विचार किया गया है।

- (ट) कार्यकारी पूंजी पर मानकों के अनुसार विचार किया गया है। भंडार और अतिरिक्त के उपभोग का उल्लेख, 2005 के प्रशुल्क दिशा-निर्देशों में निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है। रोकड़ शेष पर दिशानिर्देश स्थिति के अनुसार एक महीने के रोकड़ व्यय पर विचार किया गया है। प्रत्येक वर्ष में पट्टा किरायों के 50% पर पिछले प्रशुल्क संशोधन में अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुसार कार्यकारी पूंजी के भाग के रूप में विचार किया गया है। वर्तमान दायित्वों पर क्रमानुसार वर्षों के लेखा परीक्षित खातों में विचार किया गया है। उपरोक्त समायोजनों के अध्याधीन कार्यकारी पूंजी का परिणाम क्रृष्णात्मक(नेगेटिव्ह) निकलता है। अतः, इसे शून्य माना गया है।

इसलिए, आशोधित कार्यपूंजी में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सुविचारित वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमशः 310.96 करोड़, 290.35 करोड़ रूपये और 270.07 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए क्रमशः 316.27 करोड़, 299.97 करोड़ और 271.80 करोड़ रूपये की सम्पत्तियों का केवल निवल ब्लॉक शामिल है जो किसी परिकलन द्वारा पुष्ट नहीं है।

- (ठ) समतुल्य अवधि के वास्तविक की तुलना में 2016-17 से 2018-19 के समीक्षात्मक अनुमानों के लागत विवरण की एक प्रति अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है।
- (ड) पिछले प्रशुल्क आदेश में विचार किए गए अनुमानों की तुलना में वास्तविक की तुलना की सार नीचे सारणी बद्ध है:

विवरण	सही अर्थों में वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए कुल योग (रु. लाख में)		विचलन % में
	प्रशुल्क आदेश के अनुसार अनुमान	वास्तविक	
प्रशुल्क (एमएमटीपीए में)	22.50	27.64	22.84%
कुल संचालन आय	569.59*	751.99	32.02%
एफएमई अल्प एफएमआई, अमूल्यन और ऊपरी खर्च सहित से संबंधित कुल व्यय	492.98	579.36	17.52%
लाभ पूर्व अधिक्य/घाटा	76.61	172.63	
नियोजित पूंजी (औसत)	316.89	296.01	(6.59%)
नियोजित पूंजी पर 16% प्रत्यागम	152.11	142.08	(6.59%)
आरओसीई के पश्चात निवल अतिरिक्त (विगत अतिरिक्त के समायोजन से पूर्व)	(75.50)	30.55	
नवम्बर 2016 आदेश में आकलित विगत अवधि के अतिरिक्त का समायोजन	75.52	-	
आरओसीई के पश्चात निवल अतिरिक्त (विगत अतिरिक्त के समायोजन से पूर्व)	-	30.55	

* प्रचालन आय अनुमानों को, नवम्बर 2016 के प्रशुल्क आदेश में जनवरी 2017 से 31 मार्च 2019 तक के लिए प्रभावी प्रशुल्क वृद्धि के प्रभाव को प्रतिबिम्बित करने के लिए अद्यतित किया गया है।

(द) 2016-17 से 2018-19 की अवधि से संबंधित विगत अवधि के संदर्भ में वर्गीकरण के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:-

- (i.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान प्रबंधित वास्तविक सकल आगम-निर्गम 22.50 एमएमटीपीए के अनुमानित प्रशुल्क की तुलना में 22.64 एमएमटीपीए है। वास्तविक मापदंडों में भिन्नता अर्थात् अनुमानों की तुलना में वास्तविक संचालित 22.84% आगम-निर्गम सकारात्मक है।
- (ii.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अर्जित संचालन आय 569.59 करोड़ रूपये के अनुमान की तुलना में 751.99 करोड़ रूपये है जिसका परिणाम इसी अवधि के लिए 32.02% की सकारात्मक भिन्नता है।
- (iii.) व्यय की ओर से, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए वास्तविक कुल व्यय इसी अवधि के लिए पिछले आदेश में विचारित 492.98 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय की तुलना में 579.36 करोड़ है। अतः, पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमानित व्यय की तुलना में कुल वास्तविक व्यय 17.52% की सकारात्मक भिन्नता प्रदर्शित करता है।
- (iv.) 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए लगाई गयी वास्तविक औसत पूँजी 316.89 करोड़ रूपये की नियोजित औसत अनुमानित पूँजी की तुलना में 296.01 करोड़ रूपये है। औसत नियोजित पूँजी में भिन्नता 6.59% क्रणात्मक है।
- (v.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा विगत अवधि के लिए प्रस्तुत लागत विवरण के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल ने स्वीकार्य लागत और 16% अनुज्ञेय आरओसीई के पश्चात वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए 10.70 करोड़ रूपये का कुल अधिशेष अर्जित किया है। हमारे द्वारा तैयार किए गए विगत अवधि के लिए आशोधित लागत विवरण के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल ने 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए स्वीकार्य लागत और 16% आरओसीई के पश्चात 30.55 करोड़ का कुल अधिशेष अर्जित किया है।
- (vi.) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अर्जित औसत आरओसीई को निर्धारित करने के लिए जब हम उक्त तीन वर्षों की आरओसीई से पूर्व की स्थिति देखते हैं, तो हमारे द्वारा तैयार किए गए लागत विवरण से यह पता चलता है, कि एसडब्ल्यूपीएल ने 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रत्यागम से पूर्व कुल 172.63 करोड़ रूपये का अधिशेष अर्जित किया है और औसत अधिशेष 57.54 करोड़ निकलता है। यद्यपि, नियोजित औसत पूँजी पर अर्जित औसत वार्षिक प्रत्यागम, 19.44% तक निकलता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	औसत
प्रत्यागम से पूर्व वास्तविक अधिक्य/कमी	8,158.68	7,170.09	1,934.68	17,263.45 (कुल) 5754.48 (औसत)
नियोजित वास्तविक पूँजी	31,626.88	29,996.53	27,180.57	29,601.33 (औसत)
नियोजित पूँजी पर उपर्जित वास्तविक प्रत्यागम	25.80%	23.90%	7.12%	19.44%

- (vii.) प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खण्ड 2.13 के अनुसार, पिछले प्रशुल्क चक्र के लिए वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा, यदि, +20% से अधिक विचलन दर्शाती है, तो ऐसे उपर्जित लाभ/हानि का 50% अगले प्रशुल्क चक्र में समायोजित किया जाएगा। एजी के मतानुसार, जैसा कि एसओएएस द्वारा भी अवगत कराया गया है, वास्तविक और वित्तीय दोनों मापदंडों में भिन्नता, खण्ड 2.13 के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखी जानी चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि वास्तविक मापदंड में भिन्नता अर्थात् नियोजित पूँजी पर लाभ के मामले में संचालित वास्तविक आगम-निर्गम और वित्तीय निष्पादन सकारात्मक है और यह 20% से अधिक है। इसके अलावा, उपरोक्त सारणी के अनुसार पिछले प्रशुल्क आदेश में अनुमत 16% प्रत्यागम की तुलना में नियोजित लागत पर 19.44% का औसत प्रत्यागम अर्जित किया है। इसलिए, वास्तविक और वित्तीय दोनों मापदंडों में भिन्नता 20% से अधिक है, और यह भिन्नता धनात्मक है। अतः, एजी के 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खण्ड 2.13 की व्याख्या संबंधी मत का अनुसरण करते हुए वर्तमान प्रशुल्क चक्र के लिए प्रशुल्क निकालते समय एसडब्ल्यूपीएल संचालनों के विगत अवधि के अधिशेष के समायोजन का मामला बनता है।

एजी के मतानुसार, वास्तविक और वित्तीय दोनों मापदंडों में भिन्नता यदि 20% से अधिक है, तो अधिशेष का 20% संचालक द्वारा रोका जाना अनुमत होगा। केवल वह अधिक्य 20% अधिशेष जो संचालक और प्रयोक्ता के बीच बराबर अर्थात् 50:50 भागों में बांटा जाएगा। संक्षेप में, अतिरिक्त अधिशेष का 60% संचालक के पास रोका जाना अनुमत है और 40% अतिरिक्त अधिशेष प्रयोक्ताओं द्वारा भावी प्रशुल्क समायोजन पर विचार करते हुए बांटा जाएगा।

तदनुसार, वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए निवल अतिरिक्त अधिशेष का 40% अर्थात् 30.55 करोड़ रूपये * 40% 12.22 करोड़ रूपये को तीन वर्षों में विस्तारित करते हुए वर्तमान प्रशुल्क चक्र में समायोजन के लिए विचार किया जाना है और इसका प्रति वर्ष प्रभाव 4.07 करोड़ रूपये होगा जो कि सूचकांकित एआरआर को कम करते हुए एआरआर अभिकलन में कमी के लिए विचार किया गया है।

वर्ष 2019-20 के लिए, अगले संशोधन के दौरान 1 अप्रैल, 2019 से संशोधित एसओआर के कार्यान्वयन की तारीख तक 2005 के प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के खण्ड 2.13 के तहत वास्तविक निवल अधिक्य/कमी का मूल्यांकन किया जाएगा।

(x). जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है कि विगत अवधि अधिशेष के समायोजन के बिना संशोधित अनुक्रमित एआरआर की अधिकतम सीमा वर्ष 2019-20 के लिए 289.99 करोड़ रूपये पर पहुंच गयी थी (रु. 278.14 करोड़* 1.0426)। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए रु. 4.07 करोड़ के अतिरिक्त विगत अवधि अधिशेष की घटीती के पश्चात सूचकांकित एआरआर की अधिकतम सीमा रु.285.92 करोड़ होती है (अर्थात् रु.278.99 करोड़ – रु. 4.07 करोड़)।

(xi). (क) प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2019 के खण्ड 2.10 के अनुसार एसओआर तय करने के लिए विचार किये जाने वाला आगम-निर्गम, संबंधित बंदरगाह द्वारा प्रमाणित वर्ष 1, वर्ष 2 और वर्ष 3 के दौरान बीओटी संचालक द्वारा संचालित वास्तविक आगम-निर्गम का औसत होगा। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के औसत आगम-निर्गम एसडब्ल्यूपीएल द्वारा 92.00 एमएमटीपीए माना गया है। इसलिए, इस विश्लेषण के उद्देश्य के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचित वास्तविक आगम-निर्गम पर विचार किया गया है।

(ख) प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2019 के खण्ड 2.11.1 के अनुसार, बीओटी संचालक, वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित बाजार की स्थितियों के माइदानज़र और पेशेवर सनदी

लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचककांकित एआरआर की अधिकतम सीमा के भीतर दरमान तैयार करने के लिए दरों को निर्धारित करने की छूट हैं।

मूल प्रस्ताव में, एसडब्ल्यूपीएल ने स्थान किराया प्रभार और कार्गो संचालन प्रभारों में बोर्ड की अनुमति से 23% की वृद्धि का प्रस्ताव किया था।

एमओपीटी ने भू-किराया प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि पर एतराज जताया है। क्योंकि एमओपीटी एलए के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल के भू-किराया राजस्व से राजस्व-हिस्सा प्राप्त नहीं करता है। बन्दरगाह ने एसडब्ल्यूपीएल से भू-किराया प्रभार में नाममात्र वृद्धि करने और मूल प्रस्ताव में बोर्ड अनुमति से एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित 23% की वृद्धि की बजाय कार्गो संबंधी प्रभारों में उच्च वृद्धि करने पर विचार करने का अनुरोध किया है। एमओपीटी ने भी एक स्थान पर विचार किया है कि जलयान संबंधी गतिविधियां बहुत हट कर होती हैं और यदि एसडब्ल्यूपीएल कार्गो में 48% की वृद्धि का प्रस्ताव करता है तो वे बुरा नहीं मानते।

एमओपीटी द्वारा अपेक्षित कार्गो संचालन गतिविधि और पोत संबंधी गतिविधियों के बीच व्यय के कार्यकलाप-वार आवंटन के संबंध में, जैसा कि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सही कहा गया है, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के तहत कार्यकलाप-वार लागत विवरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकलाप-वार लागत का निर्धारण तैयार करना 2005 के पूर्व प्रशुल्क दिशा-निर्देशों के तहत लागू था। प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2019 के तहत, शुल्क कुछ समायोजनों और 16% आरओसीई के अधीन लेखा-परीक्षित खातों में सूचित वास्तविक आंकड़ों पर किए जाने वाले प्राक्कलन पर अपेक्षित वार्षिक राजस्व के आधार पर निर्धारित किया जाना है। बीओटी संचालक ऐसी दरों का प्रस्ताव करने की छूट प्राप्त है कि प्रस्तावित दरों पर राजस्व अनुमान एआरआर के भीतर हों। ऐसा होने पर, एमओपीटी द्वारा उठाए गए विन्दु कि व्यय का कार्यकलाप-वार आवंटन किया जाए, पूर्व के प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2005 द्वारा अभिशासित बीओटी संचालकों के लिए लागू नए प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे।

एमओपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिकोण से एसडब्ल्यूपीएल ने कहा है कि अंतिम संशोधित प्रस्ताव में, मूल प्रस्ताव में इन दोनों कार्यकलापों में प्रस्तावित 23% वृद्धि की तुलना में भू-किराया प्रभार में 15% वृद्धि और कार्गो-संचालन प्रभार में 26% की वृद्धि प्रस्तावित है। अंतिम प्रस्तावित एसओआर में प्रस्तावित कार्गो संचालन प्रभार की तुलना करने पर और राजस्व अनुमानों में यह पाया गया है कि कार्गो संचालन प्रभारों में वृद्धि 20% से 26.67% की सीमा में और भू-किराया प्रभार में 15% वृद्धि प्रस्तावित है। कार्गो संचालन गतिविधि में अधिक वृद्धि पर विचार करने के लिए एमओपीटी द्वारा किए गए अनुरोध के सन्दर्भ में, एसडब्ल्यूपीएल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कार्गो संचालन में अधिक वृद्धि की जाती है तो कार्गो पड़ोस के बंदरगाहों पर चला जाएगा। प्रशुल्क दिशा-निर्देश, 2019 का खण्ड 2.11.1 बीओटी संचालकों को वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित बाजारी स्थितियों के मद्दे नज़र अनुमानित एआरआर के भीतर दरों निर्धारित करने के लिए छूट प्रदान करता है। एसडब्ल्यूपीएल का प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के प्रावधानों भीतर है। वास्तव में मैरसर्स हीरालाल एंड कं. एसडब्ल्यूपीएल के प्रस्ताव और बीआरसी की दरों में अपेक्षित वृद्धि से सहमत है। उन्होंने विशेष तौर पर उल्लेख किया है कि एसडब्ल्यूपीएल की

दक्षता बहुत अधिक है और इसलिए उन्हें वीआरसी में प्रस्तावित वृद्धि के कारण कोई समस्या नहीं है।

संशोधित प्रस्तावित दर पर, एसडब्ल्यूपीएल ने 2828.50 करोड़ रुपये के राजस्व का अनुमान लगाया है। एसडब्ल्यूपीएल ने वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए इसी औसत यातायात के लिए प्रस्तावित एसआरआर में प्रत्येक टैरिफ आइटम का संकेत देते हुए राजस्व आकलन का विस्तृत परिकलन किया है, जो कि टैरिफ विशानिर्देश, 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार आवश्यक है। राजस्व अनुमान विवरण को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है।

हमारे द्वारा किए गए संशोधित एआरआर अभिकलन और पिछले अवधि के विश्लेषण के अनुसार, पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लेखित किए गए हैं, पिछली अवधि के अधिशेष के समायोजन के बाद संशोधित अधिकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित एआरआर 285.92 करोड़ (यानी ₹. 289.99 करोड़ - ₹ .4.07 करोड़) बनता है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित टैरिफ पर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित राजस्व ₹.287.50 करोड़, एआरआर ₹. 1.58 करोड़ से अधिक है।

चूंकि एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अनुमानित राजस्व, एआरआर से अधिक है, और यह देखते हुए कि लाइसेंसधारी बंदरगाह ने वर्थ किराया शुल्कों में वृद्धि पर आपत्ति जताई है, मौजूदा वर्थ किराया शुल्कों में वृद्धि को बंदरगाह द्वारा प्रस्तावित 15% वृद्धि के अनुसार 12.5% अनुमत करना होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राजस्व अनुमान संशोधित एआरआर के भीतर रहे। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर संशोधित राजस्व अनुमान, मामूली राजस्व अंतर की सीमा ₹.0.08 को छोड़ते हुए करोड़ ₹.285.84 करोड़ निकलता है।

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत राजस्व अनुमान और हमारे द्वारा संशोधित राजस्व अनुमान क्रमशः अनुलग्नक-III (क) और (ख) के रूप में संलग्न हैं।

(xii). उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत अधिकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित एआरआर का सारांश, जो कि हमारे द्वारा संशोधित लागत विवरण पर आधारित है, नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत एसआरआर परिकलन	प्राधिकरण द्वारा संशोधित एआरआर परिकलन
1	वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए औसत स्वीकार्य व्यय [व1 + व2 + व3] / 3	197.63	197.63
2	31.03.2019 को पूंजी नियोजित है जिसमें 31.03.2019 को पूंजी कार्य प्रगति पर है और मानदंडों के अनुसार कार्यशील पूंजी है	509.51	503.20
3	की नियोजित पूंजी पर 16% प्रत्यागम	81.52	80.51
4	31 मार्च 2019 तक एआरआर) 4 = 2 + 3)	279.15	278.14
5	वर्ष 2019-20 (वर्ष 2019-20 के लिए 4.26%) के लिए लागू एआरआर @ 100% डब्ल्यूपीआई में सूचकांकन	291.04	289.99

6	एसडब्ल्यूपीएल: एसडब्ल्यूपीएल द्वारा एआरआर अभिकलन में उल्लेखित वर्ष 2016-17 से 2019-20 की पिछले अवधि के तुकसान का समायोजन जोड़ना। प्राधिकरण : एआरआर अभिकलन में वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए पिछले अधिशेष का समायोजन घटाना।	0.31	(-4.07
7	सूचकांकित वार्षिक राजस्व मांग एआरआर))	291.35	285.92
8	एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित दर पर अनुमानित राजस्व और वर्ष भाड़े के प्रभार में एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित 15% की वृद्धि के स्थान पर प्राधिकरण द्वारा विचारित 12.5% वृद्धि के साथ संशोधित राजस्व का अनुमान,	287.50	285.84
9	राजस्व में अंतर	3.85	0.08

(xiii). एमओपीटी का एक और बिंदु यह है कि एसडब्ल्यूपीएल ने थर्मल कोल और लौह अयस्क छर्रों के कार्गो प्रहस्तन प्रभार में रियायत का प्रस्ताव किया है जो विदेशी कार्गो के लिए प्रस्तावित दर का 60% है। ये दो कार्गो आइटम तटीय रियायत के लिए सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुसार हकदार नहीं हैं। एसडब्ल्यूपीएल के मौजूदा एसओआर इन दो कार्गो वस्तुओं के लिए तटीय रियायत नहीं देता है जो तटीय रियायत के लिए पात्र नहीं हैं। एसडब्ल्यूपीएल को सरकार के तटीय रियायत नीति के अनुरूप प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया गया था, जिनका सभी महापत्त न्यासों और बीओटी ऑपरेटरों के बीच समान रूप से पालन किया जाता है।

अंतिम संशोधित एसओआर प्रस्ताव में, एसडब्ल्यूपीएल ने सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुरूप किसी भी तटीय रियायत के बिना थर्मल कोयले के लिए अलग दर का प्रस्ताव किया है। हालांकि, इस संबंध में, लौह अयस्क छर्रों, एसडब्ल्यूपीएल ने तटीय कार्गो के लिए रियायती दर का प्रस्ताव दिया है जो सरकार की तटीय रियायत नीति के अनुरूप नहीं है। संशोधित एसओआर में, कार्गो प्रहस्तीन दर और तटीय लौह अयस्क छर्रों के लिए घाट-भाड़ा विदेशी कार्गो के लिए प्रस्तावित दर के बराबर है क्योंकि यह कार्गो तटीय रियायत के लिए योग्य नहीं है। इसका कोई राजस्व प्रभाव नहीं होगा क्योंकि 2016-17 से 2018-19 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई तटीय लौह अयस्क छर्रों के आगम-निर्गम के प्रहस्त न की सूचना नहीं है।

(xiv). विलंबित भुगतान और धन-वापसी के लिए ब्याज की दंडात्मक दर के संबंध में, एसडब्ल्यूपीएल ने 15% की दर से दंडात्मक ब्याज का प्रस्ताव किया है, जो कि टैरिफ दिशानिर्देश 2019 के खंड 5.4.1 के अनुरूप है। आयात कार्गो के लिए मौजूदा तीन दिनों की निःशुल्क अवधि को निर्यात कार्गो के लिए निर्धारित सात दिन के बराबर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। विलंबित भुगतान और धन वापसी के लिए ब्याज की दंड दर के संबंध में, आरंभ कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। 2019 की कार्यात्मक दिशानिर्देशों में बीओटी प्रचालकों को निशुल्क अवधि निर्धारित करने की छूट प्रदान की गई है। अतः प्रस्तावित निशुल्की अवधि को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(xv). एसडब्ल्यूपीएल से अनुरोध किया गया था कि वह तटीय माल/केटेनर के लिए रियायती शुल्क वसूलने के संबंध में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सामान्य अनुकरणीय आदेश सं. प्राधिकरण/53/2015-बीओसीपीटी दिनांक 29 सितंबर 2015 तथा आगे के प्राधिकरण/53/2015-बीओसीपीटी दिनांक 26 नवंबर 2015 और 10 जून 2016 में अनुमोदित एवं निर्धारित एसओआर के प्रावधानों को सम्मेलित करे। उक्त आदेश सभी

मेजर पोर्ट ट्रस्टों और संबंधित बीओटी ऑपरेटरों द्वारा आम अनुपालन के लिए है, जिनके दरमानों में प्रासंगिक शर्तों को निर्धारित किया गया है। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा शामिल किए गए आम अनुकरणीय नोट, उक्त आदेश के अनुरूप नहीं हैं। ऐसा होने के कारण, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित '1.2 सामान्य नियम और शर्तें' के तहत इन नोटों को इस प्राधिकरण के द्वारा 26 नवंबर 2015 और 10 जून 2016 के आदेशों में अनुमोदित संशोधित प्रावधानों के साथ बदला गया है।

(xvi). मूल प्रस्ताव में बंदरगाह द्वारा प्रस्तावित पोतों को पानी की आपूर्ति और विविध सेवाओं के लिए नई प्रशुल्क मदों को एसडब्ल्यूपीएल द्वारा अंतिम संशोधित प्रस्ताव में वापस ले लिया गया है।

(xvii). टैरिफ गाइडलाइंस, 2019 के क्लॉज 2.12 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति को वार्षिक रूप से सूचकांकित किया जाएगा। प्रासंगिक वर्ष के इस तरह के समायोजित एसओआर आगामी वर्ष के 1 मई से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक लागू होंगे। यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि वर्तमान मामले में वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक सूचकांकन, दरमान निर्धारित करने से पहले ही कर लिया गया है। इस प्रकार इस आशय का एक नोट कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान प्राधिकरण द्वारा घोषित किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांकन के अध्याधीन हैं, दरमानों में शामिल किया गया है। यह वार्षिक सूचकांकन 01 मई 2010 से लागू होगा। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचकांकित दरमानों को संबंधित एमओपीटी, उपयोगकर्ताओं और इस प्राधिकरण को एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचित किया जाना अपेक्षित होगा।

(xviii). टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 के खंड 4.9, में तीन वर्षों के प्रशुल्कच वैधता चक्र को वार्षिक सूचकांकन के अध्याधीन रखा गया है जैसा कि खंड 2.12 में उल्लेखित है। इसलिए, संशोधित एसओआर की वैधता, एसओआर में निर्धारित वार्षिक सूचकांकन खंड के अध्याधीन, संशोधित एसओआर की प्रभावी तारीख से 3 साल की अवधि के लिए निर्धारित है।

(xix). टैरिफ दिशानिर्देश 2019 के खंड 4.8, में कहा गया है कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश, आमतौर पर राजपत्र में अधिसूचित आदेश से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा। तदनुसार, यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा।

(xx). (क). टैरिफ दिशानिर्देश, 2019, के अनुसार, दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम सीमा स्तर की हैं; इसी तरह, छूट और रियायतनिम्नतम स्तर पर हैं। एसडब्ल्यूपीएल, कम दरों और/या उच्च छूट और रियायत देने की अनुमति देने के लिए छूट का प्रयोग कर सकता है।

(ख). रिकॉर्ड में पायी गई स्पूष्टप त्रुटि पाए जाने पर या किसी अन्य न्यायसंगत कारण से मान्य होने पर, एसडब्ल्यूपीएल, पारित किए गए आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पर्याप्त औचित्य/तर्क के साथ इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रशुल्क की समीक्षा के लिए संपर्क कर सकता है।

13.1. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों से और सामूहिक आवेदन सोच विचार के आधार पर, अनुलग्नक – IV के रूप में संलग्न एसडब्ल्यूपीएल के संशोधित दरमानों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

13.2. एसडब्ल्यूपीएल के संशोधित दरमान और शर्तें भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद की लागू हो जाएंगे और संशोधित दरमान प्रभावी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए लागू रहेंगे। प्रदान की गई यह स्वीकृति, प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विस्तारित नहीं किए जाने की स्थिति में स्वतः समाप्त हो जाएगी।

13.3. टैरिफ दिशानिर्देश 2019 के खंड 7 के अनुसार, एसडब्ल्यूपीएल कार्गो आगम-निर्गम के प्रहस्त न और पोतों की वर्ष-डे आउटपुट पर रिपोर्ट, बिना किसी त्रुटि के लगातार टीएएमपी को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद 90 दिनों के भीतर एसडब्ल्यूपीएल द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कोई अन्य जानकारी जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक है, उन्हें भी समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। एसडब्ल्यूपीएल को विशेष रूप से अपेक्षित आवश्यक जानकारी प्रदान न करने से बचने की सलाह दी जाती है।

टी. एस बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./386/19]

अनुलग्नक-1 (क)

फार्म - 1

प्रशुल्क नीति, 2019 के तहत महापत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी ऑपरेटरों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत और पत्तन द्वारा संशोधित प्रशुल्क निर्धारण के लिए वार्षिक राजस्व मांग का परिकलन

रु. लाखों में

क्रम सं.	विवरण	व1 (2016-17)	व2 (2017-18)	व3 (2018-19)
(1).	कुलव्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार)			
(i).	प्रचालन व्यय(मूल्य हास सहित)	24,021.16	23,605.00	16,819.02
(ii).	वित्त और विविध व्यय(एमएमई)	239.73	279.60	21.84
	कुल व्यय 1 = (i) + (ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86
(2).	आईजीएपी और आईएनडीएस के अनुसार सूचित आंकड़ों में मर्दों के बारे में जहां कहीं विचलन है, समायोजन घटाएं			
(i).	मूल्यहास	(670.77)	(964.17)	(793.46)
(ii).	अन्य व्यय आइटम, यदि कोई हो, सूचीबद्ध हों	(217.50)	(8.69)	(18.20)
	समायोजन का कुल 2=(i)+(ii)	(888.27)	(972.86)	(811.66)
(3).	घटाएं समायोजन:			
(i).	पत्तन को अदा किया गया वास्तविक रायलटी/ राजस्व का हिस्सा	(3,554.06)	(2,154.16)	
(ii).	ऋणों पर व्याज	(239.73)	(279.60)	(21.84)
(iii).	अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-
(iv).	इन्वेंट्री के धीमें संचलन के लिए प्रावधान	-	-	-
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हों	-	-	-

	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	(3,655.71)	(3,833.65)	(2,176.00)
(4).	जोड़ें: खंड 2.2 के अनुसार स्वीकार्य रॉयल्टी / राजस्व शेयर। टैरिफ गाइडलाइंस, 2019 की	2,486.07	2,586.56	1,567.75
(5).	सभी समायोजनों के पश्चात कुल व्यय (5 = 1-2-3+4)		21,664.65	15,420.95
(6).	क्रम सं.5 का औसत व्यय = [व1 + व2 + व3] / 3	19,762.86		
(7).	नियोजित पूँजी			
	(i).कुल स्थायी परिसंपत्तियां(संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) 31 मार्च के अनुसार बीओटी आपरेटर द्वारा अनुकरणीय(एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत आईजीएपी के अनुसार- चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रमाणित)			
	(ii) जोड़ें: बीओटी आपरेटर द्वारा 31 मार्च को Y 3 या 31 दिसंबर को प्रगति के रूप में प्रगति में पूँजीगत कार्य (लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार)			
	(iii) जोड़ें: टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यशील पूँजी			
	(क) मदसूची	162.85		
	(ख) विविध देनदार	433.88		
	(ग) नकद	1,579.45		
	(घ) सम (क) + (ख) + (ग)	2,176.18		
	(iv)कुल कार्यरत पूँजी कार्यरत [(i) + (ii) - (iii)]	50,951.02		
(8).	क्रम सं.7 (iv) पर नियोजित पूँजी पर 16% पर प्रत्यागम।			
(9).	वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) 31 मार्च को व3 या 31 दिसंबर को व3 के रूप में यथा लागू होती है [(6) + (8)]			
(10).	वर्ष 4 [(9) x 1.0426] के लिए लागू एआरआर @ 100% डब्ल्यूपीआई में इंडेक्सेशन			
(11).	वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए संबंधित समयावधि घाटा ₹ .30.51 लाख है			
(12).	पिछली अवधि के घाटे के समायोजन के बाद एआरआर [(10) + (11)]			
(13).	सूचकांकित वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर)	29,134.72		
(14).	ऊपर क्रम नं .11 में अनुमानित अधिकतम सीमा स्तरीय एआरआर के भीतर प्रस्तावित सूचकांकित दरमानों में राजस्व अनुमान।	28,750.36		

अनुलग्नक-1 (ख)

फार्म 1

प्रशुल्क नीति , 2019 के तहत महापत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी आपरेटरों के लिए एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत और पत्तन द्वारा संशोधित प्रशुल्क निर्धारण के लिए वार्षिक राजस्व मांग का परिकलन

रूपये लाखों में

	विवरण	व1 (2016-17)	व2 (2017-18)	व3 (2018-19)

(1).	कुल व्यय (लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार)			
(i).	प्रचालन व्यय(मूल्य हास सहित)	24,021.16	23,605.00	16,819.02
(ii).	वित्त और विविध व्यय (एमएमई)	239.73	279.60	21.84
	कुल व्यय 1=(i)+(ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86
(2).	आईजीएपी और आईएनडीएएस के अनुसार सूचित आंकड़ों में मदों के बारे में जहां कहीं विचलन है, समायोजन घटाएं			
(i).	मूल्यहास	670.77	964.17	793.46
(ii).	व्यय की अन्य मदें यदि कोई हो सूचीबद्ध की जाएं		8.69	18.20
	कुल समायोजन 2=(i)+(ii)	888.27	972.86	811.66
(3).	समायोजन घटाएं			
(i).	पत्तन को अदा किया गया वास्तविक रायलटी/राजस्व का हिस्सा		3,554.06	2,154.16
(ii).	ऋणों पर ब्याज	239.73	279.60	21.84
(iii).	अशोध्य और सदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-
(iv).	इन्वेंट्री के धीमे संचालन के लिए प्रावधान	-	-	-
(v).	अन्य प्रावधान, यदि कोई हो	-	-	-
	3 का योग = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	3,655.71	3,833.65	2,176.00
(4).	जोड़ें : प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के क्लाज़ 2.2 के अनुसार अनुज्ञेय रायलटी/राजस्व का भाग	2,486.07	2,586.56	1,567.75
(5).	सभी समायोजनों के पश्चात कुल व्यय (5 = 1-2-3+4)		21,664.65	15,420.95
(6).	क्रम सं.5 का औसत व्यय = [व1 + व2 + व3] / 3			
(7).	नियोजित पूँजी			
	(i).कुल स्थायी परिसंपत्तियां (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) 31 मार्च के अनुसार बीओटी आपरेटर द्वारा अनुकरणीय (एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुतआईजीएपी के अनुसार- चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रमाणित)			
	(ii). जोड़ें: बीओटी आपरेटर द्वारा 31 मार्च को Y3 या 31 दिसंबर को प्रगति के रूप में प्रगति में पूँजीगत कार्य (लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार)			
	(iii). जोड़ें: टैरिफ दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.6 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यशील पूँजी			
	(क) मदसूची	162.85		
	(ख) विविध देनदार	328.45		
	(ग) नकद	1,053.34		
	(घ) जोड़: (क) + (ख) + (ग)	1,544.64		
	(iv). कुल नियोजित पूँजी[(i)+(ii)-(iii)]	50,319.48		
(8).	क्रम सं. 7 (iv) पर कैपिटल एम्प्लॉइड 16% पर प्रत्यागम			
(9).	वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर) 31 मार्च को व3 के लिए यथा लागू [[6] + (8)]			

(10).	एआरआर @ 100% डब्ल्यूपीआई में इंडेक्सेशन,उदाहरण के लिए वर्ष व4 के लिए लागू यदि व4 2019-20 है, तो लागू डब्ल्यूपीआई 4.26% है और वर्ष व4 के लिए सूचकांकित सूचकांकित एआरआर (9) 1.0426 होगा		
(11).	कम: तीन वर्षों में 2016-17 से 2018-19 के लिए पिछली अवधि के अधिशेष का समायोजन। इस तरह के समायोजन का वार्षिक प्रभाव 407.31 लाख रुपये है। (यानी $3054.81 \text{ लाख } \times 40\% = 1221.92 \text{ लाख} / 3 \text{ साल} = 407.31 \text{ लाख रुपये}$)।		
(12).	पिछली अवधि के अधिशेष (10-11) के समायोजन के बाद अधिसूचित सूचकांकित वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर)		
(13).	ऊपर क्रम सं.11 में अनुमानित अधिकतम सीमा स्तरीय सूचकांकित एआरआर के भीतर प्रस्तावित अधिसूचित दरमानों में राजस्व अनुमान।	28,584.00	

अनुलग्नक-II

दक्षिण पश्चिम पत्तन लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल)

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तुत और टीएएमपी द्वारा संशोधित एसडब्ल्यूपीएल के पिछले अवधि के वर्ष 2016-17 से 2018-19 के निष्पादन का विवरण

क्रम सं.	विवरण	15 जनवरी 2016 के ट्रैफ ऑंडर में अनुमानित अनुमान				वास्तविक			कुल
		2016-17	2017-18	2018-19	कुल	2016-17	2017-18	2018-19	
	आगम/निर्वाचनीय में	7.50	7.50	7.50	22.50	11.77	10.62	5.25	27.64
	धमता (एमएमटीपीए)	7.00	7.00	7. 0	21.00	7.00	7.00	7.00	21.00
I	कुल परिचालन आय								
	(i) काग़ॉ हैडलिंग आय	10,744.20	12,838.79	12,838.79	36,421.77	18,958.89	19,763.87	11,967.05	50,689.81
	(ii) पोत संबंधी आय	6,541.87	7,003.73	6,991.15	20,536.75	11,167.66	7,819.55	4,701.94	23,689.15
	(iii) अन्य आय	-	-	-	-	88.75	309.51	421.56	819.82
	योग (i + ii)	17,286.06	19,842.52	19,829.94	56,958.52	30,215.30	27,892.93	17,090.54	75,198.77
II	परिचालन लागत (मूल्यहास को छोड़कर)								
	(i) काग़ॉ हैडलिंग व्यय	7,596.23	7,976.04	8,374.84	23,947.11	12,125.64	11,408.33	6,761.29	30,295.26
	(ii) उपकरण चलाने की लागत	1,907.31	2,038 33	2,124.87	6,070.51	1,827.34	1,740.89	1,060.99	4,629.22
	(iii) मितानापन ट्रैकिंग	-	-	-	-	219.10	328.07	313.46	860.63
	(iv) रायल्टी / राजस्व हिसेदारी	1,316.03	1,316.03	1,316.03	6.00	2,486.07	2,586.56	1,567.75	6,640.39
	(v) सी। समझौते के अनुसार देव किराया किराया	613.30	643.20	675.36	1,931.86	603.14	605.45	656.89	1,865.47
	(vi) बीमा	152.05		181.48			117.54		392.05

			165.29		498.82	144.42		130.08	
	(vii) अन्य व्यय	59.22	60.68	62.17 182.07					-
	योग (i से vii)	11,644.14	12,199.57	12,7 4.75 36,578.46	17,405.71	16,786.85		10,490.46	44,683.02
III	मूल्यहास्त	2,343.15	2,421.35	2,594.25 7,358.75		2,821.60		2,780.92	8 114.36
IV	ओवरहेड्स								
	(i) प्रबंधन और प्रशासन ओवरहेड्स	1,258.56	1,289.52	1,321.24 3,869.32	1,985.23	1,834.50		1,934.05	5,753.78
	(ii) जनरल ओवरहेड्स	537.56	550.78	564.33 1,652.67	300.48	221.71		215.31	737.51
	(iii) प्रारंभिक व्यय और अधिम भूगतान राइट-ऑफ़	37.03	37.03	37.03 111.09	37.03	37.03		37.03	111.09
	योग (i से iii)	1,833.15	1,877.33	1,922.60 5,633.08	2,322.74	2,093.24		2,186.40	6,602.38
V	प्रचालन अधिक्य/ (आटा) (I) - (II) - (III) - (IV)	1,465.62	3,344.27	2,578.34 7,388.23	7,975.01	6,191.24		1,632.77	15,799.02
VI	वित्त और विविध आय (एफएमआई)								
	(i) परिसंपत्तियों की विक्री पर लाभ	-	-	-	0.45	0.55		-	1.00
	(ii) अन्य परिचालन आय	99.80	99.80	99.80 299.40	-	-		-	-
	(iii) स्ट्रैप की विक्री				182.35	152.66		115.51	450.52
	(iv) एनईआईएस की आय				-	824.68		185.33	1,010.01
	(V) अन्य (सुरक्षा जमा से वापसी का क्रेडिट)	0.87	0.96	1.07 2.90	0.87	0.9	1.07		2.90
	योग (i से v)	100.67	100.76	100.87 302.30	183.67	978.85	301.91		1,464.43
VII	वित्त और विविध व्यय (एफएमआई)								
	(i) बैंक प्रमार	9.60	10.10	10.60 30.30					-
	योग (i से iv)	9.60	10.10	10.60 30.30					-
VII	एफएमआई कम एफएमई (VI) - (VII)	91.07	90.66	90.27 272.00	183.67	978.85	301.91		1,4 4.43
IX	व्याज और कर से पहले अधिशेष (V) + (VII)	1,556.69	3,434.93	2,668.61 7,660.23	8,158.68	7,170.09	1,934.68		17,263.45
X	नियोनित पूरी	30,181.10	32,489 75	32,395.50 95,066.35	31,626.88	29,996.53	27,180.57		88,803.99
XI	आरओसीई - अधिकतम अनुज्ञेय @ 16%	4,828.98	5,198.36	5,183.28 15,210.62	5,060.30	4,799.45	4,3 8.89		14,208.64
XII	शुद्ध अधिशेष / (आटा) (IX) - (XII)	(3,272.29)	(1,763.43)	(2,514.67) (7,550.39)	3,098.37	2,370.65	(2,414.21)		3,054.81

XIII	ऑपरेटिंग आय के% (XII / 1% में) के रूप में शुद्ध अधिशेष / (कमी)	-18.93%	-8.8 %	-12.68%	-13.26%	10.25%	8.50%	-14.13%	4.06%
XIV	अतिरिक्त पिछले अधिशेष का समायोजन	1,589.28	1,589.27	1,589.27	4,767.82				
	(ए) एजी की राय के बाद 2014-15 (फरवरी 2015) से शुरू हुई पाच साल की अवधि में समायोजन के लिए, पिछले तीन वर्षों 2010-11 से 2012- 13 में अंजित अतिरिक्त अतिरिक्त अधिशेष का 50%।	701.04	701.04	701.04	2,103.12				-
	(ख) परिचालन लागत और आत्मोसीर्व की अंतिम टैरिफ़ में छूट, इन- मोशन वैगन प्रणाली, एकल रेल लाइन के साथ सबधित परिसंपत्तियों के सकल बर्जांक में परिवर्तन के प्रदर्भ में अनुमति दी गई है, जो संबंधित परिसंपत्तियों के साथ 31मार्च 2012 तक होनी चाहिए। लेकिन एसडब्ल्यूपीएल द्वारा मथापित नहीं किया गया। इसलिए, चालू चक्र में 2014-15 (फरवरी 2015) और 2015-16 से शुरू होने वाले पाच वर्षों में 100% समायोजन के लिए विचार किया गया और ये प्र की बाद के टैरिफ़ चक्र में समायोजित किया गया। [जनवरी 2015 के आदेश में यह अधिशेष, वर्ष 2014- 15 और 2015-16 में समायोजित किया गया था।]	226.93	226.93	226.93	680.79				-
(सी) 2014-14 और 2015-16 में वर्ष 2013-14 के लिए 100% वास्तविक अधिशेष									
XV	पिछले अधिशेष के समायोजन के बाद शुद्ध अधिशेष / (घाटा)	(755.04)	753.81	2.57	1.34	3,098.37	2,370.65	(2,414.21)	3,054.81
XVI	% परिचालन आय के रूप में शुद्ध अधिशेष (घाटा)	-4.37%	3.80%	0.01%	0.00%	10.25%	8.50%	-14.13%	4.06%
XVII	% परिचालन आय में औसत शुद्ध अधिशेष / घाटा	0.0%				4.1%			

अनुलग्नक(क)

फार्म- 4

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित दरों के प्रस्तावित पैमाने पर राजस्व अनुमान

(ए) यातायात विवरण

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक आगम/निर्गम			कुल	औसत
		व1 (2016-17)	व2 (2017-18)	व3 (2018-19)		
(1).	विवरण	1,17,47,065	1,06,05,899	52,48,022	2,76,00,986	92,00,329
	कुल वास्तविक यातायात (मीट्रिक टन / टीईयू में) संभाला					
(2).	वास्तविक पोत यातायात					
(i).	जहाजों की संख्या संभाला	193	156	107	456	152
(ii).	कुल सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी)	84,57,161	81,62,571	41,74,285	2,07,94,017	69,31,339

(ख). राजस्व आकलन

	30,000 जीटी तक	0.0303		0.0348	यूएस\$ / जीटी / घंटा		-	-	15%
	30,001 जीटी और ऊपर	0.0358		0.0412	यूएस\$ / जीटी / घंटा	69,45,954	6,459	15%	
	तटीय जहाज								
	30,000 जीटी तक	0.83		0.95	भा.मुद्रा / जीटी / घंटा		-	-	15%
	30,001 जीटी और ऊपर	0.96		1.10	भा.मुद्रा / जीटी / घंटा	14,00,249	514	15%	
	चाटभाड़ा								
	कोयला	38.34	चाट भाड़ा प्रभारों के खंड क का भाग-	48.00	भा.मुद्रा/एमटी	चाट भाड़ा प्रभारों के भाग- का खंड 'क'	66,51,185	3,193	24%
	कोयला (तटीय)	23.00		29.00			3,50,062	102	24%
	कोक	57.51		71.00	भा.मुद्रा/एमटी		5,88,879	418	24%
	चूना पत्थर	12.78		16.00	भा.मुद्रा/एमटी		7,56,077	121	24%
	स्टील के उत्पाद	38.34		48.00	भा.मुद्रा/एमटी		8,54,126	410	24%
	कार्गो हैंडलिंग शुल्क								
	कोयला	128.69	कार्गो संबंधी प्रभारों के खंड ख का भाग-	160.00	भा.मुद्रा/एमटी	कार्गो संबंधी प्रभारों के भाग- का खंड 'ख'	66,51,185	10,642	24%
	कोयला (तटीय)	77.19		96.00	भा.मुद्रा/एमटी		3,50,062	336	24%
				36					
	कोक	182.88		227.00	भा.मुद्रा/एमटी		5,88,879	1,337	24%
	चूना पत्थर	169.34		210.00	भा.मुद्रा/एमटी		7,56,077	1,588	24%
	स्टील के उत्पाद	203.20		252.00	भा.मुद्रा/एमटी		8,54,126	2,152	24%
	भंडारण आय (मुक्त अवधि के बाद पहले 5 दिन)								
	कोयला	10.00	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-	12.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के भाग- का खंड ग	14,00,249	168	24%

	लोहे के छर्रे	10.00	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग ॥	12.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	-	-	24%
	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	5.00		6.00	भा.मुद्रा/एमटी		4,27,063	26	24%
	(छठे दिन से दसवें दिन के लिए दर)			37					
	लोहे के छर्रे	25.00	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग ॥	31.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	-	-	24%
	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	10.00		12.00	भा.मुद्रा/एमटी		2,56,238	31	24%
	(र्यारहवें दिन बीसवें दिन के लिए दर)								
	लोहे के छर्रे	50.00	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग ॥	62.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	-	-	24%
	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	25.00		31.00	भा.मुद्रा/एमटी		1,70,825	53	24%
	(पहले दिन बीस के लिए दर)								
	लोहे के छर्रे	100.00	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग ॥	124.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	-	-	24%
	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	50.00		62.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24%
	धूल का दमन								
	कोयला	2.75	धूल संपीड़न प्रभार के खंड घ का भाग ॥	3.40	भा.मुद्रा/एमटी	धूल संपीड़न प्रभारों के भाग ॥ का खंड 'घ'	70,01,247	238	24%
	कोक	2.75		3.40	भा.मुद्रा/एमटी		5,88,879	20	24%
	चूना पत्थर	2.75		3.40	भा.मुद्रा/एमटी		7,56,077	26	24%
	प्रस्तावित टैरिफ पर कुल अनुमानित राजस्व						28,750		

अनुलग्नक-III (ख)

फार्म-4

एसडब्ल्यूपीएल द्वारा प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरमानों पर राजस्व अनुमान

(क). आगम/निर्गम विवरण

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक आगम-निर्गम			कुल	औसत
		व1 (2016-17)	व2 (2017-18)	व3 (2018-19)		
(1).	कुल वास्तविक प्रहस्तित आगम निर्गम(भी. टन/टीईयू में)	1,17,47,065	1,06,05,899	52,48,022	2,76,00,986	92,00,329
(2).	पोतों का वास्तविक आवागमन					
(i).	प्रहस्तित पोतों की संख्या	193	156	107	456	152
(ii).	कुल सकल पंजीकृत टन भार (जीआरटी)	84,57,161	81,62,571	41,74,285	2,07,94,017	69,31,339

(ख). राजस्व आकलन

क्रम सं.	विवरण	मौजूदा आगम-निर्गम	अनुसूची का संदर्भ और मौजूदा दरमानों में क्रम सं.	प्रस्तावित प्रशुल्क	लगान इकाई	अनुसूची का संदर्भ और प्रस्तावित दरमानों में क्रम सं.	वर्ष 1, 2 और 3 के दौरान बीजोटी प्रचालक द्वारा वास्तविक आगम निर्गम का औसत	प्रस्तावित प्रशुल्क पर राजस्व आकलन(रु. लाखों में)	%मौजूदा प्रशुल्क पर प्रतिशत वृद्धि (गणितीय त्रुटि के कारण प्रहस्तन प्रभारों के लिए सुधार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 5*8	(10) = (5-3)/3
क.	टैरिफ आइटम								
	वर्थ भाड़ा शुल्क								
	वर्थ 5 पर								
	विदेशी जहाज	0.0138	पोत सर्वंधी प्रभारों के भाग-। का खंड ग	0.01550	यूएसडी/जीटी/घंटा	पोत सर्वंधी प्रभारों के भाग-। का खंड ग	8,54,126	593	12.50%
	तटीय जहाज	0.37		0.42	भा.मुद्रा/जीटी/घंटा		-	-	12.50%
	वर्थ 6 पर								
	विदेशी जहाज								
	30,000 जीटी तक	0.0303		0.0341	यूएसडी/जीटी/घंटा				12.50%

30,001 जीटी और ऊपर	0.0358		0.0403	यूएसडी/जीटी/बंदा		-	-	12.50%
तटीय जहाज			69,45,954		6,318			
30,000 जीटी तक	0.83		0.93	भा.मुद्रा/जीटी/बंदा		-	-	12.50%
30,001 जीटी और ऊपर	0.96		1.08	भा.मुद्रा/जीटी/बंदा		14,00,249	504	12.50%
चाटभाड़ा								
कोयला	38.34	चाट भाड़ा के भाग ॥ का खंड क	48.00	भा.मुद्रा/एमटी	चाट भाड़ा के भाग ॥ का खंड क	66,51,185	3,193	25.20%
कोयला (तटीय)	23.00		28.80	भा.मुद्रा/एमटी		3,50,062	101	25.22%
कोक	57.51		71.00	भा.मुद्रा/एमटी		5,88,879	418	23.46%
चूना पत्थर	12.78		16.00	भा.मुद्रा/एमटी		7,56,077	121	25.20%
स्टील उत्पाद	38.34		48.00	भा.मुद्रा/एमटी		8,54,126	410	25.20%
कार्गो हैंडलिंग शुल्क								
कोयला	128.69	कार्गो संवंधी प्रभारों के भाग ॥ का खंड ख	160.00	भा.मुद्रा/एमटी	कार्गो संवंधी प्रभारों के भाग ॥ का खंड ख	66,51,185	10,642	24.33%
कोयला (तटीय)	77.19		96.00	भा.मुद्रा/एमटी		3,50,062	336	24.37%
कोक	182.88		227.00	भा.मुद्रा/एमटी		5,88,879	1,337	24.13%
चूना पत्थर	169.34		210.00	भा.मुद्रा/एमटी		7,56,077	1,588	24.01%
स्टील के उत्पाद	203.20		252.00	भा.मुद्रा/एमटी		8,54,126	2,152	24.02%
			39					
भंडारण आय								
(मुक्त अवधि के बाद पहले 5 दिन)								
कोयला	10.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	12.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-॥	14,00,249	168	20.00%
कोक	15.00		19.00	भा.मुद्रा/एमटी		1,17,776	22	26.67%
चूना पत्थर	10.00		12.00	भा.मुद्रा/एमटी				20.00%

						1,51,215	18	
कोई और सूखा बल्क	15.00		19.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	26.67%
(ल्ठे दिन से दसवें दिन के लिए दर)								
लोहे के छर्रे	25.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-II का खंड ग	31.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-II	7,00,125	217	24.00%
धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कागों	40.00		50.00	भा.मुद्रा/एमटी		58,888	29	25.00%
	25.00		31.00	भा.मुद्रा/एमटी		75,608	23	24.00%
(र्यारहवें दिन से बीसवें दिन के लिए दर)	40.00		40.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	0.00%
लोहे के छर्रे								
धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कागों								
कोयला	50.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-II का खंड ग	62.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-II	-	-	24.00%
कोक	75.00		93.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24.00%
चूना पत्तथर	50.00		62.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24.00%
कोई अन्य ड्राइ बल्क	75.00		93.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24.00%
(21वें दिन से आगे)								
कोयला	100.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-II का खंड ग	124.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-II	-	-	24.00%
कोक	150.00		186.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24.00%
चूना पत्तथर	100.00		124.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24.00%
कोई अन्य ड्राइ बल्क	150.00		186.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24.00%
निशुल्क अवधि के पांचदिन के पश्चात								
लौहछर्रे	10.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-II का खंड ग	12.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-II	-	-	20.00%

	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	5.00		6.00	भा.मुद्रा/एमटी		4,27,063	26	20.00%
	(छठे दिन से दसवें दिन के लिए दर)								
	लौह छर्रे	25.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	31.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-॥	-	-	24.00%
	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	10.00		12.00	भा.मुद्रा/एमटी		2,56,238	31	20.00%
	(11वें दिन से आगे 20वें दिन तक)								
	लौह छर्रे	50.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	62.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-॥	-	-	24.00%
	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	25.00		31.00	भा.मुद्रा/एमटी		1,70,825	53	24.00%
	(21वें दिन से आगे)								
	लौह छर्रे	100.00	भू-किराया प्रभारों के भाग-॥ का खंड ग	124.00	भा.मुद्रा/एमटी	भू-किराया प्रभारों के खंड ग का भाग-॥	-	-	24.00%
	धातु उत्पाद, स्टील कॉइल, स्लैब और अन्य सामान्य थोक कार्गो	50.00		62.00	भा.मुद्रा/एमटी		-	-	24.00%
	धूल का दमन								
	कोयला	2.75	धूल दमन प्रभारों के भाग ॥ का खंड घ	3.40	भा.मुद्रा/एमटी	धूल दमन प्रभारों के खंड घ का भाग ॥	70,01,247	238	23.64%
	कोक	2.75		3.40	भा.मुद्रा/एमटी		5,88,879	20	23.64%
	चूना पत्थर	2.75		3.40	भा.मुद्रा/एमटी		7,56,077	26	23.64%
	प्रस्तावित प्रशुल्क दर पर आकलित कुल राजस्व							28,584	

अनुलग्नक-IV

साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड
दरमान

1. परिभाषाएँ – सामान्य

इन वर्तमान दरमानों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो निम्न परिभाषाएँ लागू होंगी :

- (i) "प्रति दिन" का अभिप्रायः प्रति कैलेंडर दिवस है यदि अन्य था उल्लेख न किया गया हो।
- (ii) "एसडब्ल्यूपीएल" का अभिप्राय साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड भारतीय कंपनी इसके उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों से है।
- (iii) "पत्तन" का अभिप्राय मुरमुगांव पत्तन न्यास (एमओपीटी) जिसमें टर्मिनल का अभिप्राय साउथ वेस्टन पोर्ट लिमिटेड एसडब्ल्यूपीएल से होगा जो अब या इसके बाद साउथ वेस्ट पोर्ट लिमिटेड (एसडब्ल्यूपीएल) द्वारा प्रचालित किया जाएगा।
- (iv) "तटीय पोत" का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाईसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (v) "तटीय कार्गो" का अभिप्राय उस कार्गो से है जिसे कोई पोत एक भारतीय पत्तन से लदान के बाद दूसरे भारतीय पत्तन व इसके विपरीत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाईसेंस के अधीन व्यापार कार्य में नियोजित है।
- (vi) "विदेशी कार्गो" का अर्थ है तटीय कार्गो के अलावा अन्य कार्गो।
- (vii) "विदेशगामी पोत" का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।
- (viii) "टन" या "एमटी" का अभिप्राय एक मीट्रिक टन या 1,000 किलोग्राम या एक क्यूबिक मीटर होगा।

2

सामान्य नियम व शर्तेः

- (i) पोत संबंधी प्रभार लगाने के प्रयोजन से "विदेशगामी" अथवा "तटीय" श्रेणी में वर्गीकृत करने के लिए पोत का दर्ज वर्गीकरण, जैसा सीमा शुल्क विभाग अथवा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी इसके प्रमाणन में दिया गया होगा, निर्णायक घटक होगा और कार्गो की प्रकृति अथवा उसके उदगम की, इस प्रयोजन से कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।
- (ii) पोत संबंधी प्रभार (वीआरसी)लगाने के लिए पोत वर्गीकरण संबंधी पद्धति :
 - (क) सामान्य ट्रेडिंग लाईसेंस रखने वाला भारतीय ध्वज का विदेशगामी पोत सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चलन कर सकता है। ऐसा पोत जो तटीय चलन में परिवर्तन करता है उसे भारतीय पत्तन पर प्रथम बार पहुंचने पर सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर, आगे भारतीय तट पर चलन करते समय तक, सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।
 - (ख) विदेशी ध्वज का, विदेशगामी पोत, परिवहन निदेशक द्वारा जारी निश्चित अवधि के लाईसेंस और सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चलन में परिवर्तित किया जा सकता है।
- (iii) पोत संबंधी प्रभारों के लिए रियायती तटीयःदर के मापदंड-दर और विदेशी-
 - (क) परिवर्तन संबंधी ऐसे मामलों में, पोत पर तटीय सामान का लदान आरंभ होते ही लादानपत्तन द्वारा - तटीय दरें प्रभार्य हो जाएंगी।
 - (ख) परिवर्तन के ऐसे मामलों में भारतीय पत्तन की अंतिम पुकार पर प्रचलन कार्य पूरा होने के समय तक ही तटीय दरें प्रभार्य रहेंगी। उसके तुरत पश्चात प्रेषणकर्ता पत्तन द्वारा विदेशगामी दरें प्रभार्य होंगी।
 - (ग) पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा जारी तटीय लाईसेंस धारक पूर्ण भारतीय तटीयः समर्पित पोत को, तटीय दरों के लिए किसी अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iv). रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधी प्रभार (सीआरसी) के लिए मापदंडः
 - (क) विश्व स्तर पर सामान्य कारोबारी व्यापारिक लाईसेंस धारक भारतीय/ध्वत के किसी विदेशगामी पोत द्वारा तटीय प्रचालन के लिए के लिए प्रहस्तन प्रभारों हेतु तटीय दरें लागू की जानी चाहिएं (एचसी) से भंडारण /को क्लेल को/पोत से तट तक और क्वें से अर्थात् सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर यार्ड तक स्थानान्तरण के लिए, वार्फेज सहित, तटीय दरें, निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में लागू होंगी :-

- (i). तटीय चलन में परिवर्तित और तटीय कार्गो ले जाने के लिए पोत किसी भी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए।
- (ii). तटीय चलन में परिवर्तित नहीं परंतु किसी भी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारत *ीय पत्तन को तटीय कार्गो ले लाने वाले पोत।
- *केंद्रीय सीमा कर और शुल्क परिपत्र सं 15/2002-सी दिनांक .श. 25 फरवरी 2002 के अनुसार तटीय कार्गो का भारतीय घ्वज वाले विदेशगामी पोत में बिना कस्टम परिवर्तन के भारत में एक पत्तन से दूसरे पत्तन को लाना-ले/ जाना अनुमत्त है।
- (xv). पोत परिवहन महानिंदेशालय द्वारा जारी निश्चित अवधि प्रमाण पत्र तथा सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चलन में परिवर्तित किसी एक भारतीय पत्तन पर लादे गए तथा अन्य भारतीय पत्तन पर गमन के लिए लक्षित कार्गो कंटेनर के लिए/तटीय लागू दरें प्रभार्य होंगी।
- (v). पोत संबंधी प्रभार दरें जहां कहीं भी अमेरिकी डालर में निर्धारित हैं, वहां ये प्रभार दरें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या इससे संबद्ध बैंक या किसी सर्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा समयसमय पर अधिसूचित बाजार - भाव की दर पर अमेरिकी मुद्रा में परिवर्तित करने के पश्चात, भारतीय मुद्रा में ही ली जाएगी। मुद्रा संबंधी परिवर्तन हेतु गणना के लिए तिथि, पोत के पत्तन में प्रवेश की तिथि ही मानी जाएगी।
- (vi). पोत के 30 दिन से अधिक पत्तन में ठहरने पर, प्रत्येक 30 दिन के पश्चात विनिमय दर की नियमित तौर पर समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में, समीक्षा के समय प्रचलित उचित विनिमय दर के संदर्भ में बिलों में तदनुसार, परिवर्तन किया जाएगा।
- (vii). (क) क्रूड आयल, लौह अयस्क और लौह पल्ले सहित तापीय कोयला और पीओएल को छोड़ कर, सभी तटीय कार्गो के कार्गो संबंधी प्रभार सामान्य कार्गो कंटेनर संबंधी प्रभारों के/60 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- (ख) कार्गो संबंधी प्रभारों के मामले में पोत तट स्थानान्तरण और क्रेसेको स्थानान्तरण /को भंडारण यार्ड से/ के लिए वार्फेज सहित सभी संबंधित प्रहसूतन प्रभारों हेतु रियायती दरें प्रभार्य होंगी।
- (ग) विदेशी पत्तन का एक कार्गो से पत्तन 'ख' पर अनुवर्ती पोतांरण हेतु पत्तन 'क' पर पहुंचने पर, उसके लिए तटीय चलन से प्रासंगिक रियायती प्रभार लागू होंगे। अन्य शब्दों में, उन पोतों को भारतीय पत्तन सेको कार्गो/ओ लाने लेजाने के लिए तटीय चलन की अनुमति होगी और वे रियायत के पात्र होंगे।
- (घ) तटीय कार्गो/पोत संबंधी प्रभार भारतीय मुद्रा में मूल्यवर्गित तथा संग्रहित किए जाएंगे।
- (viii) देयता संगणन के लिए, भार की इकाई 1 टन या 1000 कि.ग्र., आयतन की इकाई 1 क्यूबिक मीटर और तरल पदार्थों के परिमाण क्षमता की इकाई 1000 लिटर होगी।
- (ix) समग्र कुल भार के परिमापन या किसी एक मद के परिमाण के लिए/0.5 तक का भिन्नातमक दशमलव अंश 0.5 इकाई माना जाएगा और (यूनिट)0.5 इकाई(यूनिट)या और उससे अधिक अंश को पूरा एक इकाई (यूनिट) माना जाएगा, वर्तमान अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।
- (x) विलंबित अदायगियों/वापसियों पर ब्याज:
- (क) उपयोक्ता, इन दरमानों के तहत विलंबित भुगतानों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा। इसी प्रकार, एसडब्ल्यूपीएल विलंबित वापसियों पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।
- (ख) दंडात्मक ब्याज की दर 15.00 प्रतिशत होगी। दंडात्मक ब्याज की यह दर एसडब्ल्यूपीएल और पत्तन दोनों पर एक समान लागू होगी।
- (ग) उपयोक्ता द्वारा भुगतान में विलंब की गिनती, एसडब्ल्यूपीएल द्वारा बिल के पेश करने की तिथि से 10 दिन बाद से आरंभ हो जाएगी लेकिन यह प्रावधान उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जिनमें महापत्तन न्यास अधिनियम के अनुसार प्रभार का भुगतान सेवाएं लेने से पहले करने का उल्लेख किया गया है और/या दरमानों में प्रभारों का अग्रिम भुगतान निर्धारित है।

- (घ) धन वापसी में देरी सेवाओं के पूरा होने के या उपभोगकर्ताओं से सभी जरूरी दस्तावेजों को लेने के 20 दिन बाद, जो कोई भी बाद में हो, संगणित किया जायेगा।
- (xi) हिसाब किये गये सभी किराये भाड़े को प्रत्येक बिल के कुल योग पर अगले उच्च रूपये तक शुन्यान्तकपूर्णांतक/ किया जायेगा।
- (xii) (क) दरों के पैमाने में निर्धारित दरें अधिकतम सीमा स्तर की है, इसी प्रकार छूट गृहमूल स्तरों पर है। एसडब्ल्यूपीएल अगर यह चाहे तो निम्न दरों पर चार्ज कर सकता है या/ उच्च छूट की अनुमति दे सकता है।
 (ख) अगर यह तर्कसंगति प्रति यूनिट दर में उपभोक्ता को राहत मिलती है व दरों के पैमाने में निर्धारित यूनिट दरें ऊपरी सीमा को पार नहीं करतीं तो एसडब्ल्यूपीएल, दरों के पैमाने में निर्धारित दरों के इस्तेमाल को शासित करने वाली निर्धारित शर्तों को अगर यह चाहे तो तर्कसंगत कर सकता है।
 (ग) एसडब्ल्यूपीएल द्वारा इन न्यूनतम दरोंया इन दरों के प्रयोजन को श/ासित करने वाली शर्तों के तर्कसंगतिकरण को जनता को अधिसूचित करना चाहिए तथा इन न्यूनतम दरों में या इन दरों के प्रयोजन को शासित करने वाली शर्तों में बदलावों, बर्तने नयी दरें टीएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से ज्यादा न हो, को अधिसूचित करना जारी रखा जाना चाहिए।
- (xiii). उपयोगकर्ताओं एसडब्ल्यूपीएल के कारण तर्कसंगत स्तर के पार देरी के लिए किराया भाड़ा भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।
- (xiv). पूर्वी तट पर एक भारतीय बंदरगाह और पश्चिमी तट पर एक अन्य भारतीय बंदरगाह या इसके विपरीत, श्रीलंका के प्रादेशिक जल के माध्यम से एक जहाज द्वारा तटीय वस्तुओं को पहुँचाया जाता है, चाहे और बदले में पोत के परिवर्तन के बीच में, श्रीलंका में किसी भी बंदरगाह पर जाए या नहीं, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की 11 मई 2018 की अधिसूचना संख्या.38 / 2018-सीमा शुल्क (एनटी) के संदर्भ में पोत संबंधी शुल्कों और कार्गों संबंधित शुल्कों में रियायत के लिए पात्र होंगे।
- (xv). तटीय माल पूर्वी तट पर एक भारतीय बंदरगाह और भारत में एक नदी पर बंदरगाह या इसके विपरीत, एक जहाज द्वारा बांग्लादेशी पानी से गुजरने वाले मार्ग के माध्यम से और पोत के परिवर्तन के बिना में परिवहन करता है तो अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एनटी) 11 मई 2018 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड पोत संबंधी शुल्कों और कार्गों संबंधित शुल्कों में रियायत के पात्र होंगे।
- (xvi). दरमान, संबंधित वर्ष की पहली जनवरी से 31 दिसंबर के बीच होने वाले प्राधिकरण द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति के लिए स्वतः वार्षिक अनुक्रमण के अध्याधीन हैं। अगला वार्षिक इंडेक्सेशन 1 मई, 2020 से होगा। एसडब्ल्यूपीएल द्वारा सूचकांकित दरमान एमओपीटी, संबंधित उपयोगकर्ताओं और प्राधिकरण को सूचित किये जाएंगे।

भाग I - पोत संबंधी प्रभार

खण्ड-क - पत्तन देयता एवं खण्ड-ख - पायलेटेज संबंधी प्रशुल्क

ये सेवाएं, उनके लिए अनुमोदित दरमानों के अनुसार मुरमुगांव पोर्ट न्यास द्वारा एसडब्ल्यूपीएल के वर्थ सं .5क व 6क में प्रवेश करने वाले पोतों को दी जायेगी। ये प्रभार पोतों के स्वामियों एजेन्टों द्वारा सीधे मुरमुगांव पत्तन न्यास को देय होंगे। /मालिकों/

खण्ड-ग - वर्थ किराया भाड़ा

वर्थ संख्या 5क व 6क के लिए, पोतों के स्वामियोंपीएलएजेन्टों द्वारा एसडब्ल्यू/मालिकों/ को देय वर्थ किराया भाड़ा, निम्नलिखित दरों पर होगा।

वर्थ सं .5क

(अधिकतम एलओए 190 मीटर पोत के वर्थ संख्या 6क पर एलओए 225 मीटर के अन्य पोत के साथ)

क्रम सं.	पोत वर्ग	दर प्रति जी आर टी प्रति घंटा या उसका भाग	
		विदेशगामी पोत(यू एस \$ में)	तटीय पोत(रूपये में)
1.	सभी पोत	0.0155	0.42

बर्थ सं .6 क

मशीन द्वारा संचालित प्रणाली के साथ

क्रम सं.	पोत वर्ग	दर प्रति जी आर टी प्रति घंटा या उसका भाग	
		विदेश जाने वाले पोत(यू एस \$ में)	तटीय पोत (रूपये में)
1.	30,000 जीआरटी तक	0.0341	0.93
2.	30,001 जीआरटी और अधिक	0.0403	1.08

नोट:

- (1). बर्थ किराया भाड़ा बर्थ पर दी गई सेवाओं व सुविधाओं जैसे बर्थ का अधिपत्य, बर्थ पर समयोपरि कार्य, पोत द्वारा बोर्ड पर एकत्रित कूड़े को हटाने व उसे घाट पर भेजने, बर्थों को साफ करने, अग्रि शमन निगरानी इत्यादि शामिल है।
 - (2). उपरोक्त किराया-भाड़ा पोत के स्वामियों, मालिकों व एजेन्टों व अन्य प्रवेश कर रहे अथवा बर्थ पर या उसके, आसपास खड़े/तैरते पोत से प्रति जीआरटी प्रति घंटा या उसके भाग के लिए वसूल किया जाना है।
 - (3). विदेशगामी और तटीय पोत के मामले में प्रति बर्थ प्रभार्य किराया विदेशगामी पोत की स्थिति में यूएस \$ 662.00 प्रति पोत और तटीय पोत की स्थिति में रु. 17,717/- के हिसाब से है।
 - (4). बर्थ किराये की अवधि, बर्थ को पोत द्वारा आधिपत्य करने के समय से संगणित की जायेगी।
 - (5). कोई भी बर्थ किराया भाड़ा उस अवधि के लिए देय नहीं होगा जब लोडिंगअनलोडिंग संचालन कार्य /, खराबी या एसडब्ल्यूपीएल के कारण, एसडब्ल्यूपीएल की तटीय क्रेनोंमशीनी प्रहस्तन प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा / रहा हो।
 - (6).
 - (i) बर्थ किराया पोत द्वारा जलयात्रा की अपनी तैयारी के संकेत देने के 4 घंटे बाद बन्द हो जायेगा।
 - (ii) बर्थ किराये के बंद होने के लिए निर्धारित 4 घंटे की समय सीमा अनुकूल ज्वार की स्थिति की कमी, खराब मौसम व रात्रि नौचालन की कमी के कारण जहाज के प्रतीक्षा समय में शामिल नहीं होगा।
 - (iii) पोत के स्वामी/एजेन्ट को केवल अनुकूल ज्वार एंव मौसम दशाओं के अनुसार जलयात्रा की तैयारी के संकेत देंगे।
 - (iv) झूठे संकेत के लिए बर्थ किराया जुर्माना एक दिन)24 घंटे के बर्थ किराया भाड़ा के बराबर होगा।
- “झूठा संकेत” तब होगा जब पोत तैयारी का संकेत देता है व प्रत्याशा में पायलेट के लिए पूछता है जबकि इंजिन तैयार नहीं रहता या कार्गो संचालन पूर्ण नहीं किया जाता या पोत के अन्य किसी कारणवश पोत वर्थ से हटने के लिए तैयार न हों। यह जब पोत प्रतिकूल ज्वार, रात्रि नौचालन की कमी या विपरीत मौसम दशाओं के कारण जलयात्रा नहीं कर पाता तब की तों को शामिल नहीं करता। तैयारी के संकेत
- (7). बर्थ स 5क एवं 6क पर अनुज्ञेय गिटी हटाने का समय 3 घंटे होगा व उसके बाद, बर्थ किराया भाड़ा जुर्माना सामान्य बर्थ किराया भाड़े के 5 गुना वसूल किया जायेगा यह प्रति घंटा या उसके भाग तक घटाया जायेगा जो पोत के लिए प्रयोज्य है। यह बर्थ पर पोत के रुकने के सामान्य बर्थ किराया भाड़े के अलावा होगा।
 - (8). इन बर्थों पर दूसरे पोतों के ऑफसाइड पर खड़े पोतों द्वारा सामान्य बर्थ किराया भाड़ा का 50 प्रतिशत देय होगा।

- (9). लाइसेंस समझौते के प्रावधान प्राथमिकता वर्थीग व उस पर अगर कोई भाड़ा हो, शासित करेगी। जब कभी भी किसी पोत को प्राथमिकता वर्थीग दी जाती है, एक दिन (24 घंटे) के लिए वर्थ किराया भाड़ा के बराबर शुल्क या वर्थ पर वास्तविक रुकने की कुल अवधि के लिए संगणित वर्थ किराया भाड़ा का 75 प्रतिशत जो कोई भी ज्यादा हो वसूल किया जायेगा।
- (10). (i) पोत की बाहर निकलने में प्राथमिकता के लिए वर्थ पर रुकने की वास्तविक कुल अवधि के लिए एक दिन (24 घंटे) वर्थ किराया भाड़े के बराबर शुल्क या वर्थ किराया भाड़े का 100 % जो भी उच्चतम हो, वसूल की जायेगा।
- (ii) इसके अलावा पोत संबंधी का अन्दर/बाहर बदलाव भाड़ा उन पोतों से वसूल किया जायेगा जिन्हें बाहर निकलने की प्राथमिकता उपलब्ध करायी गयी है।
- (iii) वर्थ सं. 6क पर बाहर निकलने की प्राथमिकता तभी दी जायेगी जब 25000 मी.टन का कार्गोप्रति कार्य दिवस की लदान दर/निर्गमन पोत द्वारा रखे गये प्रतिरोधों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

भाग II - कार्गो संबंधी प्रभार

खण्ड-क

वर्थ सं. 5क व 6क पर घाट किराया भाड़ा (वार्फेज)

दर्शाये गये कार्गो की मात्रा पर जिसे सीमा शुल्क के साथ दायर प्रवेश विल में घोषित किया जाता है कार्गो के आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा नीचे निर्दिष्ट दरों पर, वर्थ सं. 5क व 6क पर कार्गो प्रहस्तन के लिए, घाट शुल्क प्रत्यक्ष रूप से एसडब्ल्यूपीएल को देय होगा:

क्रम सं	उत्पादों का विवरण	इकाई	दर आयात व निर्यात के लिए (रूपये में)	
			विदेशी कार्गो	तटीय कार्गो
1.	कोयला (प्रकार थर्मल कोयले को छोड़कर सभी)	एम टी	48.00	28.80
2.	तापीय कोयला	एम टी	48.00	48.00
3.	धातुकर्म कोक लकड़ी का कोयला /कोक /	एम टी	71.00	42.60
4.	चूना पत्थर	एम टी	16.00	9.60
5.	लौह अयस्क छर्रे	एम टी	48.00	48.00
6.	धातु उत्पाद, इस्पात द्वायल , स्लेव्स	एम टी	48.00	33.60
7.	अन्य कोई बल्क कार्गो जो ऊपर निर्दिष्ट हों	एम टी	48.00	33.60

घाट अनुसूची के तहत किसी भी कार्गो को "अनिर्दिष्ट" श्रेणी में वर्गीकृत करने से पहले, प्रासंगिक कस्टम वर्गीकरण को यह पता लगाने के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए कि क्या कार्गो को घाट अनुसूची में उल्लिखित किसी भी निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

खण्ड – ख

कार्गो प्रहस्तन प्रभार

वर्थ सं. 5क व 6क पर दर्शाये गये कार्गो पर कार्गो प्रहस्तन प्रभार, कार्गो के आयातक या निर्यातक द्वारा निम्नलिखित दर पर सीधे एसडब्ल्यूपीएल को देय होगा:

वर्थ सं. 5क पर

क्रम सं.	उत्पादों का विवरण	इकाई	दर:आयात व निर्यात के लिए (रूपये में)
----------	-------------------	------	--------------------------------------

			विदेशी कार्गों	तटीय कार्गों
1.	लौह अयस्क छर्रे	एम टी	252.00	252.00
2.	धातु उत्पाद, इस्पात ब्रायल , स्लेब्स	एम टी	252.00	151.20
3.	अन्य कोई बल्क कार्गों जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं	एम टी	241.00	144.00

बर्थ सं .6क पर

क्रम सं.	उत्पादों का विवरण	इकाई	दर :आयात व निर्यात के लिए (रूपये में)	
			विदेशी कार्गों	तटीय कार्गों
1.	कोयला (थर्मल कोयले को छोड़कर सभी प्रकार)	एम टी	160.00	96.00
2.	तापीय कोयला	एम टी	160.00	160.00
3.	धातुकर्म कोक लकड़ी का कोयला /कोक /	एम टी	227.00	136.20
4.	चूना पत्थर	एम टी	210.00	126.00
5.	लौह अयस्क छर्रे	एम टी	252.00	252.00
6.	धातु उत्पाद, इस्पात ब्रायल , स्लेब्स	एम टी	252.00	151.00
7.	अन्य कोई बल्क कार्गों जो ऊपर निर्दिष्ट हों	एम टी	238.00	143.00

नोट:

- (1) बर्थ सं .5क पर कार्गों प्रहस्तन किराया भाड़ा निम्नलिखित सेवाओं के लिए होगा ।
 - पोत्त से कार्गों को बर्थ पर उतारना अथवा विलोमतः,
 - पोत बर्थ से एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड गमनागमन अथवा विलोमतः,
 - एसडब्ल्यूपीएल के अन्दर गमनागमनः,
 - रेलवे बैगन से उत्तरायी अथवा विलोमतः,
- (2) बर्थ सं .6क पर, कार्गों प्रहस्तन किराया भाड़ा निम्नलिखित सेवाओं के लिए होगा।
 - पोत से कार्गों को बर्थ पर उतारना अथवा विलोमतः,
 - पोत बर्थ से एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड गमनागमन अथवा विलोमतः,
 - एसडब्ल्यूपीएल स्टैकयार्ड के अन्दर गमनागमन,
 - रेलवे बैगनों पर रेल द्वारा सामान भेजने के लिए लदान अथवा विलोमतः।
- (3) अनुसूची में निर्धारित उपरोक्त प्रहस्तन भाड़े में बैगनों को तारपोलिन/प्लास्टिक आवरण से ढकना शामिल नहीं है।
- (4) डन-एंजिंग व लैशिंग की (उचित मजदूर व सामान लगाकर) पोत के मालिक की संतुष्टि तक उपयोगकर्ता द्वारा अपने खर्च पर व्यवस्था की जायेगी।
- (5) कार्गों प्रहस्तन किराया भाड़े का 50 प्रतिशत कार्गों के प्रहस्तन के लिए प्राप्त होने से पहले देय होगा। कार्गों प्रहस्तन किराये भाड़े का शेष 50 प्रतिशत कार्गों के नौवहन/निकासी से पहले देय होगा।

खण्ड- ग

भू-किराया/भंडारण किराया भाड़ा

एसडब्ल्यूपीएल के स्टैकयार्ड में भंडारित कार्गों के लिए भंडारण किराया भाड़ा निम्न प्रकार से होगा:

1. आयात/आगम कार्गों के लिए भू-किराया/भंडारण किराया भाड़ा

(एसडब्ल्यूपीएल में शेष कार्गों के लिए, प्रति मीटन प्रति दिन. रूपयों में)

क्रम सं.	उत्पादों का विवरण	फ्री पीरियड के बाद शेष पहले पांच दिनों के लिए दर	छठे दिन से दसवें दिन के लिए दर	ग्यारहवें दिन से बीसवीं दिन के लिए दर	इक्कीसवें दिन से दर
1.	कोयला (सभी प्रकार)	12.00	31.00	62.00	124.00
2.	धातुकर्म कोक /(सभी प्रकार) कोक / लकड़ी का कोयला	19.00	50.00	93.00	186.00
3.	चूना पत्थर	12.00	31.00	62.00	124.00
4.	अन्य कोई ड्राई बल्क कार्गो जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है	19.00	40.00	93.00	186.00

नोट्स:-

- (1) पोत के कार्गो के पूर्ण उत्तरायी के या जब अन्तिम पार्सल उतारे जाने के बाद, तीन दिन की निशुल्क अवधि की अनुमति दी जायेगी, निशुल्क अवधि का हिसाब करने के लिए रविवार कस्टम द्वारा अधिसूचित छुट्टियों व टर्मिनलों के गैर कार्य दिवस अलग किए जायेंगे।
- (2) जमीन का किराया दिनों के परे कार्गो के रुकने के लिए रविवारों व निर्धारित निशुल्क भंडारण किराया भाड़ा नि/ कस्टम द्वारा प्रतिसूचित छुट्टियों समेत सभी दिनों के लिए देय होगा।
- (3) मुफ्त दिनों के परे 21 दिनों के बाद, आयातक, निर्यातक के तमाम लागत व परिणामों पर शेष कार्गो एसडब्ल्यूपीएल क्षेत्र के बाहर अन्य क्षेत्र में बदलाव किया जाना संभाव्य है।
- (4) जमीन का किराया भंडारण को वसूल करने के लिए दिवस प्रातः 7:00 बजे से अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक गिनी जायेगी।
- ॥ निर्यात/वहिर्गमी कार्गो के लिए जमीन का किराया/भंडारण किराया भाड़ा

(एसडब्ल्यूपीएल में शेष कार्गो के लिए में प्रति मीटन प्रतिदिन .

क्रम सं.	उत्पादों का विवरण	फ्री पीरियड के बाद शेष पहले पांच दिनों के लिए दर	छठे दिन से दसवें दिन के लिए दर	ग्यारहवें दिन से बीसवीं दिन के लिए दर	इक्कीसवें दिन से दर
1.	लौह पल्ले	12.00	31.00	62.00	124.00
2.	धातु उत्पाद, स्टील कायल, स्लेब और अन्य सामान्य बल्क कार्गो	6.00	12.00	31.00	62.00

नोट्स:-

- (1) निर्यात कार्गो के मामले में, पहले कार्गो की खेप प्राप्त होने के पहले दिन से निशुल्क सात दिवस अनुमेय होंगे, मुफ्त अवधि का हिसाब करने के लिए रविवार कस्टम द्वारा अधिसूचित छुट्टियां व टर्मिनलों के गैर कार्य दिवस अपवर्जित किये जायेंगे।
- (2) निर्धारित निशुल्क दिवसों के बाद, जमीन का किराया/भंडारण किराया भाड़ा जैसा कि ऊपर बताया गया है रविवारों व कस्टम द्वारा अधिसूचित छुट्टियों समेत सभी दिनों के लिए देय होगा।
- (3) निशुल्क 21 दिनों के बाद शेष कार्गो का एसडब्ल्यूपीएल क्षेत्र के बाहर निर्यातक के एकमात्र लागत व परिणामों पर अन्य क्षेत्र में बदलाव किया जाना संभाव्य है।
- (4) जमीन का किराया/भंडारण को वसूल करने के दिवस की गणना प्रातः 7:00 बजे से अगले दिन के प्रातः 7:00 बजे तक की जायेगी।

(5) अगर इक्कठा किया गया संपूर्ण कार्गो निशुल्क अवधि के अन्दर नहीं है व शेष कार्गो अगले पोत से निर्धारित/संबंधित किया जाता है अगली मुफ्त अवधि इस दावे के समर्थन में दस्तावेजीकरण के पेश करनी की तारीख से अनुमेय किया जायेगा। अन्यथा, उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित के अनुसार अचित प्रयोज्य दर पर जमीन का दंडात्मक किराया देय होगा।

खण्ड सी – सामान्य नोट्स :

- (1) कोई भी जमीन का किराया/भंडारण किराया भाड़ा उस अवधि के लिए देय नहीं होगा जब एसडब्ल्यूपीएल के कारण एसडब्ल्यूपीएल कार्गो प्रहस्तन की स्थिती में न हो तथा उपयोगकर्ताओं ने अनुरोध किया हो।

खण्ड – घ

धूल दमन प्रशुल्क

प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल के दमन के लिए छिँड़के गये पानी के लिए धूल दमन खर्चों कोयले, कोक व चूनापत्थर पर प्रकट मात्रा पर निम्नलिखित दरों पर बसूल किये जायेंगे :

कोयला, चूना-पत्थर व कोक के लिए ₹ 3.40 :प्रति मीट्रिक टन .

यह पोत से उतारने के चरण से एसडब्ल्यूपीएल स्टैकगार्ड पर भंडारण सहित कार्गो के रेलवे वैगनों में लदान तक बसूल किया जायेगा।

भाग III

अन्य सेवाएं

1. आगन्तुक प्रविष्टि पास:

	वार्षिक	मासिक	प्रतिदिन
(क).	प्रति प्रार्थना-पत्र	₹255.60	₹25.56
(ख).	प्रति प्रतिस्थापन	₹63.90	₹25.56

2. वाहन प्रविष्टि पास

प्रति प्रविष्टि - ₹ 95.85

नोट: वाहन प्रविष्टि शुल्क कार्गो को भेजने/प्रेषण करने के लिए एसडब्ल्यूपीएल वर्थों पर प्रवेश/छोड़ने वाले वाहनों से बसूल नहीं की जायगी।

3. फोटोग्राफी

(क).	फिल्म शूटिंग व फोटोग्राफी	₹10863.00 प्रतिदिन
(ख).	सामान प्रहस्तन करने के फोटो लेना	₹639.00 प्रतिदिन
(ग).	नाविक दल व अन्य का फोटो लेना	₹319.50 प्रतिदिन
(घ).	वीडियोग्राफी (संचालन गतिविधियों से संबंधित)	₹3195.00 प्रतिदिन

4. क्रेन किराया भाड़ा (प्रभार)

कार्गो प्रहस्तन के उद्देश्यों के अलावा उपयोग के लिए वर्थ सं .5क व 6क पर स्थापित एसडब्ल्यूपीएल के क्रेनों के लिए किराया भाड़ा निम्नलिखित दरों के अनुसार एसडब्ल्यूपीएल को सीधे देय होगा।

(क).	110/42 मी टन क्षमता वाली हार्बर मोबाईल हार्बर क्रेनों के लिए	₹31950.00 प्रति घंटा
(ख).	अन्य क्रेनों के लिए	₹19170.00 प्रति घंटा

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th December, 2019

No.TAMP/38/2019-SWPL In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal of the South West Port Limited for general revision of its Scale of Rates for Berth 5A and 6A in the Mormugao Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/38/2019-SWPL

South West Port Limited

Applicant

QUORUM:

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of November 2019)

This case relates to the proposal dated 24 July 2019 received from South West Port Limited (SWPL) for revision of its Scale of Rates (SOR) for Berth 5A and 6A in the Mormugao Port Trust (MOPT).

2.1. This Authority vide its Order No.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016 had revised the SOR of the SWPL based on the proposal filed by SWPL and following the erstwhile Tariff Guidelines, 2005 then applicable to SWPL. The SOR approved on 17 November 2016 was notified in the Gazette of India on 30 November 2016 vide Gazette No.433. The revised SOR came into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order notifying the SOR in the Gazette of India. In the said Order, this Authority had granted tariff increase of 27.80% in cargo handling charge and 10% in berth hire charge as against tariff increase of 34% and 17% sought by SWPL for the corresponding activities. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2019. A speaking Order passed by this Authority was notified in the Gazette of India on 06 January 2017 vide Gazette No.10.

2.2. In the context of the tariff Order dated 17 November 2016, the MOPT filed an application to review the said tariff Order dated 17 November 2016. However, the MOPT withdrew its review application.

3.1. The SWPL vide its letter dated 08 April 2019 had made a request to extend the validity of the existing tariff till 30 September 2019 or till the new tariff is notified whichever is earlier.

3.2. In this regard, it was brought to the notice of SWPL that we have vide our letter dated 8 November 2017 requested the SWPL to file a proposal based on actuals of 2016-17 and revise the tariff estimates and corresponding income and expenditure estimations for the years 2017-18 and 2018-19 latest by 30 November 2017 in pursuance of the decision of this Authority in para 13 (vii) (a) of the Order No.TAMP/40/2016- SWPL dated 17 November 2016. This was followed by reminder dated 5 March 2018. The SWPL did not respond, despite reminder. Instead of complying with the decision taken by this Authority and keeping silent on the request made to

SWPL by our letter, the SWPL sought extension of the validity of existing SOR. SWPL was requested to furnish the physical and financial performance for the year 2018-19 to process the SWPL letter dated 08 April 2019 seeking extension. The SWPL remained silent.

4. In the meantime, the MOS vide its letter No.PR-14019/20/2009- PG (Pt-IV) dated 5 March 2019 has issued Tariff Guidelines for BOT operators operating in all Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed this Authority to act accordingly with immediate effect. The Tariff Guidelines for BOT operators operating in Major Port Trust and previously governed by 2005 Tariff Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 7 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is notified in the Gazette of India vide Gazette No.244 dated 11 July 2019 after consultation with the Major Port Trusts and the concerned BOT Operators governed under the erstwhile Tariff Guidelines of 2005.

5.1. In this backdrop, the SWPL has filed its proposal dated 24 July 2019 following Tariff Policy, 2019 for general revision of its SOR. The SWPL has submitted the following:

- (i). The SWPL has prepared the proposal for fixation of tariff in accordance with the said Tariff Guidelines and Working Guidelines, in the formats and supporting documents as prescribed by the Tariff Authority for Major Ports. The proposed tariff will have a validity period of three years from 01 April 2019 to 31 March 2022.
- (ii). **Traffic:**
SWPL handled traffic of 11.75 MMT, 10.61 MMT & 5.25 MMT for the years 2016-17, 2017-18 & 2018-19. For consideration of Average Revenue Requirement (ARR) traffic for next tariff cycle is taken as average of previous three years actual i.e. 9.2 MMT.
- (iii). **Expenditure Projections:**
 - (a). **Operating expenses (excluding depreciation) :**
Operating expenses is taken as average of previous 3 years' actual expenses.
 - (b). **Depreciation:**
For tariff proposal, depreciation was calculated as per IGAAP and due adjustment is made in depreciation calculated as per Ind AS. Details given in Form-7.
 - (c). **Royalty:**
As per Clause 2.2 of the revised tariff guidelines of 2019, Royalty / Revenue share payable to the landlord port by the private operator will not be allowed as an admissible cost for tariff computation as decided by the Govt. in the Ministry of Shipping vide its Order No.PR-14019/6/2002-PG dated 29 July 2003. In those BOT cases where bidding process was finalised before 29 July 2003, the tariff computation will take into account royalty / revenue sharing as cost subject to maximum of the amount quoted by the next highest bidder for tariff fixation.

Accordingly, Royalty at 13.1% (being the second highest bid for the Tender) has been considered as admissible expenses for tariff computation.
 - (d). **Lease Rentals:**
This has been projected on the basis of the provisions of the L.A.
[The lease rental considered in the ARR calculation is based on actuals reported in the Audited Annual Accounts]
- (iv). **ARR:**
To arrive at ARR following assumption were taken:
 - (a). **Exchange rate:**

For calculating berth hire income INR / USD rate of `70 is considered.

(b).

Fixed Assets:

For consideration of Gross Fixed Assets, due adjustments were made on Fixed Assets reported in the Audited Annual Accounts based on Ind AS to arrive at Fixed Assets based on IGAAP.

(c).

Working Capital:

For consideration of working capital following assumptions were made:

(i). **Inventory:** Inventory consumption for FY 2018-19 was `325.70 lakh. For ARR calculation, 6 months average consumption i.e. `162.85 lakh is considered.

(ii). **Sundry debtors:** SWPL paid `867.76 lakh in advance to the Port Trust as License fee and lease rent. Annual average i.e. `433.88 lakh is included as Sundry Debtors for ARR calculation.

(iii). **Cash:** Annual expense, based on FY 2018-2019, of SWPL terminals is `13,244.44 lakh. For consideration of ARR, one month expense i.e. `1103.70 Lakh is taken as cash requirement for working capital.

(v).

Return on Capital Employed:

As prescribed in the Guidelines, Return on Capital Employed of 16% is considered.

(vi).

Indexation in the ARR:

To arrive at ARR with indexation, applicable WPI of 3.45% is considered.

(vii).

Proposed SOR:

Based on the calculation of ARR, it is proposed to increase tariff for SWPL terminals by 23%. Proposed SOR is furnished.

5.2. The SWPL has furnished detailed computation of ARR under Form-1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form-3 and other Forms as prescribed in the Working Guidelines. The Form-1 (ARR), Form-3 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement), Form-7 (Fixed Assets Statement as per IGAAP considered in ARR computation giving details of adjustments) have been duly certified by practicing Chartered Accountant.

(i).

A summary position of ARR computation furnished by SWPL is tabulated below:

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	24,021.16	23,605.00	16,819.02
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	239.73	279.60	21.84
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86
(2).	Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP			
(i).	Depreciation	(670.77)	(964.17)	(793.46)
(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed	(217.50)	(0.02)	(0.75)
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	(888.27)	(964.19)	(794.21)
(3).	Less Adjustments:			
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	(3,415.98)	3,554.06	(2,154.16)
(ii).	Interest on loans	(239.73)	(279.60)	(21.84)
(iii).	Provision for bad and doubtful debts	-	-	-

(iv).	Provision for slow moving inventory	-	-	-
(v).	Other provisions, if any	-	-	-
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	(3,655.71)	(3,833.65)	(2,176.00)
(4).	Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019	2,486.07	2,586.56	1,567.75
(5).	Total Expenditure after Total Adjustments (5=1+2+3+4)	22,202.98	21,673.32	15,438.40
(6).	Average Expenses of SI. No.5 = [Y1+Y2+Y3]/3			19,771.57
(7).	Capital Employed			
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)			48,602.09
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			172.75
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019			
	(a). Inventory			162.85
	(b). Sundry Debtors			2,704.74
	(c). Cash			1,103.70
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)			3,971.30
	(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)]			52,746.14
(8).	Return on Capital Employed 16% on SI. No.7(iv)			8,439.38
(9).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [(6)+(8)]			28,210.95
(10).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 @ 3.45% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0345			29,218.22
(11).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement			29,218.22
(12).	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at SI. No.11 above			29,082.00

- (ii). The SWPL has proposed across the board increase of 23% in Berth hire charges and in Cargo handling charges to meet the estimated ARR.
- (ii). The SWPL has in Form 4 furnished detailed working of revenue estimation for the existing tariff as well as the proposed tariff for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed tariff is `29,082.00 lakhs.

6.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of SWPL proposal dated 24 July 2019 was circulated vide our letter dated 1 August 2019 to the MOPT and concerned users/ user organisation seeking their comments.

6.2. In response, the Goa Chamber of Commerce and Industry (GCCI) and Hiralal & Co. vide their letters dated 16 August 2019 have furnished their comments which were forwarded to SWPL vide our letter dated 27 August 2019 as feedback information. The SWPL vide its email dated 21 August 2019 has furnished its reply.

6.3. The MOPT vide its email dated 23 September 2019 has forwarded a copy of letter dated 23 September 2019 addressed to SWPL in which MOPT has furnished its comments on the subject proposal which were forwarded to SWPL vide our letter dated 24 September 2019 as feedback information. The SWPL vide its email dated 02 September 2016 has furnished its comments on the comments of MOPT dated 23 September 2019.

7.1. A joint hearing in this case was held on 27 September 2019 at the MOPT premises. The SWPL made a brief Power Point presentation of its proposal. A copy of Hard copy of the Power Point presentation is given by the SWPL. At the joint hearing, the MOPT, SWPL and the concerned users / user organizations have made their submissions.

7.2. Subsequently, the MOPT has furnished additional comments vide its email dated 10 October 2019 which were forwarded to SWPL vide our letter dated 10 October 2019 as feedback information. The SWPL has, however, not responded.

7.3. As agreed at the joint hearing, the SWPL vide our letter dated 04 October 2019 was requested to take action on the following points arising out of joint hearing proceedings by 09 October 2019:

- (i). At the joint hearing, the MOPT pointed out that as per the License Agreement (LA) entered by the port with the SWPL, port earns 18% revenue share on gross revenue earned by the SWPL from cargo handling charges. The MOPT does not get revenue share from berth hire revenue of SWPL as per the LA. The port requested the SWPL to consider nominal increase in berth hire charges and higher increase in cargo related charges instead of 23% increase proposed by the SWPL across the board. As agreed at the joint hearing, the SWPL was requested to look into the matter and respond to TAMP and MOPT.
- (ii). The another point of the MOPT is that SWPL has proposed concession in the cargo handling charge for thermal coal and iron ore pellets at 60% of the rate proposed for the foreign cargo. These two cargo items are not entitled for coastal concession as per the coastal concession policy of the Govt. The existing SOR of the SWPL does not prescribe coastal concession for these two cargo items which are not eligible for coastal concession. The SWPL to make necessary modification in the proposal to fall in line with the Coastal Concession Policy of the Government which is uniformly followed across all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat.

8. In response to the action points flowing from the joint hearing, the SWPL has filed its revised proposal dated 16 October 2019 under cover of its email dated 17 October 2019. The SWPL has made the following modifications in its revised proposal.

- (i). Vessel related charges is proposed to be increased by 15% and Cargo related charges is proposed to be increased by 26% as against across the broad increase of 23% in berth hire charges and cargo related charges proposed earlier.
- (ii). Tariff for coastal coal and coke is kept same as foreign cargo.
- (iii). Penal interest is now proposed at 15% as per the Tariff Guidelines, 2019.
- (iv). There is no change done by SWPL in Form-1 to Form-8.

9. Based on the preliminary scrutiny of the revised proposal, the SWPL was requested vide our letter dated 04 November 2019 to furnish information/ clarifications on a few points by 18 November 2019. The SWPL has furnished its reply on additional information/ clarification vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent emails dated 22 November 2019 and 22 November 2019. A summary of additional information/ clarification sought by us and reply furnished by SWPL thereon is tabulated below:

Sl. No.	Information/ Clarification sought by us	Reply furnished by SWPL
1.	<u>Annual Revenue Requirement (ARR) (Form No.1):</u>	
(i).	As per Clause 2.3.2 of Tariff Guidelines, 2019 in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP, then necessary adjustments need to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. In this regard, Form 6A, furnished by the SWPL at Sr.	The Company recognizes under the provision of IND AS disclosure, the net obligation of the defined benefit plan in its balance sheet as asset and liability. Gain and losses through a re-measurement of the net defined benefits liability / assets are recognized in other comprehensive income, which was applicable in IGAAP.

	<p>No.2 shows adjustments for Gratuity and Genl. Expenses as per IND AS reported in the Accounts vis-à-vis IGAAP considered in the cost statement. The SWPL is requested to explain the adjustments done giving cross reference with the figures reported in the Annual Accounts as per IND AS. Further the basis of IGAAP figures consolidated in form 6A for each of the years with explanation.</p> <p>Whilst the SWPL has shown adjustment for gratuity for the year 2016-2017 with reference to the figures reported in the Audited Annual Accounts as per IND AS vis-à-vis IGAAP, the reasons for not considering any such adjustment for the gratuity item reported in the Audited Annual Accounts for the years 2017-2018 and 2018-2019 as per IND AS to be explained.</p>	<p>The SWPL has subsequently vide email dated 22 November 2019 clarified that under IND AS, company recognises current and past periods service cost and the net interest on the net benefit liability or asset arrived using discount rate as expenses of the period and has charged as an employee benefit cost. However, remeasurement of defined benefit liability or asset consisting of: actuarial gains / losses, return on plan assets and changes in the asses ceiling effect needs to be treated as other comprehensive income under the provision of IndAS accounting rule. However, in erstwhile scenario, under IGAAP it was treated as an employee benefits.</p>
(ii).	<p>(a). In the Form 3 relating to computation of working capital (as per norms), the SWPL has considered receivables at `2,270.86 lakhs at Sr. No.II (a). This is not found to be in line with Working capital norms prescribed in Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 and the format prescribed (Form 3) to the Working Guidelines. The SWPL to make necessary modification to comply with the Tariff Guidelines.</p>	For the calculation of working capital, debtors are removed.
	<p>(b). As per the clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 read with clause 2.2 of the Working guidelines to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, advance payment of lease rental / license fee to landlord port flowing from the contractual obligations will be recognised as sundry debtor for computation of working capital. The SWPL is required to pay the lease rent for the lands allotted to it in advance every year as stipulated in Article 7.3.5.2 of the LA. The License fees for the year 2018-19 reported in the Audited Annual Accounts is `656.89 lakhs. 50% thereof comes to `328.45 lakhs in line with the approach followed in earlier tariff revision. Whereas, the SWPL has considered an amount of `433.88 lakhs towards Advance paid for license fee in Form-3. SWPL to make necessary corrections in the computation of Working Capital in this item.</p>	The Company has paid licensee fee of `8,6776,187 to the Port Trust in the month of May 2019 for advance license fee for the financial year 2019-20. Previous year the company paid `656.89 lakh only and hence even if considering the allowable escalation of 4.26% on License fee paid during FY 2019 this will be less than the actual amount paid to the Port Trust. Therefore, half of the actual amount paid `4,33,88,094 is considered for working capital.
	<p>(c). Allowable cash expenses in Working Capital computation is considered at `1,103.70 lakhs i.e. one month of operating expenses reported in the Audited Annual Accounts for the year 2018-19 excluding depreciation and finance cost. Recognizing that in the computation of ARR few adjustments have been done under Sr. No.2, one month cash</p>	<p>Total operating expense based on Annual Revenue requirement is `19771.57 lakhs. After adjustment of average depreciation of last three years for ARR calculation of ` 809.47 Lakhs, annual operating expense is `18,962.10 lakh.</p> <p>For purpose of working capital consideration, average one month expense i.e. `1580.17 is considered as cash</p>

	expenses need to be considered based on total expenditure for the year 2018-19 as per Sr. No.5 as per Form 1 and after excluding depreciation captured therein as per IGAAP.	balance required.
(iii).	<p>As per clause 2.5 of the Tariff Guidelines 2019 Capital Employed will comprise of Gross Fixed assets (Property, Plant & Equipment) [as arrived as per the Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP)] plus capital work in progress as on 31 March/ 31 December of the year Y3 to be restated from the figures reported under IND AS in the Audited Annual Accounts and working capital as per norms prescribed. The BOT operators need to furnish a reconciliation statement duly certified by a Chartered Accountant/ Cost Accountant reconciling the figures of Audited Accounts and Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) under IGAAP considered by them giving details of the adjustment. Capital employed shall be duly certified by a practicing Chartered Accountant / Cost Accountant.</p> <p>The SWPL to furnish a reconciliation statement duly certified by a practicing Chartered Accountant / Cost Accountant of the gross fixed assets considered at `48,602.09 lakhs for the year 2018-19 under the IGAAP vis-à-vis gross fixed assets reported in the Audited Annual accounts at `46,790.08 lakhs [i.e. `194.73 lakhs (Tangibles) + `46,595.35 lakhs (intangible assets)] for the year 2018-19 under the IND AS. This may be supported with detailed working and explanation. If the working is being given in excel, then the same may be furnished with linkages for ease of understanding the adjustments done.</p>	Under the head of plant and equipment, ship unloaders were acquired under the EPCG scheme of the Government of India for the capital goods acquired. The value of duty saved amount, aggregating to `3008 lakh is recognized as fixed asset under the provision of IND AS for considering the fair value of the asset, however the said duty benefit cannot be recognized as Cost of the Fixed Asset under AS 12 of IGAAP. Reconciliation is attached as annexure I.
(iv).	The SWPL has indexed the estimated ARR of `28210.95 lakhs arrived based on actuals for the years 2016-17 to 2018-19 by 3.45%. The applicable indexation to be considered should be 4.26% for the year 2019-20. The SWPL to, therefore, modify the indexation factor and arrived at the revised ARR	Indexation for FY 2019-20 is revised from 3.45% to 4.26% and accordingly proposal is revised.
2.	Revenue estimation (Form-4):	
(i).	<p>The SWPL vide email dated 17 October 2019 has furnished revised proposal under cover of its letter dated 16 October 2019. In the revised proposal the SWPL has proposed 15% increase in vessel related income and 26% increase in cargo related income as against 23% increase sought in its original proposal for both cargo and vessel related activities. The SWPL has also furnished revised proposed SOR. It is, however, seen that in the revenue estimation</p>	<p>Form 4 is revised as per the revised revenue estimates and revised tariff proposal.</p> <p>Subsequently, the SWPL vide its email dated 22 November 2019 has furnished in further revised Form 4 giving detailed working of revenue estimation at the proposed tariff for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed tariff is `287.50 crores as against revised</p>

	furnished in Form 4, the SWPL has not considered revised proposed rate. The SWPL is, therefore, requested to furnish modified Form-4 based on the rates proposed in the revised proposed SOR.	estimated ARR of `291.35 crores.
(ii).	The current exchange rate is 1US\$ = `70.99 as against 1US\$ = `69.00 considered by SWPL in the revenue estimation of vessel related charges. The SWPL may consider to modify the revenue estimation of vessel related charges based on the prevailing exchange rate.	Exchange rate of 1US\$ = INR 69 is modified to 1US\$ = INR 71.
(iii).	The SWPL has proposed a new tariff item viz., Charges for supply of water to vessels for which the SWPL has not captured any revenue impact in Form-4. The SWPL to capture probable revenue estimate for this item also in Form-4.	Water supply income is not envisaged. The same is removed from SOR.
(iv).	<p>Tariff items prescribed in existing SOR and also included in proposed SOR with revised tariff; but no revenue is estimated by the port in Form-4 for the following tariff items:</p> <p>(a). <u>Wharfage Charges at Berth No.5A & 6A:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (i). Foreign cargo: <ul style="list-style-type: none"> (a). Iron Ore Pellets (b). Any other bulk cargo (ii). All Coastal cargo. <p>(b). <u>All cargo Handling Charges at Berth No. 5A.</u></p> <p>(c). <u>Cargo Handling Charges at Berth No.6A:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> (i). (a). Iron Ore Pellets (Foreign cargo) (b). Any other bulk cargo (Foreign cargo) (ii). All Coastal cargo. <p>The SWPL to confirm that no traffic / services are rendered by the SWPL for the above items in the year 2018-19 and no revenue earned during the year 2018-19. If the traffic was not handled by the SWPL in the year 2018-19, the SWPL may consider traffic of the years 2016-17 and / or 2017-18 as base for revenue estimation for the above items.</p>	Revenue from Iron Ore Pellets and any other bulk cargo has not been estimated as these cargoes are not expected as per previous years experience. The proposal has escalated tariff assuming that if the customers do feel to handle these cargoes through this terminal then the same will be applicable. In case these cargoes would be handled, other quantity of cargo like limestone or coal may be reduced due to capacity constraints. Therefore, there will be no impact on total revenue due to these cargoes.
3.	<u>Scale of Rates:</u>	
(i).	<u>General Terms and Conditions:</u> The Authority has passed common adoption Orders for all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including SWPL from time to time and all the Major Port Trusts	

	<p>and BOT operators operating thereat including SWPL were requested to include suitable notes in the SOR. However, the SWPL has not included suitable notes in the proposed SOR in line with following common adoption Order:</p> <p>(a). (i). Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 10 June 2016 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC) and Criteria for levy of Vessel Related Charges and Concessional Coastal rate.</p> <p>(ii). Amendment Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 25 September 2018 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance.</p>	<p>Provisions as per Amendment Order No. TAMP/53/2015-VOCPT dated November 26, 2015 for System for classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC) and Criteria for levy of Vessel Related Charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate has been incorporated in revised SOR.</p>
	<p>(b). The Authority had passed the Order No.TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 as common Order incorporating a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat for a period of two years as per the common adoption Order by all Major Port Trusts and BOT terminals thereat shall be applicable in case of SWPL also.</p> <p>The SWPL is requested to incorporate the provisions in the SOR stipulated in these common Orders.</p>	<p>Provision for Mandatory User Charges (MUC) as per Order No. TAMP/12/2019-MUC is specifically for containers. South West Port is not handling any container cargo, hence the same is not applicable.</p>
(ii).	<p>As per the coastal concession policy of the Government, thermal coal, iron ore pellets and POL including Crude oil are not entitled for coastal concession.</p>	<p>For revenue estimate of coal, both thermal and non-thermal, the Company considered only foreign vessels based on the previous years' experience. Though, in revised SOR, concession for coastal vessels carrying coal other than thermal coal has been proposed as per the tariff</p>

	<p>(a). Accordingly, in the existing SOR no coastal concession is prescribed for iron ore pellets under Wharfage Charge and Cargo Handling Charges. However, the SWPL in the proposed SOR has proposed concessional rate for coastal iron ore pellets which is not in line with the coastal concession policy of the Government. The SWPL to make necessary correction in the proposed SOR and revenue estimate, if any, under this category is estimated to be handled.</p> <p>(b). In the existing SOR, in the wharfage charges and cargo Handling charges under Section A and B respectively, the nomenclature prescribed is “Coal except thermal coal”. Accordingly, as per the coastal concession policy of the Govt., concession in tariff is prescribed for coastal cargo under this nomenclature. However, the SWPL in the proposed SOR has modified the nomenclature as coal of all types. While doing so, the SWPL has not proposed concessional tariff for coastal coal cargo. Since thermal coal is not entitled for coastal concession per the coastal concession policy of the Govt. and the Tariff Order No.TAMP/4/2004-Genl. dated 15 March 2005, the SWPL is requested to make necessary correction in the proposed SOR prescribing coastal concession for coal-all types except thermal and separate entry may be prescribed for thermal coal without concessional tariff to fall in line with the coastal concession policy of the Govt. Consequently, necessary correction may be made in the revenue estimates as well.</p>	<p>policy, there is no need to change the revenue estimates as all the coal are considered for foreign vessels.</p> <p>[In the revised proposed SOR, the SWPL has not proposed Coastal Concession for thermal Coal. However, for iron ore pellets, SWPL has proposed Coastal Concession which is not in line with the Coastal Concession Policy of the Government]</p>
(iii).	Clause 8.2.3 of Working Guidelines, 2019 stipulates that before classifying any cargo under “Unspecified” category under the wharfage schedule, the relevant custom classification should be referred to find out whether the cargo could be classified under any of the specified categories mentioned in the wharfage schedule. The MOPT while furnishing the comments on the original proposal of the SWPL has requested for incorporation of said clause. The SWPL is, therefore, requested to incorporate the same in the proposed SOR.	Provision for unspecified cargo incorporated in revised SOR.
(iv).	The SWPL has proposed to include a new tariff item viz., charges for supply of water to vessels and miscellaneous services at the rate of US \$ 3.3069 per 1000 litres for foreign going vessel and `88.55 per 1000 litres for coastal vessels. The SWPL to furnish the basis for proposed rate and proposing dollar denominated tariff for supply of water to foreign vessels may be	Tariff for water charges is removed.

	justified.			
4. Past Period Surplus:				
	Clause 3.1.2 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that in case of operators who have not approached Courts, the surplus/deficit upto the period of first tariff fixation under this Guidelines shall be dealt with as per Clause 2.13 of the 2005 Tariff Guidelines as reproduced below: <i>"The actual physical and financial performance will be reviewed at the end of the prescribed tariff validity period with reference to the projections relied upon at time of fixing the prevailing tariff. If performance variation of more than + or - 20% is observed as compared to the projections, tariff will be adjusted prospectively. While doing so 50% of the benefit/ loss already accrued will be set off while revising the tariff."</i>	The SWPL has furnished revised statement of past period surplus for the year 2016-17 to 2018-19. A summary position is given below:		
Particular	Estimates relied upon in the Tariff Order dated 15.01.2016	Actuals	Variation in %	
Traffic (In MMTPA)	22.50	27.64	22.84%	
Total Operating Income	73,507.32	74,378.95	1.19%	
Operating Costs (excluding depreciation)	36,578.46	44,683.01	22.16%	
Depreciation	7,358.75	8,115.00	10.28%	
Overheads	5,633.08	6,846.77		
FMI Less FME	272.00	278.64	2.44%	
Capital Employed	95,066.35	87,139.26	-8.34%	
RoCE adjusted for capacity utilization	15,210.62	13,942.28	-8.34%	
Net Surplus / (Deficit)	8,998.41	1,070.53		

Subsequently, SWPL vide its email dated 22 November 2019 has further clarified with regard to income classified under other income viz., Foreign exchange gain/loss, SEIS (Service Export from India Scheme) Income, EPCG (Export Promotion of Capital Goods) and Miscellaneous income as follows:

(i). Foreign exchange gain/loss: This amount is reflected in Profit and Loss statement considering notional gain on buyers credit availed for Ship Unloaders.

(ii). SEIS (Service Export from India Scheme) Income: This income is received under export of services incentive scheme.

(iii). EPCG (Export Promotion of Capital Goods): Under this scheme benefit is availed on saving of custom duty. Currently under IndAS accounting, this custom duty benefit needs to be added in the capital cost, hence this is also reflected in the amortization of the assets.

		(iv). Miscellaneous income: This income is in nature of non-operational one time generated out of equipment shared with outside customers or subcontractors for the temporary assignments and other capex purposes.
--	--	---

10.1. While furnishing the additional information/ clarifications, the SWPL vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent email dated 22 November 2019 has furnished revised proposal comprising revised Form-1 (ARR), Form-3 (Working Capital), Form-4 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement) and Past Period.

(i). A summary position of ARR computation furnished by SWPL is tabulated below:

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)	(₹ in lakhs)
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)				
(i).	Operating expenses (including depreciation)	24,021.16	23,605.00	16,819.02	
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	239.73	279.60	21.84	
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86	
(2).	Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP				
(i).	Depreciation	(670.77)	(964.17)	(793.46)	
(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed	(217.50)	(8.69)	(18.20)	
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	(888.27)	(972.86)	(811.66)	
(3).	Less Adjustments:				
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	(3,415.98)	(3,554.06)	(2,154.16)	
(ii).	Interest on loans	(239.73)	(279.60)	(21.84)	
(iii).	Provision for bad and doubtful debts	-	-	-	
(iv).	Provision for slow moving inventory	-	-	-	
(v).	Other provisions, if any	-	-	-	
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	(3,655.71)	(3,833.65)	(2,176.00)	
(4).	Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019	2,486.07	2,586.56	1,567.75	
(5).	Total Expenditure after Total Adjustments (5=1+2+3+4)	22,202.98	21,664.65	15,420.95	
(6).	Average Expenses of SI. No.5 = [Y1+Y2+Y3]/3			19,762.86	
(7).	Capital Employed				
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)			48,602.09	
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			172.75	
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019				
	(a). Inventory			162.85	
	(b). Sundry Debtors			433.88	
	(c). Cash			1,579.45	
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)			2,176.18	
	(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)]			50,951.02	
(8).	Return on Capital Employed 16% on SI. No.7(iv)			8,152.16	
(9).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable			27,915.02	

	[(6)+(8)]	
(10).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable @1.0426% and after adjustment of past period surplus of ` 30.51 lakhs	29,134.72
(11).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement	29,134.72
(12).	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above	28,750.00

(ii). The SWPL in the final revised proposal has proposed the following modifications:

- (a). Berth hire charges is proposed to be increased by 15% and Cargo related charges is proposed to be increased by 26% to meet the estimated ARR.
[At the proposed rate, the increase in cargo related charges works out to 20% to 26.67% and not uniform increase of 26% as stated by the SWPL]
- (b). The SWPL has furnished in revised Form 4 giving detailed working of revenue estimation at the proposed tariff for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, revised estimated ARR is ₹291.35 crores as against the earlier estimated revenue of ₹290.82 crores.
- (c). Further, the SWPL has agreed to send copies each of Form-1 (ARR), Form-3 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement), Form-7 (Fixed Assets Statement as per IGAAP considered in ARR computation giving details of adjustments) duly certified by practicing Chartered Accountant as soon as possible.

10.2. Subsequently, the SWPL vide its email dated 25 November 2019 has furnished Form-1 (ARR), Form-3 (Revenue Estimation), Form-6A (Reconciliation statement), Form-7 (Fixed Assets Statement as per IGAAP considered in ARR computation) duly certified by practicing Chartered Accountant with reference to its final revised cost statements furnished vide email dated 22 November 2019.

11. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

12. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The Scale of Rates of South West Port Limited (SWPL) was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/40/2016-SWPL dated 17 November 2016, following the Tariff Guidelines of 2005, which stipulated cost plus pricing model. The validity of the SOR was prescribed till 31 March 2019.

Before proceeding to the current proposal filed by the SWPL for revision of its SOR, it is relevant here to state that the said tariff Order of November 2016, stipulated that the SWPL may be called upon to file ahead of schedule review in case the actual traffic handled by the SWPL varies significantly from the traffic estimates considered relying on the submissions made by the SWPL and endorsed by the MOPT for the reasons explained in para 13 (vii) (a) of the Order No.TAMP/40/2016- SWPL dated 17 November 2016. The SWPL in the current proposal has reported to have handled traffic of 11.75 MMT, 10.61 MMT & 5.25 MMT for the years 2016-17, 2017-18 & 2018-19 respectively.

In this regard it is relevant here to state that, when the MOPT reported the actual traffic handled by the SWPL in the year 2016-17 is 11.75 MTPA, at that point of time itself, SWPL was vide our

letter dated 8 November 2017 requested to file a proposal based on actuals of 2016-17 and revise the tariff estimates and corresponding income and expenditure estimations for the years 2017-18 and 2018-19 and furnish its proposal latest by 30 November 2017 in pursuance of the decision of this Authority in para 13 (vii) (a) of the Order dated 17 November 2016. This was followed by reminder dated 5 March 2018. The SWPL had chosen to remain silent at that point of time and did not respond, despite reminder and despite follow up done by the Licensor Port. On the other hand, the SWPL, vide its letter dated 08 April 2019 had requested this Authority to extend the validity of the existing tariff till 30 September 2019 or till the new tariff is notified whichever is earlier. The above position of non-action from the side of the SWPL was brought to the notice of SWPL vide our letter dated 14 May 2019 advising SWPL to furnish the actual performance for the year 2018-19. It was then, that SWPL has filed the current proposal in July 2019 for revision of its SOR under the new Tariff Guidelines, 2019.

- (iii). The Ministry of Shipping (MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019, by the MOS, the tariff fixation exercise in respect of the SWPL is to be governed by the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019.

The current proposal dated 24 July 2019 filed by the SWPL for general revision of its SOR is under the Tariff Guidelines, 2019 and Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019. The SWPL has furnished the requisite information/ clarification sought by us along with revised Annual Revenue Requirement (ARR), draft SOR and modified estimates of revenue vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent email dated 22 November 2019. The final revised proposal filed by SWPL vide its letter dated 14 November 2019 and subsequent email dated 22 November 2019 along with submissions made by the SWPL and port during the processing of the case are considered in this analysis.

- (iv).
 - (a). Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, requires each BOT Operator to assess the ARR which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on Capital Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.
 - (b). The SWPL has assessed the ARR based on Audited Annual Accounts for three years i.e. 2016-17 (Y1), 2017-18 (Y2) and 2018-19 (Y3) duly certified by a practicing Chartered Accountant. While assessing the ARR, the SWPL has made exclusions of the expenses not admissible in ARR computation, as prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019. The following adjustments done by SWPL in line with provisions prescribed in Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines are brought out for specific mention:
 - (i). Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, interalia, stipulates that Royalty/Revenue share payable to the landlord port by the BOT operator in those cases where the bidding process was finalized before 29 July 2003 tariff computation will be taken into account to the extent of the next highest bidder in the ARR computation.

Accordingly, of Revenue share as reflected in the Audited Annual Accounts to the tune of ₹34.16 crores, ₹35.54 crores and ₹21.54 crores during the years 2016-17 to 2018-19 respectively is excluded. Since the bidding process in respect of SWPL was finalised before 29 July 2003, revenue share to the extent of the next highest bidder i.e. 13.1% has been considered in the computation of ARR i.e. ₹24.86 crores, ₹25.86 crores and ₹15.67 crores during the years 2016-

17 to 2018-19 respectively. This is in line with the clause 2.2 of the tariff guidelines of 2019.

- (ii). As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019, Interest on loans, provision for bad and doubtful debts, provision for slow moving inventory etc., are to be excluded. The SWPL has accordingly, excluded ₹239.73 lakhs, ₹279.60 lakhs and ₹21.84 lakhs during the years 2016-17 to 2018-19 respectively as interest on loan. The other items for exclusion are considered as nil.
- (iii). Clause 2.3.2 stipulates that in case there is variation in the expenditure reported under IND AS and IGAAP (like depreciation), then necessary adjustments to be done in ARR computation by excluding IND AS figure and considering figures as per IGAAP. The Audited accounts of SWPL are IND AS compliant. The SWPL has made necessary adjustment in the Depreciation, Gratuity and General expenses to capture these items as per IGAAP to comply with the Guideline position. The SWPL has shown as exclusion of ₹888.27 lakhs, ₹972.86 lakhs and ₹811.66 lakhs during the years 2016-17 to 2018-19 respectively from the computation of ARR on account of adjustment of Deprecation and other expenses under IGAAP. The SWPL has furnished the requisite working in Form 6A which is duly certified by practicing Chartered Accountant and the same is relied upon.
- (v). Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines and based on the adjustments as discussed above, the SWPL has arrived at average expenses for the years 2016-17 to 2018-19 at ₹19,762.86 lakhs (₹197.63) crores, as per the stipulation prescribed in clause 2.4 of the Tariff Guidelines, 2019.
- (vi).
 - (a). As per clause 2.5 of the Tariff Guidelines 2019 Capital Employed will comprise of Gross Fixed assets (Property, Plant & Equipment) [as arrived as per the Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP)] plus capital work in progress as on 31 March/ 31 December of the year Y3 to be restated from the figures reported under IND AS in the Audited Annual Accounts and working capital as per norms prescribed. The Audited Annual Accounts for the year 2018-19 reports Gross fixed Assets of ₹467.90 crores under the IND AS. The SWPL has considered gross fixed assets at ₹48,602.09 lakhs (₹486.03 crores) as per IGAAP in line with provision prescribed in Clause 2.5 of the Tariff Guidelines, 2019. The SWPL has furnished prescribed Form 7 giving computation of gross fixed assets as per IGAAP duly certified by practicing Chartered Accountant. The SWPL has also furnished a reconciliation in this regard. The Gross Fixed Assets as on 2018-19 considered by the SWPL as per IGAAP duly certified by the Chartered Accountant is relied upon and considered.

The SWPL has considered capital work-in-progress of ₹172.75 lakhs as reflected in the audited Annual Accounts for the year 2018-19.

- (b). Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. The Inventory is seen to have been computed as per norms prescribed in clause 2.6 of Tariff Guidelines, 2019. As regards cash, the SWPL has considered average cash expense of last three years instead of the year 2018-19. Cash expense for working capital computation is considered at one month cash expense of the year 2018-19.
- (c). As per the clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 read with clause 2.2 of the Working guidelines to operationalise the Tariff Guidelines, 2019, advance payment of lease rental / license fee to landlord port flowing from the contractual obligations will be recognised as sundry debtor for computation of working capital. The SWPL is required to pay the lease rent for the lands allotted to it in advance every year as stipulated in Article 7.3.5.2 of the LA. The License fees for the year 2018-19 reported in the Audited Annual Accounts is

₹656.89 lakhs. 50% thereof comes to ₹328.45 lakhs in line with the approach followed in earlier tariff revision. Whereas, the SWPL has considered an amount of ₹433.88 lakhs towards advance license fee. SWPL has stated that it has paid advance licensee fee for the financial year 2019-20 to the tune of ₹ 867.77 lakhs in the month of May 2019 and the same is considered in the ARR computation. The SWPL has contended that the SWPL has paid ₹ 656.89 lakhs in the previous year 2018-19 and even if the allowable escalation of 4.26% thereon is considered, License fee for the financial year 2019-20 will be less than the actual amount of ₹867.77 lakhs paid by the SWPL to the MOPT. Therefore, the SWPL has tried to justify the figure of half of the actual amount paid during the year 2019-20 i.e. ₹433.88 lakhs considered for working capital.

In this regard, it is relevant to state that Tariff Guidelines 2019 require to calculate the ARR computation based on average of expenses of immediate previous three years Y1, Y2 and Y3 as per the final Audited Annual Accounts subject to certain adjustments plus 16% return on capital employed for which the figures reported in the Audited Accounts of Y3 forms the base. In the case of SWPL, the ARR computation is based on actuals of the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 Audited Accounts subject to adjustments as prescribed in the Tariff Guidelines. The request of SWPL to consider only one component i.e. advance payment of license fee for working capital based on Y4 figures i.e. 2019-20 for the reasons cited is not found to be in line with the Guideline position and hence not considered. The computation of the working capital is modified to that extent. 50% of License fees reported in the Audited Annual Accounts for the year 2018-19 i.e. 50% of ₹656.89 lakhs= ₹328.45 lakhs is considered.

- (d). Subject to modifications as explained above, the modified capital employed works out to ₹50,319.48 lakhs as against total capital employed arrived by SWPL at ₹50,951.02 lakhs. Return on Capital Employed (ROCE) considered by SWPL at 16% is ₹8,152.16 lakhs. The modified ROCE works out to ₹8,051.12 lakhs based on the modified Capital Employed.
- (vii). The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2016-17 to 2018-19 plus 16% ROCE. The ARR arrived by SWPL is ₹279.15 crores (₹197.63 crores + ₹81.52 crores). The modified ARR arrived by us works out to ₹278.14 crores (₹197.63 crores + ₹80.51 crores). Further, as per Clause 2.8 of Tariff Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 which is 4.26%. The indexed ceiled ARR assessed by the SWPL is ₹291.04 crores applying 4.26% indexation. The SWPL has also made adjustment of past period deficit for the years 2016-17 to 2018-19 to the tune of ₹30.51 lakhs (₹0.31 crores) and added this deficit to the ARR and arrived at ceiling indexed ARR of ₹291.35 crores (₹291.04 + 0.31 crores).

However, the modified cost statement furnished by the SWPL subsequently for the past period 2016-17 to 2018-19 reflects aggregate additional surplus of ₹1070.53 lakhs (₹10.70 crores) after admissible cost plus 16% ROCE.

As per the modified ARR computation done by us the modified indexed ceiling ARR works out to ₹289.99 crores for the year 2019-20 (₹278.14 crores * 1.0426). This does not include of past period adjustment. The analysis relating to the past period is brought out in subsequent paragraphs.

The final detailed working of ARR calculation furnished by the SWPL which has been duly certified by Chartered Accountant are relied upon. This is subject to minor modification as explained above. The detailed ARR calculation furnished by the SWPL and modified ARR calculation by us are attached as **Annex-I (a)** and **(b)** respectively.

- (viii). Clause 3.1.2.of the Tariff Guidelines 2019 stipulate that in case of the BOT operators who have not gone to the Court against the previous Order of this Authority, the surplus/ deficit for the past period till the period of tariff fixation during the first fixation of Tariff under the Tariff Guidelines of 2019 is to be done as per clause 2.13 of the Tariff Guidelines 2005.

The SWPL has furnished Form-8 giving the average of actuals for the years 2016-17 to 2018-19. In the said form, the SWPL has assessed average net deficit of ₹76.28 lakhs after admissible expenses and 16% return on capital employed. 20% thereof is absorbed by SWPL and of the balance 80% i.e. ₹76.28 crores *80% = ₹61.02 lakhs, the SWPL has considered adjustment of 50% of the net deficit i.e. ₹30.51 lakhs in the computation of the final ceiling indexed ARR. The Form-8 furnished by SWPL is not relevant for the first cycle under Tariff Guidelines, 2019. As per the note prescribed in the said Form attached to the Working Guidelines 2019, Form 8 is relevant to be furnished subsequent to the first tariff revision under the Tariff Guidelines, 2019.

The SWPL has, however, subsequently furnished revised Cost Statement for the past period 2016-17 to 2018-19 reviewing the estimates considered in last tariff Order vis-à-vis the actuals in line with clause 3.1.2.of the Tariff Guidelines 2019 read with clause 2.13 of the Tariff Guidelines 2005. The review of past period actuals vis-à-vis estimates furnished by the SWPL for the years 2016-17 to 2018-19 is modified/ corrected for the reasons explained in the subsequent paragraphs.

- (ix). During the last tariff revision, the tariff of SWPL was fixed by relying upon the estimates for the years 2016-17 to 2018-19. Thus, the estimates vis-à-vis actuals for the years 2016-2017 to 2018-19 are to be analyzed to assess the actual performance of SWPL during the said tariff period to comply with the clause 3.1.2. of the Tariff Guidelines 2019. The general approach followed to analyse the estimated position in the last tariff Order is adopted to assess the actual net surplus / deficit for the years 2016-17 to 2018-19. The analysis is as given below:

- (a). The actual traffic handled by SWPL during the period from 2016-17 to 2018-19 is 11.77 Million Metric Tonnes Per Annum (MMTPA), 10.62 MMTPA and 5.25 MMTPA respectively aggregating to 27.64 MMTPA as against the estimated traffic of 7.50 MMTPA for each of the three years aggregating to 22.50 MMTPA estimated in the tariff Orders of November 2016 for the corresponding period.

The actual traffic of the SWPL reported by MOPT in the years 2016-17 to 2018-19 aggregates to 27.68 MMTPA which slightly varies from the actual aggregate traffic reported by the SWPL at 27.64 MMTPA for the corresponding period. The SWPL has clarified that there is negligible variation from the traffic figures because they have gone by the actual traffic as per the bill of lading. For the purpose of this analysis, the actual traffic reported by the SWPL is considered.

The variation in the physical performance is 22.84% positive which is found to be more than 20%.

- (b). The income estimates considered in the last tariff Order for the year 2017-18 is adjusted for three months i.e. the period from January 2017 to 31 March 2017 and for the years 2017-18 and 2018-19 on pro rata basis to capture the effect of tariff increase of 10% in berth hire charges and 27.8% tariff increase in cargo handling charges effected in the November 2016 tariff Order for a like to like comparison with the actual income from the date of implementation of the Order.

- (c). The opinion of Attorney General for India conveyed by Ministry of Shipping vide its letter dated 12 June 2015 is that the actual income earned by the operator based on their Audited Accounts should be considered and not any notional income. Therefore, for the purpose of analysis of the past period, the actual income as reported in the Annual Accounts is considered.

- (d). Revenue share is considered as a cost item to the extent of the revenue share quoted by the second highest bidder i.e., 13.10% on the actual cargo handling revenue reported during the years 2016-17 to 2018-19 in line with the approach adopted in the last tariff Order which is in line with the clause 2.8.1 of the tariff guidelines of 2005 as done by the SWPL as well.
- (e). The SWPL has considered the depreciation figure as per the IGAAP in the cost statement prepared by it for the past period. The same is considered on the premise, that the cost statement prepared during the last revision was based on the estimates which at that time was based on IGAAP. From the year 2016-17, the SWPL has followed IND AS method of accounting. But, for a like to like comparison as done by the SWPL, the depreciation figure under IGAAP duly certified by the Practicing Chartered Accountant is considered as done by the SWPL.
- (f). It is seen that the SWPL has not made necessary adjustment as regards Gratuity and General expenses as per IGAAP in the past period cost statement for the years 2016-17 to 2018-19. Since the estimates for the years 2016-17 to 2018-19 considered during the last tariff revision was based on the then accounting method as per IGAAP followed by the SWPL, while comparing the actuals vis a vis the estimates for the same period, the figures reported in the Audited Accounts for the years 2016-17 to 2018-19 based on IND AS need to brought as per IGAAP. The SWPL has not done this adjustment. Hence, in the cost statement prepared by us for the past period, this adjustment is done based on the figures as per IGAAP made available by the SWPL in form 6A. This adjustment is captured in the management and general overheads expenses by reducing it to the tune of ₹217.50 lakhs, ₹8.69 lakhs and ₹18.20 lakhs based on the IGAAP figures for these items furnished by the SWPL itself in Form 6A.
- (g). The actual FMI reported in the Audited Annual Accounts of the SWPL is ₹1,858.51 lakhs, ₹3,564.87 lakhs and ₹2,576.96 for the years 2016-17 to 2018-19 crores respectively.

The SWPL has considered ₹88.75 lakhs, ₹309.51 lakhs and ₹421.56 lakhs for the year 2016-18 to 2018-19 respectively under the head FMI. This income pertains to operating income from other port services as per the Annual Accounts and hence it is shifted from FMI to operating income in the Cost Statement prepared by us. The SWPL has clarified the nature of foreign exchange gain/ loss, Service Export from India Scheme (SEIS) income, miscellaneous income reported under the head FMI in the Audited Annual Accounts. The foreign exchange gain is stated to be notional gain on account of buyers credit. Since, this item is not reported to have arisen due to actual transaction, it is not captured as income in the cost statement prepared by us. As regards miscellaneous income, SWPL has stated that it is non-operational one time income generated out of equipment shared with sub-contractors for which no tariff is approved by this Authority. These items are, therefore, not considered as FMI in the modified cost statement for the past period prepared by us. The SEIS income in the years 2017-18 and 2018-19 is stated to have been received by SWPL as export of service incentive income. This is captured in the Cost Statement. Further, income from profit on sale of assets and sale of scrap reported in the Audited Annual Accounts are also captured in the Cost Statement prepared by us for the past period.

- (h). As per the LA, Security Deposit of ₹1.53 crores paid by the SWPL to the MOPT is refundable at the end of the project period. During the last tariff revision, the Security Deposit refund was annualized over the remaining period of the project life by discounting at 11%. The SWPL has not considered the effect of this item. In the last tariff fixation exercise, the terminal value receivable at the end of the project was annualized over the project life by applying discounting rate of 11%. The same figures is considered in the cost statement for a like to like comparison.

- (i). All the other cost items are considered as reported in the Annual Accounts.
- (j). The Capital employed considered during the last tariff revision under the then applicable Tariff Guidelines of 2005 is Net Fixed Assets + working capital as per the prescribed norms. The Net Fixed Assets reported in the Audited Annual Accounts for the year 2016-17 to 2018-19 is based on IND AS. The SWPL has considered capital employed at ₹310.96 crores, ₹290.35 crores and ₹270.08 cores for the years 2016-17 to 2018-19 respectively for the purpose of computing ROCE. The capital employed considered by the SWPL is not supported with working.

The Net Fixed Assets under IGAAP as furnished by the SWPL duly certified by the practicing Chartered Accountant at ₹316.27 crores, ₹299.97 crores and ₹271.80 crores for the years 2016-17 to 2018-19 is considered for like to like comparison of the estimate of net fixed assets considered during the last tariff revision which was also based on IGAAP method of accounting then followed by the SWPL.

- (k). The working capital is considered as per norms. The Stores and spares consumed is captured in line with the norms prescribed in the Tariff Guidelines of 2005. The cash balance is considered at one month cash expense in line with the guideline position. 50% of the lease rentals in each of the years is considered as part of working capital in line with the approach followed in the last tariff Order. The current liabilities as reported in the audited annual accounts of the respective years is considered. Subject to the above adjustments, Working Capital works out to be negative. Hence, it is considered as NIL.

Thus, the modified Capital Employed comprises of only Net Block of Assets at ₹316.27 crores, ₹299.97 crores and ₹271.80 crores for the years 2016-17 to 2018-19 respectively as against ₹310.96 crores, ₹290.35 crores and ₹270.07 crores for the years 2016-17 to 2018-19 respectively considered by the SWPL, which is not supported by any working.

- (l). A copy of the cost statement reviewing estimates of 2016-17 to 2018-19 vis-à-vis actuals of the corresponding period is attached as **Annex - II**.
- (m). A summary of the comparison of the actuals vis-à-vis the estimates considered in the last tariff Order is tabulated below:

Particulars	Aggregate for the years 2016-17 to 2018-19 in absolute terms (₹ in lakhs)		Variation in %
	Estimates as per tariff Order	Actuals	
Traffic (in MMTPA)	22.50	27.64	22.84%
Total Operating Income	569.59*	751.99	32.02%
Total Expenditure including FME less FMI, Depreciation and overheads	492.98	579.36	17.52%
Surplus/ deficit before Return	76.61	172.63	
Capital Employed (Average)	316.89	296.01	(6.59%)
16% Return on Capital Employed	152.11	142.08	(6.59%)
Net Surplus after ROCE (before adjustment of past surplus)	(75.50)	30.55	
Adjustment of Past period surplus assessed in November 2016 Order	75.52	-	
Net Surplus after ROCE (after adjustment of past surplus)	-	30.55	

* *The operating income estimates are updated to reflect the effect of tariff increase effected in tariff Order of November 2016 from January 2017 till 31 March 2019.*

(n). The findings of the analysis with reference to the past period relating to the period from 2016-17 to 2018-19 are given below:

- (i). The actual aggregate traffic handled by the SWPL is 27.64 MMTPA as against the estimated traffic of 22.50 MMTPA during the period from 2016-17 to 2018-19. The variation in the physical parameters i.e. actual traffic handled is 22.84% positive in comparison to the estimates.
- (ii). The operating income earned by the SWPL is ₹751.99 crores as against estimation of ₹569.59 crores for the corresponding period resulting in positive variance of 32.02%.
- (iii). On the expenditure side, the actual aggregate expenditure for the years 2016-17 to 2018-19 is ₹579.36 crores as against the estimated expenditure of ₹492.98 crores considered in the last Order for the corresponding period. The total actual expenditure thus shows positive variance of 17.52% in comparison to the expenditure estimated in the last tariff Order.
- (iv). The actual average capital employed for the period from 2016-17 to 2018-19 is ₹296.01 crores as against average estimated capital employed of ₹316.89 crores. The variation in the average capital employed comes to 6.59% negative.
- (v). As per the cost statement for the past period furnished by the SWPL, the SWPL has earned aggregate surplus of ₹10.70 crores for the years 2016-17 to 2018-19 after admissible cost and 16% ROCE. As per the modified cost statement for the past period prepared by us, the SWPL has earned aggregate surplus of ₹30.55 crores after admissible cost and 16% ROCE for the period from 2016-17 to 2018-19.
- (vi). When we see the position before ROCE to determine the average ROCE earned by SWPL for the said three years, it is seen from the cost statement prepared by us, that the SWPL has earned aggregate surplus of ₹172.63 crores before return on capital employed for the period from 2016-17 to 2018-19. The average surplus comes to ₹57.54 crores. The average annual return earned on the average capital employed thus works out to 19.44%, as shown in the following table:

Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	(₹ in Lakhs)
Actual Surplus/ deficit before return	8,158.68	7,170.09	1,934.68	17,263.45 (Total) 5754.48 (Avg.)
Actual Capital Employed	31,626.88	29,996.53	27,180.57	29,601.33 (Avg.)
Actual Return earned on capital employed	25.80%	23.90%	7.12%	19.44%

- (vii). As per clause 2.13 of the tariff guidelines, if review of actual physical and financial performance for the previous tariff cycle shows the variation of more than + 20%, then 50% of such accrued benefit / loss has to be adjusted in the next tariff cycle. As per the opinion of AG also as conveyed by the MOS, variation in both physical and financial parameters should be taken into account for the purpose of clause 2.13.

It can be seen from the above analysis that the variation in the physical parameter i.e., actual traffic handled and financial performance in terms of return on capital employed is positive and the same is more than 20%. Further, as per the above table, the SWPL has earned average return of 19.44% on the capital employed as against 16% return allowed in the last tariff Order. Thus, the variation in both physical and financial parameters exceeds 20% variation and variation is positive. Hence, there is a case for adjustment of past period surplus of SWPL operations while arriving at the tariff for the current tariff cycle following the opinion on the interpretation of clause 2.13 of the Tariff Guidelines of 2005 of the AG..

As per the opinion of the AG, if the variation in both the physical and financial parameters is more than 20%, then 20% of the surplus is to be allowed to be retained by the operator. It is only the surplus over and above the 20% that shall be shared equally i.e. 50:50 between the operator and the users. In nutshell, 60% of additional surplus is allowed to be retained with the operator and 40% additional is to be shared with users by considering adjustment in future tariff.

Accordingly, 40% of Net additional surplus for the years 2016-17 to 2018- 19 i.e. ₹30.55 crores * 40% ₹12.22 crores is to be considered for adjustment in the current tariff cycle by spreading it over three years and the per annum impact shall come to 4.07 crores which is considered for reduction in the ARR computation by reducing the indexed ARR.

For the year 2019-20, from 1 April 2019 till the date of implementation of the revised SOR, the actual net surplus/ deficit will be assessed under Clause 2.13 of the Tariff Guidelines, 2005 during the next revision.

- (x). As brought out in the preceding paragraphs, the modified indexed ceiling ARR was arrived at ₹289.99 crores for the year 2019-20 (₹278.14 crores * 1.0426) without adjustment of past period surplus. The ceiling indexed ARR after reduction of the additional past period surplus of ₹4.07 crores for the years 2016-17 to 2019-20 comes to ₹285.92 crores (i.e. ₹289.99 crores – ₹4.07 crores).
- (xi).
 - (a). As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average traffic for the years 2016-17 to 2018-19 has been considered by the SWPL at 92.00 MMTPA. Therefore, for the purpose of this analysis, the actual traffic reported by the SWPL is considered.
 - (b). As per Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, the BOT Operators have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the Scale of Rates within the ceiling of indexed ARR, duly certified by a practicing Chartered Accountant.

In the original proposal, the SWPL had proposed across the board increase of 23% in berth hire charges and cargo handling charges.

The MOPT has objected the increase proposed in the berth hire charges. Since the MOPT does not get revenue share from berth hire revenue of SWPL as per the LA. The port has requested the SWPL to consider nominal increase in berth hire charges and higher increase in cargo related charges instead of 23% increase proposed by the SWPL across the board in the original proposal. The MOPT has also at one place viewed that

vessel related activity is in huge surplus and they do not mind if SWPL proposes 48% increase in cargo.

As regards the activity wise allocation of expenditure between the cargo handling activity and vessel related activity sought by the MOPT, as rightly stated by the SWPL, under Tariff Guideline 2019, there is no provision for activity wise cost statement. Furnishing of activity wise costing was applicable under the earlier Tariff Guidelines of 2005. Under the Tariff Guidelines of 2019, the tariff is to be fixed based on the Annual Revenue Requirement to be computed on the actuals reported in the Audited Accounts subject to certain adjustments and 16% ROCE. The BOT operators have the flexibility to propose rates such that the revenue estimates at the proposed rates are within the ARR. That being so, the point made by the MOPT seeking activity wise allocation of expense is not found to be in line with the new Tariff Guidelines 2019 applicable to the BOT operators governed by the erstwhile Tariff Guidelines of 2005.

The SWPL in view of the request made by the MOPT has stated that, in the final revised proposal, 15% increase in the berth hire charges and 26% increase in the cargo handling charges is proposed as against 23% increase proposed in both these activities in the original proposal. On comparing the cargo handling charges proposed in the final proposed SOR and captured in the revenue estimates, it is seen that for cargo handling charges the increase proposed is in the range of 20% to 26.67% and 15% increase in berth hire charges. With reference to the request made by the MOPT to consider steep increase in cargo handling activity, the SWPL has categorically stated that if steep increase is done in cargo handling rate, the cargo will go to neighboring ports. Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, gives flexibility to the BOT Operators to determine the rates within the estimated ARR to respond to the market forces based on commercial judgment. The proposal of the SWPL is within the guideline provision. In fact the M/s.Hiralal & Co., have agreed to the proposal of SWPL and the increase sought in the VRC. They have categorically stated that the efficiency of SWPL is very high and hence they have no problem for increase proposed in VRC.

At the revised proposed rate, the SWPL has estimated revenue of `287.50 crores. The SWPL has given detailed working of revenue estimation indicating each of the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for the years 2016-17 to 2018-19, as required as per Clause 2.11.1 of the Tariff Guidelines, 2019. The revenue estimation statement has been duly certified by a Chartered Accountant.

As per the modified ARR computation and past period analysis done by us, as brought out in the preceding paragraph, the modified ceiling indexed ARR after adjustment of the past period surplus comes to ₹285.92 crores (i.e. ₹289.99 crores – ₹4.07 crores). The revenue estimated by the SWPL at ₹287.50 crores at the proposed tariff exceeds the ARR by ₹1.58 crores as against revenue gap of ₹3.85 crores estimated by the SWPL.

Since the revenue estimated by the SWPL exceeds the ARR, and considering that the licensor port has objected the increase in the berth hire charges, the increase in the existing berth hire charges have to be allowed by 12.5% as against 15% increase proposed by the port. This is done to ensure that the revenue estimates is within the modified ARR. The modified revenue estimate based on the above analysis works out to ₹285.84 crores leaving a marginal revenue gap of ₹0.08 crores uncovered.

The revenue estimation furnished by the SWPL and revenue estimation modified by us are attached as **Annex-III (a)** and **(b)** respectively.

- (xii). Based on the above analysis, a summary of the ceiling indexation ARR furnished by the SWPL and as considered by us based on the modified cost statement is given below:

(₹ in crores)

Sr. No.	Particulars	ARR computation furnished by the SWPL	ARR computation modified by us
1	Average admissible Expenses for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 $[Y_1+Y_2+Y_3]/3$	197.63	197.63
2	Capital employed as on 31.03.2019 including capital work in progress as on 31.03.2019 and working capital as per norms	509.51	503.20
3	Return on capital employed @ 16%	81.52	80.51
4	ARR as on 31 March 2019 $(4=2+3)$	279.15	278.14
5	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 (4.26% for the year 2019-20)	291.04	289.99
6	SWPL: Add Adjustment of past period loss for the years 2016-17 to 2019-20 captured by SWPL in the ARR computation. TAMP: Less Adjustment of past period additional surplus for the years 2016-17 to 2019-20 in the ARR computation.	0.31	(-) 4.07
7	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)	291.35	285.92
8	Revenue estimated by the SWPL at proposed rate and modified revenue estimated by TAMP by considering 12.5% increase in berth hire charge as against 15% increase proposed by the SWPL	287.50	285.84
9	Revenue gap	3.85	0.08

(xiii). One another point of the MOPT is that SWPL has proposed concession in the cargo handling charge for thermal coal and iron ore pellets at 60% of the rate proposed for the foreign cargo. These two cargo items are not entitled for coastal concession as per the coastal concession policy of the Govt. The existing SOR of the SWPL does not prescribe coastal concession for these two cargo items which are not eligible for coastal concession. The SWPL was requested to make necessary modification in the proposal to fall in line with the Coastal Concession Policy of the Government which is uniformly followed across all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat.

In the final revised proposed SOR, the SWPL has proposed separate rate for thermal coal without any coastal concession in line with the coastal concession policy of the Government. However, as regards, iron ore pellets, SWPL has proposed Concessional rate for coastal cargo which is not in line with the Coastal Concession Policy of the Government. In the revised SOR, the cargo handling rates and wharfage for coastal iron ore pellets is prescribed at par with the rate proposed for foreign cargo as this cargo is not eligible for coastal concession. This will not have any revenue impact as no coastal iron ore pellets traffic is reported to have been handled during the last three years 2016-17 to 2018-19.

(xiv). As regards the penal rate of interest for delayed payment and refund, the SWPL has proposed the rate penal interest at 15% which is in line with clause 5.4.1 of the Tariff Guidelines 2019. Free period for import cargo is proposed to be increased from existing three days to seven days at par with free days prescribed for export cargo. The Working Guidelines, 2019 gives flexibility to BOT Operators to propose free period. Hence, the proposed free period is approved. Apart from this, the SWPL has retained the conditionalities as prescribed in the existing SOR.

(xv). The SWPL was requested to incorporate the provisions in the SOR stipulated in common adoption Orders approved by this Authority regarding levy of concessional charges for coastal cargo/container vide an Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 and further amended vide Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 and 10 June 2016. The said Order passed is for common adoption by all the Major Port Trusts and the concerned BOT operators in whose Scale of Rates the relevant conditions are prescribed. The notes incorporated by the SWPL are not complete in line with the said common adoption Order. That being so, the notes under 1.2 General Terms and Conditions proposed by the SWPL are replaced

with the modified provisions approved by this Authority vide Orders dated 26 November 2015 and 10 June 2016.

- (xvi). The new tariff item for supply of water to vessels and miscellaneous services proposed by the port in the original proposal has been withdrawn by the SWPL in the final revised proposal.
- (xvii). As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31 December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. It is relevant here to state that in the instant case indexation for the year 2019-20 is already considered in the ARR and for drawing the SOR. The next annual indexation in SOR will be applicable from 1 May 2020. That being so, a note is inserted in the SOR to the effect that the SOR approved by this Authority is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI to be announced by this Authority. The annual indexation will be from 01 May 2020. The indexed SOR by the SWPL has to be intimated by the SWPL to the concerned MOPT, users and to this Authority.
- (xviii). Clause 4.9 of the Tariff Guidelines, 2019 prescribe tariff validity cycle of three years subject to annual indexation as mentioned in clause 2.12. Therefore, the validity of the revised SOR is prescribed for a period of 3 years from the date of effect of revised SOR subject to annual indexation clause prescribed in the SOR.
- (xix). Clause 4.8 of the Tariff Guidelines, 2019 stipulates that ordinarily the Order approved by this Authority shall come into effect after expiry of 30 days from the date the Order is notified in the Gazette. Accordingly, the SOR will come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette.
- (xx).
 - (a). **As per the Tariff Guidelines, 2019, the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels; likewise, rebates and discounts are floor levels. The SWPL may exercise the flexibility to charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.**
 - (b). **If there is any error apparent on the face of record considered or for any other justifiable reasons, the SWPL may approach this Authority for review of the tariff fixed, giving adequate justification/ reasoning within 30 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India.**

13.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the revised Scale of Rates of the SWPL attached as **Annex - IV** is approved.

13.2. The revised Scale of Rates and conditionalities of the SWPL shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and shall be in force for a period of three years from the date the revised SOR comes into effect. The approval accorded will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

13.3. As per clause 7 of the Tariff Guidelines 2019, the SWPL shall furnish to TAMP without fail annual reports on cargo traffic handled and ship berth day output. The annual reports shall be submitted by the SWPL within 90 days following the end of each of the year. Any other information which is required by TAMP shall also be furnished to them from time to time. The SWPL is advised specifically to refrain from withholding requisite information.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./386/19]

**Annex-I (a)
Form -1**

**Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for
BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by SWPL**

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)	Rs. in lakhs
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)				
(i).	Operating expenses (including depreciation)	24,021.16	23,605.00	16,819.02	
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	239.73	279.60	21.84	
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86	
(2).	Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP				
(i).	Depreciation	(670.77)	(964.17)	(793.46)	
(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed	(217.50)	(8.69)	(18.20)	
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	(888.27)	(972.86)	(811.66)	
(3).	Less Adjustments:				
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	(3,415.98)	(3,554.06)	(2,154.16)	
(ii).	Interest on loans	(239.73)	(279.60)	(21.84)	
(iii).	Provision for bad and doubtful debts	-	-	-	
(iv).	Provision for slow moving inventory	-	-	-	
(v).	Other provisions, if any	-	-	-	
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	(3,655.71)	(3,833.65)	(2,176.00)	
(4).	Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019	2,486.07	2,586.56	1,567.75	
(5).	Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2+3+4)	22,202.98	21,664.65	15,420.95	
(6).	Average Expenses of SI. No.5 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3	19,762.86			
(7).	Capital Employed				
	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP)		48,602.09		
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)			172.75	
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019				
	(a). Inventory	162.85			
	(b). Sundry Debtors	433.88			
	(c). Cash	1,579.45			
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)	2,176.18			
	(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]	50,951.02			
(8).	Return on Capital Employed 16% on SI. No.7(iv)	8,152.16			
(9).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or 31 December of Y3 as applicable [(6)+(8)]		27,915.02		

(10).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 [(9) x 1.0426]	29,104.20
(11).	Adjustment of past period deficit of Rs.30.51 lakhs pertaining to years 2016-17 to 2018-19	30.51
(12).	ARR after adjustment of past period deficit [(10)+(11)]	29,134.72
(13).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR)	29,134.72
(14).	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above	28,750.36

**Annex-I (b)
Form-1**

Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for BOT operators operating at Major Port Trusts furnished by SWPL and modified by TAMP

Sl. No.	Description	Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)
(1).	Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts)			
(i).	Operating expenses (including depreciation)	24,021.16	23,605.00	16,819.02
(ii).	Finance and Miscellaneous expenses (FME)	239.73	279.60	21.84
	Total Expenditure 1=(i)+(ii)	24,260.89	23,884.60	16,840.86
(2).	Less Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP			
(i).	Depreciation	670.77	964.17	793.46
(ii).	Other expenditure items, if any, to be listed	217.50	8.69	18.20
	Total of Adjustments 2=(i)+(ii)	888.27	972.86	811.66
(3).	Less Adjustments:			
(i).	Actual Royalty / Revenue share paid to the port	3,415.98	3,554.06	2,154.16
(ii).	Interest on loans	239.73	279.60	21.84
(iii).	Provision for bad and doubtful debts	-	-	-
(iv).	Provision for slow moving inventory	-	-	-
(v).	Other provisions, if any	-	-	-
	Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)]	3,655.71	3,833.65	2,176.00
(4).	Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff Guidelines, 2019	2,486.07	2,586.56	1,567.75
(5).	Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1-2-3+4)	22,202.98	21,664.65	15,420.95
(6).	Average Expenses of SI. No.5 = [Y1 + Y2 + Y3] / 3	19,762.86		
(7).	Capital Employed			

	(i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March Y3 followed by the BOT operator (As per IGAAP furnished by SWPL duly certified by Chartered Accountant)	48,602.09
	(ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March Y3 or 31 December of Y3 followed by the BOT operator (As per Audited Annual Accounts)	172.75
	(iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019	
	(a). Inventory	162.85
	(b). Sundry Debtors	328.45
	(c). Cash	1,053.34
	(d). Sum of (a)+(b)+(c)	1,544.64
	(iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)-(iii)]	50,319.48
(8).	Return on Capital Employed 16% on SI. No.7(iv)	8,051.12
(9).	Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March Y3 or as applicable [(6)+ (8)]	27,813.98
(10).	Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year Y4 for example, if Y4 is 2019-20, then the applicable WPI is 4.26% and the indexed ARR for the year Y4 will be (9) x 1.0426)	28,998.85
(11).	Less: Adjustment of past period surplus for the years 2016-17 to 2018-19 over the three years. The annual impact of such adjustment works out to Rs 407.31 lakhs. (i.e. Rs. 3054.81 lakhs * 40% = Rs. 1221.92 lakhs / 3 years = Rs. 407.31 lakhs)	407.31
(12).	Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) after adjustment of past period surplus (10-11)	28,584.00
(13).	Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at SI. No.11 above	28,584.00

Annex-II

SOUTH WEST PORT LIMITED

Analysis of the Past Period Performance of SWPL for the years 2016-17 to 2018-19 furnished by SWPL and modified by TAMP

(Rs. In Lakhs)

	(i) Cargo handling expenses	7,596.23	7,976.04	8,374.84	23,947.11	12,125.64	11,408.33	6,761.29	30,295.26	
	(ii) Equipment Running Costs	1,907.31	2,038.33	2,124.87	6,070.51	1,827.34	1,740.89	1,060.99	4,629.22	
	(iii) Maintenance dredging	-	-	-	-	219.10	328.07	313.46	860.63	
	(iv) Royalty / revenue share	1,316.03	1,316.03	1,316.03	3,948.09	2,486.07	2,586.56	1,567.75	6,640.39	
	(v) Lease Rentals payable as per C. Agreement	613.30	643.20	675.36	1,931.86	603.14	605.45	656.89	1,865.47	
	(vi) Insurance	152.05	165.29	181.48	498.82	144.42	117.54	130.08	392.05	
	(vii) Other expenses	59.22	60.68	62.17	182.07				-	
	Total (i to vii)	11,644.14	12,199.57	12,734.75	36,578.46	17,405.71	16,786.85	10,490.46	44,683.02	22.16%
III	Depreciation	2,343.15	2,421.35	2,594.25	7,358.75	2,511.84	2,821.60	2,780.92	8,114.36	10.27%
IV	Overheads									
	(i) Management & Administration overheads	1,258.56	1,289.52	1,321.24	3,869.32	1,985.23	1,834.50	1,934.05	5,753.78	
	(ii) General Overheads	537.56	550.78	564.33	1,652.67	300.48	221.71	215.31	737.51	
	(iii) Preliminary expenses & Upfront Payment write-off	37.03	37.03	37.03	111.09	37.03	37.03	37.03	111.09	
	Total (i to iii)	1,833.15	1,877.33	1,922.60	5,633.08	2,322.74	2,093.24	2,186.40	6,602.38	
V	Operating Surplus / (Deficit) (I) – (II) – (III) - (IV)	1,465.62	3,344.27	2,578.34	7,388.23	7,975.01	6,191.24	1,632.77	15,799.2	
VI	Finance & Miscellaneous Income (FMI)									
	(i) Profit on sale of assets.	-	-	-	-	0.45	0.55	-	1.00	
	(ii) Other Operating Income	99.80	99.80	99.80	299.40	-	-	-	-	
	(iii). Sale of scrap					182.35	152.66	115.51	450.52	
	(iv). SEIS income					-	824.68	185.33	1,010.01	
	(v). Others (Credit of return from security deposit)	0.87	0.96	1.07	2.90	0.87	0.96	1.07	2.90	

	Total (i to v)	100.67	100.76	100.87	302.30	183.67	978.85	301.91	1,464.43	
VII	Finance & Miscellaneous Expenses (FME)									
	(i) Bank charges	9.60	10.10	10.60	30.30				-	
	Total (i to iv)	9.60	10.10	10.60	30.30	-	-	-	-	
VIII	FMI Less FME (VI) - (VII)	91.07	90.66	90.27	272.00	183.67	978.85	301.91	1,464.43	
IX	Surplus Before Interest and Tax (V)+(VIII)	1,556.69	3,434.93	2,668.61	7,660.23	8,158.68	7,170.09	1,934.68	17,263.45	
X	Capital Employed	30,181.10	32,489.75	32,395.50	95,066.35	31,626.88	29,996.53	27,180.57	88,803.99	-6.59%
XI	RoCE - Maximum permissible @ 16%	4,828.98	5,198.36	5,183.28	15,210.62	5,060.30	4,799.45	4,348.89	14,208.64	-6.59%
XII	Net Surplus / (Deficit) (IX) - (XIII)	(3,272.29)	(1,763.43)	(2,514.67)	(7,550.39)	3,098.37	2,370.65	(2,414.21)	3,054.81	
XIII	Net Surplus / (Deficit) as a % of operating income (XII/I in %)	-18.93%	-8.89%	-12.68%	-13.26%	10.25%	8.50%	-14.13%	4.06%	
XIV	Adjustment of additional past surplus	1,589.28	1,589.27	1,589.27	4,767.82					
	(a) 50% of the net additional surplus accrued in the past three years 2010-11 to 2012-13 considered for adjustment over five years period beginning from 2014-15 (February 2015) following the AG's opinion.	701.04	701.04	701.04	2,103.12				-	

	(b) .Impact of operating cost and ROCE allowed in the last tariff Order with reference to the additions to the gross block of assets relating to in-motion wagon system, single rail line along with related assets which should have been in place by 31 March 2012 but not deployed by the SWPL. Hence considered for 100% adjustment over five years beginning from 2014-15 (February 2015) and 2015-16 in the current cycle and balance to be adjusted in the subsequent tariff cycle. [In January 2015 Order this Surplus was adjusted in the years 2014-15 and 2015-16]	226.93	226.93	226.93	680.79				-	
	(c). 100% Actual surplus for the year 2013-14 set off in 2014-15 and 2015-16									
XV	Net Surplus / (Deficit) after adjustment of past Surplus	(755.04)	753.81	2.57	1.34	3,098.37	2,370.65	(2,414.21)	3,054.81	
XVI	Net surplus / (Deficit) as % Operating Income.	-4.37%	3.80%	0.01%	0.00%	10.25%	8.50%	-14.13%	4.06%	
XVII	Average net surplus/deficit in % Operating Income	0.0%				4.1%				

Annex-III (a)
Form-4

Revenue Estimation at the proposed Scale of Rates furnished by SWPL

(A). Traffic details

Sl. No.	Description	Actual Traffic			Total	Average
		Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)		
(1).	Total Actual Traffic handled (in Metric Tonnes/ TEUs)	1,17,47,065	1,06,05,899	52,48,022	2,76,00,986	92,00,329
(2).	Actual Vessel Traffic					
(i).	Number of vessels handled	193	156	107	456	152
(ii).	Total Gross Registered Tonnage (GRT)	84,57,161	81,62,571	41,74,285	2,07,94,017	69,31,339

(B). Revenue Estimation

Sl. No.	Description	Existing tariff	Reference to the schedule and Sl. No. in existing SOR	Proposed Tariff	Unit of levy	Reference to the schedule and Sl. No. in proposed SOR	Average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3	Revenue estimation at the proposed tariff (Rs. in lakhs)	% increase over the existing tariff
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = 5*8	(10) = (5-3)/3
A.	Tariff Items								
	Berth hire charges								
	at Berth 5								
	Foreign vessels	0.0138	Section C of Part - I of Vessel Related Charges	0.0159	USD/GT/Hour	Section C of Part - I of Vessel Related Charges	8,54,126	608	15%
	Coastal vessels	0.37		0.43	INR/GT/Hour		-		
	At Berth 6								
	Foreign vessels								

	Upto 30,000 GT	0.0303		0.0348	USD/GT/Hour	-	-	15%	
	30,001 GT and above	0.0358		0.0412	USD/GT/Hour	69,45,954	6,459	15%	
	Coastal vessels								
	Upto 30,000 GT	0.83		0.95	INR/GT/Hour	-	-	15%	
	30,001 GT and above	0.96		1.10	INR/GT/Hour	14,00,249	514	15%	
	Wharfage								
	Coal	38.34	Section A of Part - II of Wharfage Charges	48.00	INR/MT	Section A of Part - II of Wharfage Charges	66,51,185	3,193	24%
	Coal (coastal)	23.00		29.00			3,50,062	102	24%
	Coke	57.51		71.00	INR/MT		5,88,879	418	24%
	Limestone	12.78		16.00	INR/MT		7,56,077	121	24%
	Steel products	38.34		48.00	INR/MT		8,54,126	410	24%
	Cargo handling charges			29					
	Coal	128.69	Section B of Part - II of Cargo Related Charges	160.00	INR/MT	Section B of Part - II of Cargo Related Charges	66,51,185	10,642	24%
	Coal (coastal)	77.19		96.00	INR/MT		3,50,062	336	24%
	Coke	182.88		227.00	INR/MT		5,88,879	1,337	24%
	Limestone	169.34		210.00	INR/MT		7,56,077	1,588	24%
	Steel products	203.20		252.00	INR/MT		8,54,126	2,152	24%
	Storage income (First 5 days after free period)								
	Coal	10.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	12.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	14,00,249	168	24%
	Coke	15.00		19.00	INR/MT		1,17,776	22	24%
	Limestone	10.00		12.00	INR/MT		1,51,215	18	24%
	Any other dry bulk	15.00		19.00	INR/MT		-	-	24%
	(Rate for sixth day to tenth day)								
	Coal	25.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	31.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	7,00,125	217	24%
	Coke	40.00		50.00	INR/MT		58,888	29	24%
	Limestone	25.00		31.00	INR/MT		75,608	23	24%
	Any other dry bulk	40.00		40.00	INR/MT		-	-	
	(Rate for eleventh day to								

	Coal	2.75	Section D of Part - II of Dust Suppression Charges	3.40	INR/MT	Section D of Part - II of Dust Suppression Charges	70,01,247	238	24%
	Coke	2.75		3.40	INR/MT		5,88,879	20	24%
	Limestone	2.75		3.40	INR/MT		7,56,077	26	24%
	Total estimated Revenue at the proposed tariff							28,750	

Annex-III (b)

Form-4

Revenue Estimation at the proposed Scale of Rates furnished by SWPL and Modified by TAMP

(A). Traffic details

Sl. No.	Description	Actual Traffic			Total	Average
		Y1 (2016-17)	Y2 (2017-18)	Y3 (2018-19)		
(1).	Total Actual Traffic handled (in Metric Tonnes/ TEUs)	1,17,47,065	1,06,05,899	52,48,022	2,76,00,986	92,00,329
(2).	Actual Vessel Traffic					
(i).	Number of vessels handled	193	156	107	456	152
(ii).	Total Gross Registered Tonnage (GRT)	84,57,161	81,62,571	41,74,285	2,07,94,017	69,31,339

(B). Revenue Estimation

	at Berth 5							
	Foreign vessels	0.0138	Section C of Part - I of Vessel Related Charges	0.01550	USD/GT/Hour	Section C of Part - I of Vessel Related Charges	8,54,126	593 12.50%
	Coastal vessels	0.37		0.42	INR/GT/Hour		-	12.50%
	At Berth 6							
	Foreign vessels							
	Upto 30,000 GT	0.0303		0.0341	USD/GT/Hour		-	12.50%
	30,001 GT and above	0.0358		0.0403	USD/GT/Hour		69,45,954	6,318 12.50%
	Coastal vessels							
	Upto 30,000 GT	0.83		0.93	INR/GT/Hour		-	12.50%
	30,001 GT and above	0.96		1.08	INR/GT/Hour		14,00,249	504 12.50%
	Wharfage							
	Coal	38.34	Section A of Part - II of Wharfage Charges	48.00	INR/MT	Section A of Part - II of Wharfage Charges	66,51,185	3,193 25.20%
	Coal (coastal)	23.00		28.80			3,50,062	101 25.22%
	Coke	57.51		71.00	INR/MT		5,88,879	418 23.46%
	Limestone	12.78		16.00	INR/MT		7,56,077	121 25.20%
	Steel products	38.34		48.00	INR/MT		8,54,126	410 25.20%
	Cargo handling charges							
	Coal	128.69	Section B of Part - II of Cargo Related Charges	160.00	INR/MT	Section B of Part - II of Cargo Related Charges	66,51,185	10,642 24.33%
	Coal (coastal)	77.19		96.00	INR/MT		3,50,062	336 24.37%
	Coke	182.88		227.00	INR/MT		5,88,879	1,337 24.13%
	Limestone	169.34		210.00	INR/MT		7,56,077	1,588 24.01%
	Steel products	203.20		252.00	INR/MT		8,54,126	2,152 24.02%
				32				
	Storage income (First 5 days after free period)							
	Coal	10.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	12.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	14,00,249	168 20.00%
	Coke	15.00		19.00	INR/MT		1,17,776	22 26.67%
	Limestone	10.00		12.00	INR/MT		1,51,215	18 20.00%
	Any other dry bulk	15.00		19.00	INR/MT		-	26.67%
	(Rate for sixth day to tenth day)							
	Coal	25.00	Section C of Part - II of	31.00	INR/MT	Section C of Part - II of	7,00,125	217 24.00%

			Ground Rent Charges			Ground Rent Charges			
	Coke	40.00		50.00	INR/MT		58,888	29	25.00%
	Limestone	25.00		31.00	INR/MT		75,608	23	24.00%
	Any other dry bulk	40.00		40.00	INR/MT		-	-	0.00%
	(Rate for eleventh day to twentieth day)								
	Coal	50.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	62.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	-	-	24.00%
	Coke	75.00		93.00	INR/MT		-	-	24.00%
	Limestone	50.00		62.00	INR/MT		-	-	24.00%
	Any other dry bulk	75.00		93.00	INR/MT		-	-	24.00%
	(Rate for twenty first day onwards)								
	Coal	100.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	124.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	-	-	24.00%
	Coke	150.00		186.00	INR/MT		-	-	24.00%
	Limestone	100.00		124.00	INR/MT		-	-	24.00%
	Any other dry bulk	150.00		186.00	INR/MT		-	-	24.00%
	(First 5 days after free period)								
	Iron pellets	10.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	12.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	-	-	20.00%
	Metal products, Steel Coils, Slabs and other general bulk cargo	5.00		6.00	INR/MT		4,27,063	26	20.00%
	(Rate for sixth day to tenth day)								
	Iron pellets	25.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	31.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	-	-	24.00%
	Metal products, Steel Coils, Slabs and other general bulk cargo	10.00		12.00	INR/MT		2,56,238	31	20.00%
	(Rate for eleventh day to twentieth day)								
	Iron pellets	50.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	62.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	-	-	24.00%
	Metal products, Steel Coils, Slabs and other general bulk cargo	25.00		31.00	INR/MT		1,70,825	53	24.00%

	bulk cargo							
	(Rate for twenty first day onwards)							
	Iron pellets	100.00	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	124.00	INR/MT	Section C of Part - II of Ground Rent Charges	-	24.00%
	Metal products, Steel Coils, Slabs and other general bulk cargo	50.00		62.00	INR/MT		-	24.00%
	Dust Suppression							
	Coal	2.75	Section D of Part - II of Dust Suppression Charges	3.40	INR/MT	Section D of Part - II of Dust Suppression Charges	70,01,247	23.64%
	Coke	2.75		3.40	INR/MT		5,88,879	23.64%
	Limestone	2.75		3.40	INR/MT		7,56,077	23.64%
	Total estimated Revenue at the proposed tariff						28,584	

Annex-IV**SOUTH WEST PORT LIMITED****SCALE OF RATES****1. DEFINITIONS - GENERAL**

In this Scale of Rates unless the context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i). **"Per Day"** means per calendar day unless otherwise stated.
- (ii). **"SWPL"** means South West Port Limited a company incorporated in India, its successors and assigns.
- (iii). **"Port"** means the Mormugao Port Trust (MOP) whereas "Terminal" means South West Port Limited (SWPL), now or hereafter operated by South West Port Limited.
- (iv). **"Coastal Vessel"** means any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the competent authority.
- (v). **"Coastal Cargo"** means any cargo, which the vessel discharges at one Indian port after shipment from another Indian port or vice versa irrespective of its actual origin or destination.
- (vi). **"Foreign Cargo"** means any cargo other than coastal cargo.
- (vii). **"Foreign-going Vessel"** means any vessel other than a coastal vessel.
- (viii). **"Tonne"** or **"MT"** means one Metric Tonne of 1,000 kilograms or one cubic metre.

2. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

- (i). The Status of the vessel, as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, is the relevant factor to decide whether vessel is 'coastal' or 'foreign-going' category

for the purpose of levying vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.

- (ii). System of classification of vessel for levy of Vessel Related Charges (VRC):
 - (a) A foreign going vessel of Indian flag having a General Trading Licence can convert to coastal run on the basis of a Customs Conversion Order. Such vessel that converts into coastal run based on the Customs Conversion Order at her first port of call in Indian Port, no further custom conversion is required, so long as it moves on the Indian Coast.
 - (b) A foreign going vessel of foreign flag can convert to coastal run on the basis of a License for Specified Period or Voyage issued by the Director General of Shipping and Custom Conversion order.
- (iii). Criteria for levy of vessel related charges (VRC) at Concessional Coastal rate and foreign rate:
 - (a) In cases of such conversion, coastal rates shall be chargeable by the load port from the time the vessel starts loading coastal goods.
 - (b) In cases of such conversion coastal rates shall be chargeable till the vessel completes discharging operations at the last call of Indian Port; immediately thereafter, foreign going rates shall be chargeable by the discharge ports.
 - (c) For dedicated Indian coastal vessels having a Coastal licence from the Director General of Shipping, no other document will be required to be entitled to coastal rates.
- (iv). Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate:
 - (a) Foreign going Indian vessel having General Trading License issued for ‘worldwide and coastal’ operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:-
 - (i). Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - (ii). Not Converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

*The Central Board of Excise & Customs - Circular No 15/2002-Cus dated 25th February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian Port to another Indian Port in India, in Indian flag foreign going vessels without any Custom Conversion.

 - (b). In case of Foreign flag vessels converted to coastal run on the basis of a License for Specified Period or Voyage issued by the Director General of Shipping and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined from any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo / container.
 - (v). Wherever rates of vessel related charges have been denominated in US dollar terms the charges shall be recovered in Indian Rupees after conversion of US currency to its equivalent Indian Rupees at the market-buying rate notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its Associates or any other Public Sector Banks as may be specified from time to time. The date of entry of the vessel into the port shall be reckoned with as the day for such conversion.

- (vi). A regular review of exchange rate shall be made once in thirty days from the date of arrival of the vessels in cases of vessels staying in the port for more than thirty days. In such cases, the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of the review.
- (vii). (a). The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal, POL including crude oil, iron ore and iron ore pellets should not exceed 60% of the normal cargo / container related charges.
- (b). In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from / to quay to / from storage yard including wharfage.
- (c). Cargo from a foreign port, which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transhipment to Indian Port 'B' will be, levied the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from / to Indian ports carried by vessel permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (d). The charges for coastal cargo / vessels shall be denominated and collected in "Indian Rupee".
- (viii). For the purpose of calculating the dues the unit by weight shall be 1 tonne or 1000 kilograms, the unit by volume measurement shall be 1 cubic metre and the unit by capacity measurement for liquids in bulk shall be 1000 litres.
- (ix). In calculating the gross weight or measurement by volume or capacity of any individual item, fractions upto 0.5 shall be taken as 0.5 unit and fractions of 0.5 and above shall be treated as one unit, except where otherwise specified.
- (x). Interest on delayed payments / refunds:
- (a). The user shall pay penal interest on delayed payments under this Scale of Rates. Likewise, the SWPL shall pay penal interest on delayed refunds.
- (b). The rate of penal interest will be 15.00%. The penal interest rate will apply to both the SWPL and the port users equally.
- (c). The delay in payments by the users will be counted only 10 days after the date of raising the bills by the SWPL. This provision shall, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services as stipulated in the Major Port Trusts Act and / or where payment of charges in advance is prescribed in this Scale of Rates.
- (d). The delay in refunds will be counted only 20 days after the date of completion of services or on production of all the documents required from the users, whichever is later.
- (xi). All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of each bill.
- (xii). (a). The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels, likewise, rebates and discounts are floor levels. The SWPL may, if it so desires, charge lower rates and / or allow higher rebates and discounts.
- (b). The SWPL may also, if they so desire, rationalise the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalisation gives relief to the user in rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates do not exceed the ceiling level.

- (c). The SWPL should notify the public such lower rates and / or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and / or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- (xiii). Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the SWPL.
- (xiv). Coastal goods transported between an Indian port on east coast and another Indian port on west coast or vice versa, by a vessel through the territorial waters of Sri Lanka, whether or not calling any port in Sri Lanka in between and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (xv). Coastal goods transported between an Indian port on east coast and a river port in India or vice versa, by a vessel through a route passing through the Bangladeshi waters and without change of vessel in terms Notification No.38/2018-Customs (N.T.) dated 11 May 2018 of Central Board of Indirect Taxes and Customs shall be eligible for concession in vessel related charges and cargo related charges.
- (xvi). The SOR is subject to automatic annual indexation to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Authority occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. The next annual indexation will be from 1 May, 2020. The indexed SOR by the SWPL to be intimated by the SWPL to the MOPT, concerned users and to the Authority.

PART I - VESSEL RELATED CHARGES

SECTION – A – PORT DUES and SECTION – B – PILOTAGE FEES

These services will be rendered to the vessels entering the SWPL's berth numbers 5A and 6A by the Mormugao Port Trust as per their approved Scale of Rates. The charges shall be payable directly to the Mormugao Port Trust by masters / owners / agents of the vessel.

SECTION - C - BERTH HIRE CHARGES

Berth Hire Charges at Berth numbers 5A and 6A shall be payable to SWPL by masters / owners / agents of the vessel at the following rates.

BERTH NO.5A
(Maximum LOA of Vessel 190 mtrs. in conjunction with another vessel of
LOA 225 mtrs. at Berth No.6A)

Sl. No.	Class of Vessel	Rate per GRT per hour or part thereof	
		Foreign going Vessel (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)
1.	All Vessels	0.0155	0.42

BERTH NO.6A
(Under Mechanised Operation system)

Sl. No.	Class of Vessel	Rate per GRT per hour or part thereof	
		Foreign going Vessel (in US \$)	Coastal Vessels (in ₹)
1.	Upto 30,000 GRT	0.0341	0.93
2.	30,001 GRT and above	0.0403	1.08

Notes:

- (1). Berth Hire charges includes charges for services rendered and facilities provided at the Berth, such as occupation of berth, overtime at berth, removal of rubbish collected on board by the vessel and delivered on the wharf, cleaning of Berths, fire watch, etc.
- (2). The above charges are leviable against Masters, Owners or Agents of vessels and other floating craft approaching or lying at or alongside berths per GRT per hour or part thereof.
- (3). The Berth hire charges leviable per vessel is subject to a minimum of US\$ 662.00 in case of foreign going vessel and ₹17,717/- in case of coastal vessel.
- (4). The period of berth hire shall be calculated from the time the vessel occupies the berth.
- (5). No berth hire charges shall be payable for the period when loading / unloading operations cannot be carried out due to non-availability of the shore cranes / mechanical handling system of SWPL, due to breakdown or any other reason attributable to SWPL.
- (6).
 - (i). Berth hire shall stop 4 hours after the time of vessel signaling its readiness to sail.
 - (ii). The time limit of 4 hours prescribed for the cessation of berth hire shall exclude the ship's waiting time for want of favorable tide conditions, inclement weather, and due to lack of night navigation.
 - (iii). The master / agent of the vessel shall signal readiness to sail only in accordance with favorable tidal and weather conditions.
 - (iv). The Penal Berth hire shall be equaled to one-day's (24 hours) berth hire charge for a false signal.

“False signal” would be when the vessel signals readiness and asks for a pilot in anticipation even when she is not ready for un-berthing due to engine not being ready or cargo operation not completed or such other reasons attributable to the vessels. This excludes the signaling readiness when a vessel is not able to sail due to unfavorable tide, lack of night navigation or adverse weather conditions.”
- (7). The de-ballasting time allowed at berth numbers 5A and 6A shall be 3 hours and beyond that penal berth hire charges shall be levied at five times the normal berth hire charges, the incidence being reduced to per hour or part thereof, that may be applicable to the vessel. This will be in addition to the normal berth hire charges applicable for the entire duration of the vessel's stay at the berth.
- (8). Vessels banked on offside of another vessel at these berths, berth hire charges shall be 50% of normal charges payable by such vessels.
- (9). The provisions of the License Agreement shall govern priority Berthing and charges on it, if any. Whenever the priority berthing is granted to a vessel, a fee equivalent to Berth Hire charges for a single day (24 hours) or @ 75% of the Berth Hire charges calculated for the total period of actual stay at the Berth, whichever is higher, shall be levied.
- (10).
 - (i). For providing ousting priority to a vessel, a fee equivalent to berth hire charges for a single day (24 hours) or @100% of the berth hire charges calculated for the total period of actual stay of the vessels at berth, whichever is higher, shall be levied.
 - (ii). In addition, shifting out / in charges of the vessels shall be levied on the vessels, which are provided ousting priority.
 - (iii). Ousting priority at berth no.6A will be accorded only when a discharge / load rate of 25,000 MT of cargo per weather working day cannot be achieved due to restrictions placed by the vessels.

PART - II CARGO RELATED CHARGES
SECTION – A
WHARFAGE CHARGES AT BERTH NOS. 5A AND 6A

Wharfage on the cargo handled at berths numbers 5A and 6A shall be payable directly to SWPL, at the rates specified below, by importer or exporter of cargo, on the manifested quantity of cargo, which is declared in the Bill of entry filed with the Customs:

Sl. No.	Particulars of Commodity	Unit	Rate for Import / Export (in ₹)	
			Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Coal (except thermal coal)	MT	48.00	28.80
2.	Thermal coal	MT	48.00	48.00
3.	Metallurgical Coke / Coke / Charcoal	MT	71.00	42.60
4.	Limestone	MT	16.00	9.60
5.	Iron Ore Pellets	MT	48.00	48.00
6.	Metal products, Steel Coils, Slabs	MT	48.00	33.60
7.	Any other bulk cargo not specified above	MT	48.00	33.60

Before classifying any cargo under “unspecified” category under the wharfage schedule, the relevant custom classification should be referred to find out whether the cargo could be classified under any of the specified categories mentioned in the wharfage schedule.

SECTION – B
CARGO HANDLING CHARGES

Cargo Handling Charges at Berth numbers 5A and 6A shall be payable on the manifested cargo directly to SWPL by importer or exporter of cargo at the rates specified below:

At Berth No.5A

Sl. No.	Particulars of Commodity	Unit	Rate for Import / Export (in ₹)	
			Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Iron Ore Pellets	MT	252.00	252.00
2.	Metal products, Steel Coils, Slabs	MT	252.00	151.20
3.	Any other bulk cargo not specified above	MT	241.00	144.00

At Berth No.6A

Sl. No.	Particulars of Commodity	Unit	Rate for Import / Export (in ₹)	
			Foreign Cargo	Coastal Cargo
1.	Coal (except thermal coal)	MT	160.00	96.00
2.	Thermal coal	MT	160.00	160.00
3.	Metallurgical Coke / Coke (all types) / Charcoal	MT	227.00	136.20
4.	Limestone	MT	210.00	126.00
5.	Iron Ore Pellets	MT	252.00	252.00
6.	Metal products, Steel Coils, Slabs	MT	252.00	151.00

7.	Any other bulk cargo not specified above	MT	238.00	143.00
----	--	----	--------	--------

Notes:

- (1). At the berth number 5A, Cargo Handling Charges shall cover the following services:
 - Unloading of cargo from ship to the berth or vice versa,
 - Movement of cargo from the berth to SWPL stackyard or vice versa,
 - Movement within the SWPL stackyard,
 - Unloading from railway wagons or vice versa.
- (2). At the berth number 6A Cargo Handling Charges shall cover the following services:
 - Unloading of cargo from ship to the berth or vice versa,
 - Movement of cargo from the berth to SWPL stackyard or vice versa,
 - Movement within the SWPL stackyard,
 - Loading on railway wagons for rail delivery or vice versa.
- (3). Covering of Wagons by tarpaulin / plastic cover is not included in above handling charges prescribed in the schedule.
- (4). The dunnaging and lashing (inclusive suitable labour & material) will have to be arranged by the users at their costs to the satisfaction of the Master of the vessel.
- (5). 50% of the Cargo Handling Charges shall be payable before the cargo is received for handling. Balance 50% of the Cargo Handling charges shall be payable before the clearance / shipment of the cargo.

SECTION – C**GROUND RENT / STORAGE CHARGES**

The storage charges for cargo stored in the stackyard of SWPL shall be as follows:

I. Ground rent / storage charge for import / inward cargo

(in ₹ per MT per day for the balance cargo in SWPL)

Sl. No.	Particulars of Commodity	Rate for first Five days remaining after the free period	Rate for Sixth day to Tenth day	Rate for Eleventh day to Twentieth day	Rate for Twenty-first day onwards
1.	Coal (all types)	12.00	31.00	62.00	124.00
2.	Metallurgical Coke / Coke (all types) / Charcoal	19.00	50.00	93.00	186.00
3.	Limestone	12.00	31.00	62.00	124.00
4.	Any Other dry bulk cargo not specified above	19.00	40.00	93.00	186.00

Notes:

- (1). *SEVEN Free Days* shall be allowed, after complete discharge of vessel's cargo or when the last package is discharged. For the purpose of calculation of free period, Sundays, Customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded.
- (2). *Ground rent / storage charges* shall be payable for all days including Sundays and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

- (3). After 21 days beyond Free Days, the balance cargo shall be liable to be shifted to other place out of SWPL area at the sole cost and consequences to the importer / exporter.
- (4). For levy of ground rent / storage ‘Day’ shall be reckoned as from 7.00 a.m. to 7.00 a.m. of the following day.

II. Ground rent / Storage charges for Export / Outward cargo

(in ₹ per MT per day for the balance cargo in SWPL)

Sl. No.	Particulars of Commodity	Rate for first Five days remaining after the Free Period	Rate for Sixth day to Tenth day	Rate for Eleventh day to Twentieth day	Rate for Twenty-first day onwards
1.	Iron Pellets	12.00	31.00	62.00	124.00
2.	Metal products, Steel Coils, Slabs and other general bulk cargo	6.00	12.00	31.00	62.00

Notes:

- (1). In case of export cargo, Seven Free Days shall be allowed from the day the first lot of cargo / consignment has been received. For the purpose of calculation of free period Sundays, Customs notified holidays and Terminal's non-working days will be excluded.
- (2). After the prescribed free days, ground rent / storage charges shall be payable for all days including Sundays and Customs notified holidays as stated above.
- (3). After 21st day beyond free days, the balance cargo shall be liable to be shifted to other place out of SWPL area at the sole cost and consequences to the exporter.
- (4). For levy of ground rent / storage ‘Day’ shall be reckoned as from 7.00 a.m. to 7.00 a.m. of the following day.
- (5). If the entire cargo accumulated is not within the free period and the balance cargo is earmarked / linked to the next ship, further free period will be allowed from the date of production of documentation in support of this claim. Otherwise, penal ground rent at the appropriate rate applicable as per the rates prescribed in the above schedule shall be payable.

General Note to Section C:

- (1). Storage charges / ground rent on cargo shall not accrue for the period when the SWPL is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to SWPL.

SECTION – D

DUST SUPPRESSION CHARGES

The Dust Suppression Charges for water sprayed for suppression of dust for effective pollution control shall be levied on manifested quantity on Coal, Coke and Limestone at the following rates:

For Coal, Limestone and Coke: ₹3.40 per MT

This shall be levied from the stage of unloading from the vessel till the cargo is loaded onto railway wagons including storage at SWPL stackyard.

Part- III

OTHER SERVICES

1. VISITOR ENTRY PASS

	Yearly	Monthly	Daily
(a). Per Application	₹255.60	₹63.90	₹25.56
(b). Per Replacement	₹63.90	₹63.90	₹25.56

2. VEHICLE ENTRY PASS

Per Entry	₹95.85
-----------	--------

Note: The vehicle entry fee will not be levied on vehicles entering / leaving the SWPL berths for delivery / dispatch of cargo.

3. PHOTOGRAPHY

(a). Film Shooting and Photography	₹10863.00 per day
(b). Taking Photographs of Goods handled	₹639.00 per day
(c). Taking Photographs of Crews and Others	₹319.50 per day
(d). Videography (related to operational activities)	₹3195.00 per day

4. CRANE HIRE CHARGES

The hire charges for the SWPL's cranes installed at berth nos.5A and 6A shall be payable directly to SWPL for use for the purposes other than for cargo handling as per following rates:

(a). For 110/42 MT capacity mobile harbour cranes	₹31950.00 per hour
(b). For others cranes	₹19170.00 per hour